दैनिक जागरण

मनोवल आंतरिक दीपक है, जो अभाव में भी रास्ता दिखाता है

कोचिंग पर निर्भरता

शिक्षा मंत्रालय नीट, जेईई और ऐसी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग पर निर्भरता घटाने के लिए जो पहल करने जा रहा है, उसमें सफलता तब मिलेगी, जब स्कूली स्तर पर और विशेष रूप से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में पठन-पाठन का स्तर उन्नत होगा। यह निजी के साथ सरकारी स्कूलों में भी उन्नत होना चाहिए। और भी अच्छा होगा कि आठवीं के बाद ही जब छात्र विज्ञान एवं गणित विषयों का चयन करते हैं, तभी से उनके पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों का स्तर ऐसा किया जाए, जिससे वे आगे चलकर नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में कोचिंग का सहारा लेने के लिए विवश न हों। एक समय था, जब इंटरमीडिएट के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां बदलीं और फिर कोचिंग के चलन ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया। इसका कारण हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के पठन-पाठन के स्तर में कमी के साथ यह भी रहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर कठिन होता गया। समझना कठिन है कि जिस स्तर के प्रश्न उक्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी स्तर के प्रश्न 11वीं और 12वीं परीक्षाओं में क्यों नहीं शामिल किए जा सकते?

आखिर जब पाठ्यक्रम एक है तो स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर अलग-अलग क्यों? निःसंदेह यह अंतर इसलिए आया, क्योंकि शिक्षा बोर्डों का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सफल बनाना होता है और वह भी अच्छे नंबरों से। यह किसी से छिपा नहीं कि आजकल कुछ शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत अंक लाना बहुत आम हो गया है। शिक्षा बोर्डों और साथ ही विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को केवल स्कूली परीक्षाओं में पास होने लायक ही नहीं, बल्कि मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने यह समझा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को तैयार करने में एनसीईआरटी के साथ दूसरे शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम को भी आधार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी, जब केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में साम्य होगा। शिक्षा मंत्रालय को यह भी समझना होगा कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को ही कोचिंग संस्कृति से बचाने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता अन्य परीक्षाएं देने वाले छात्रों के संदर्भ में भी है। इसी के साथ उसे ट्यूशन संस्कृति पर भी विराम लगाने पर विचार करना चाहिए।

सचेत रहने की जरूरत

नेपाल में बारिश का दंश बिहार झेल रहा। पिछले कुछ दिनों से राज्य में बाढ़ से सामान्य होती स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। इस बार आफत नेपाल की ओर से है। गंडक और कोसी में उफान ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। जब तक नेपाल में बारिश होती रहेगी, बिहार में खतरा बरकरार रहेगा। बागमती भी कुछ प्रखंडों में जन जीवन को घेर रही। पिछले दो दिनों से गंडक और कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है। इसका असर विशेषकर इन नदियों के किनारे बसी आबादी पर पड़ा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। फसलें डूब गई हैं। सड़क संपर्क फिर से बाधित होने लगा है। पिछली बाढ़ में ऊंचे स्थानों और बांधों पर शरण लिए लोग दशहरा में घर लौटने का सपना संजोए थे, अब फिर से स्थिति विकट होती दिख रही है। हालांकि सरकार की ओर से बचाव और राहत कार्य में तेजी लाई गई है, लेकिन हर साल की इस त्रासदी पर भी उसे दमखम के साथ आगे बढ़ना होगा। इस मामले में केंद्र से सहयोग की जरूरत है। इसकी कार्ययोजना पर दृढ़ता से काम करना होगा। बाढ़ से बचाव के लिए कोसी के दोनों किनारों पर मजबूत बांध के रूप में सड़क के निर्माण की योजना बनी है, लेकिन जब तक मूल कारणों के निदान पर काम नहीं होगा, खतरा बना रहेगा। फिलहाल की स्थिति में सचेत रहने की जरूरत है, ताकि नुकसान कम से कम हो।

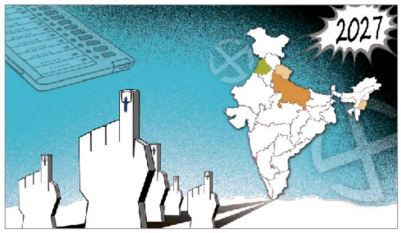
> नेपाल द्वारा हर वर्ष थोपी जा रही बाढ़ पर कार्ययोजना बनाकर दृढ़ता से आगे बढ़ने की जरूरत है

यूपी लिखेगा राष्ट्रीय राजनीति की पटकथा



डा. एके वर्मा

आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में से सबसे अधिक राजनीतिक सरगर्मी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है



अवधेश राजपूत

उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं। इन सभी राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए यह तीसरे कार्यकाल का दरवाजा खोल सकता है और लोकसभा चुनाव 2029 की पटकथा लिख सकता है। 2024 में भाजपा उत्तर प्रदेश में 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें (37+6) जीतीं और भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया। इसके बावजूद प्रदेश में भाजपा/एनडीए का मत प्रतिशत (44.01) सपा-कांग्रेस गठबंधन (43.52) से ज्यादा था। यादें रहे कि 2012 में सपा ने मात्र 29 प्रतिशत और 2007 में बसपा ने 30 प्रतिशत वोट पर सरकार बनाई थी, इसलिए भाजपा/एनडीए का वर्तमान 40 प्रतिशत जनाधार त्रिकोणीय चुनावी संघर्ष में विजय की संभावनाएं संजोए है, लेकिन भाजपा के विजय की राह आसान नहीं। योगी ने भले ही 'कानून-व्यवस्था' और 'लोक कल्याण एवं विकास' पर जनता का विश्वास हासिल किया है, लेकिन चुनावों में मतदाता 'विपक्षी विभर्श' के भ्रमजाल में फंस कर कहीं और भी जा सकता है। विगत लोकसभा चुनावों में यही हुआ था। अखिलेश-राहुल ने भाजपा के '400 पार' पर यह 'नैरेटिव' गढ़ा कि इतनी सीटें पाकर भाजपा 'बाबा साहब का संविधान बदल देगी' और 'आरक्षण खत्म कर देगी।' इससे भ्रमित होकर दलित और ओबीसी मतदाता भाजपा से खिसक गए।

जो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जनवरी-मार्च 2024 में 60 प्रतिशत जनता की पसंद थे, वे अप्रैल-मई में नीचे गिर कर 40 प्रतिशत पर आ गए थे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, बिहार, गुजरात जैसे परिणाम आते। विजय हेतु सत्तारूढ़ दल द्वारा सुशासन के साथ 'एक प्रभावी केंद्रीय विभर्श' भी गढ़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी को विपक्ष से ही नहीं, भाजपा की आंतरिक खींचतान से भी चुनौती है। मुख्यमंत्री पद के कई अभिलाषी हैं। केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप और संघ की पृष्ठभूमि न होना भी एक मुद्दा है, पर योगी की कर्मठता, मोदी का वरदहस्त और जनता के आशीर्वाद की त्रिवेणी से वह निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। कुछ समस्याएं तो हमेशा रहेंगी। इसलिए और भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है। आज 'जेन-जी' द्वारा परीक्षा और रोजगार पर आक्रोश है, लेकिन जिस देश में सूडान, बेल्जियम, यूएई आदि के बराबर जनसंख्या केवल एक वर्ष में ही बढ़ जाती हो, वहां किसी पार्टी के पास रोजगार देने का कोई बेहतर ब्लूप्रिंट है क्या? 'जेन-जी' के हाथ में मोबाइल है। क्या उसे पता नहीं कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 1989 में क्यों रिजेक्ट किया और क्यों आज 36-37 वर्ष बाद भी वह अपनी जमीन नहीं तलाश सकी? क्या उसे पता नहीं कि सपा के शासन में भय, जातिवाद और मुस्लिम-तुष्टीकरण का क्या आलम था? क्या उसे सपा-कांग्रेस शासन में दंगों का इतिहास नहीं पता? क्या उसे ज्ञात नहीं कि पिछले 10 वर्षों में सपा-कांग्रेस ने भाजपा और मोदी की अपमानित करने के अलावा कोई रचनात्मक, सकारात्मक बात जनता के सामने नहीं रखी कि वे भाजपा से बेहतर और करेंगे क्या?

प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा जातीय समीकरणों की संकीर्णता, जमीनी राजनीति की कमजोरी, अल्पसंख्यकवाद, परिवारवाद, शासन और विकास के बेहतर माडल का अभाव तथा पिछले कार्यकाल की छवि से जूझ रही है। इसका समाधान ढूंढ़ने के बजाय सपा ने नकारात्मक और प्रतिगामी राजनीति का चयन किया। पहले मुस्लिम-यादव और फिर 'पीडीए' (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का दांव चला, लेकिन अभी समावेशी राजनीति के मोदी-मंत्र 'सबका-साथ, सबका-विकास' से वह पीछे है।

बसपा सुप्रीमो मायावती कभी प्रदेश राजनीति में सशक्त किरदार थीं। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग द्वारा 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, पर वे उसे बरकरार न रख सकीं। वे ब्राह्मणों और दलितों की आकांक्षाओं में समन्वय न कर सकीं। शायद उन्हें पता नहीं कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने की कला नहीं, वरन उसे बनाए रखने की विधि भी है। 2022 के विधानसभा में बसपा को केवल एक सीट और 2024 लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका 10 प्रतिशत जनाधार बचा हुआ है। वहीं दलित राजनीति के उभरते नेता चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट जीत बसपा को चौंका दिया। मायावती विचारधारा, संगठन और नेतृत्व को लेकर अपना जनाधार खोती जा रही हैं। 2014 से भाजपा ने प्रदेश में अधिकांश सुरक्षित सीटें जीत कर दलितों में अपनी पैठ बनाई, उन्हें संगठन और सत्ता में समानुपातिक प्रतिनिधित्व देकर उनका विश्वास हासिल किया। अतः दलितों के पास कोई ऐसा ठौर कारण नहीं कि वे भाजपा छोड़ सपा या कांग्रेस जैसे दलों के साथ जाएं।

मुस्लिम मतों पर सपा अपना हमेशा अपना एकाधिकार मानती रही है, लेकिन अबकी कांग्रेस और मायावती के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है, जिसकी मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों पर नजर है। कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग तथा ओवैसी के प्रति झुकाव ने अखिलेश के 'पीडीए' पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। अब तो कुछ मुस्लिम भी योगी के कानून-व्यवस्था, विकास और लाभार्थी योजनाओं की लेकर समर्थन में हैं। छोटी-छोटी पार्टियां अपनी अस्मिता और 'एनडीए' में सत्ता-सहभागिता हेतु अपने ढंग से प्रयास कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सीटें देने में सपा को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस नेतृत्व की स्वीकार्यता है, पर यदि प्रदेश में सपा को अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो उसे कांग्रेस को सीटें देने में सतर्क रहना होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस जितना सशक्त होगी, सपा उतना ही कमजोर होगी।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

अमेरिकी बाजार का विकल्प खोजे भारत



हिमांशु गायसवाल

भारत को अमेरिका के किसी भी तरह के दबाव में आए बिना अपने व्यापार हित एवं नीति तय करनी चाहिए



भारत पर दबाव बढ़ाते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। फाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अनुमोदित होने के बाद लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एक्ट-2026 ने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के लागू होने से भारत के आर्थिक हितों पर गंभीर असर पड़ सकता है। सबसे चिंता की बात इस एक्ट का वह प्रविधान है, जिसके तहत अमेरिका उन शीर्ष पांच देशों पर सौ प्रतिशत तक का टैरिफ बढ़ा सकता है, जो देश कानून लागू होने के बाद भी रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करते रहते हैं। हाल के समय में कच्चे तेल के आयात का बिल कम करने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रणनीतिक फायदा उठाने के लिए भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना शुरू किया है, जिससे रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष से पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी सिर्फ दो प्रतिशत थी, पर अब यह 50 प्रतिशत हो गई है। रूसी कच्चे तेल का आयात इस साल जनवरी में 4.54 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर मई में 8.96 एमएमटी हो गया। हालांकि आपूर्ति सुरक्षित करने में विविधता लाने की यह रणनीति कारगर रही है, पर इसके अपने कूटनीतिक परिणाम भी हैं, खासकर अमेरिका के साथ संतुलन बनाने में, जो इस आयात का पक्षधर नहीं है।

अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों पर जबरन श्रम से जुड़े टैरिफ पहले ही लगा रखा है, जिससे भारत पर अमेरिका के मौजूदा टैरिफ 10 प्रतिशत और हो गए हैं। अब अगर रूस सैंक्शन एक्ट लागू हो जाता है और भारत रूस के साथ कच्चे तेल और गैस के आयात की जारी रखता है तो इस पर अतिरिक्त 110 प्रतिशत टैरिफ लग जाएगा। इससे यह सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक बन जाएगा। चीन पर भी अमेरिकी टैरिफ 112.5 प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि वह भी रूसी तेल का बड़ा आयातक है। अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य में से एक है। अत्यधिक टैरिफ के कारण भारत अमेरिका में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान होगा। भारत के समक्ष एक आर्थिक दुविधा यह है कि वह या तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से आयात जारी रखे और अमेरिकी टैरिफ का सामना करे या फिर अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में पहुंच बनाए रखे, लेकिन ऊर्जा के मोर्चे पर अनिश्चितता का सामना करे।

2025 में भारत ने अपने कुल निर्यात का 20 प्रतिशत अकेले अमेरिका को किया था, जिसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रानिक उपकरण, फार्मा, हीरे और आभूषण, समुद्री उत्पाद आदि शामिल थे, जो कुल अमेरिकी निर्यात का 45 प्रतिशत थे। टैरिफ लगने की दशा में इन वस्तुओं का निर्यात प्रमुख रूप से प्रभावित होगा। निर्यात कम होने से भारत में उत्पादन कम होगा, जिससे पूंजी एवं श्रम पर मिलने वाला मानदेय कम होगा तथा बहुत से छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ खाड़ी देशों में चल रही अशांति से कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने से उसके आयात मूल्य बढ़ गए हैं। ऐसे में यदि रूस से तेल एवं गैस का आयात कम किया गया तो भारत को वैश्विक बाजार में अधिक मूल्य चुकाने पड़ेंगे, जिसका सीधा प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार तथा व्यापार घाटे पर पड़ेगा। यह महंगाई भी बढ़ने का एक कारण हो सकता है। लगता है अमेरिका रशिया सैंक्शन एक्ट को वर्तमान में चल रही व्यापार-समझौता वार्ता में भारत पर दबाव बनाने के रूप में उपयोग करना चाहता है, ताकि उसे भारत का घरेलू बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। भारत को किसी भी दबाव में आए बिना अपने व्यापार हित एवं नीति तय करनी चाहिए। फरवरी में हुए द्विपक्षीय समझौते में भारत पर अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने पर सहमति बनी थी। इस एक्ट द्वारा अमेरिका अपने ही करार से मुकर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत कई उपाय कर सकता है।

भारत को अमेरिका से आगे देखना चाहिए और वैकल्पिक बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ानी चाहिए। भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजार देखने चाहिए, जहां भारत के वस्तुओं की मांग हो। इस क्रम में मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छी नीति है। हालांकि निर्यात में विविधता लाना कोई रामबाण इलाज नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि दूसरे बाजार भारत के अतिरिक्त आयात को कितना अपना सकते हैं। पर्याप्त बाहरी मांग न होने पर विविधता सीमित रह सकती है। भारत को आयात कर दरों में सुधार करते हुए उन्हें कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। सस्ते आयातित माल से उपभोक्ता मांग एवं व्यापार प्रतिस्पर्धा दोनों में ही सुधार हो सकता है। इसके साथ-साथ लगातार घरेलू सुधार भी होने चाहिए, जैसे व्यापार को आसान बनाना, नान-टैरिफ बाधाओं को हटाना, लाजिस्टिक्स और मानकों में सुधार करना और सामान की क्वालिटी को बेहतर बनाना। ऐसी रणनीति न केवल भविष्य के भू-राजनीतिक झटकों का सामना करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि लंबे समय में उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूत करेगी।

(लेखक नई दिल्ली स्थित सेंटर फार सोशल एंड इकोनमिक प्रोग्रेस में सलाहकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

त्याग की साधना

मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति संचय की है। वह वस्तुएं संचित करता है, संबंधों पर अधिकार स्थापित करना चाहता है, उपलब्धियों को स्मृति में सुरक्षित रखता है और अपेक्षाओं को भविष्य की पोटली में बांध लेता है। शनैश्चरैः यही संचय उसके अंतर्मन पर ऐसा भार बन जाता है कि जीवन की सहजता कहीं पीछे छूट जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह जीवन भर पाने की साधना करता रहता है, जबकि शांति का द्वार सदैव छोड़ देने की प्रवृत्ति से खुलता है। संग्रह को हमने सफलता का पर्याय बना लिया है और त्याग को अभाव का, जबकि भारतीय चिंतन-परंपरा में त्याग रिक्तता नहीं, अपितु भीतर के अनावश्यक को विसर्जित कर स्वयं को अधिक पूर्ण करने की प्रक्रिया है। त्याग का अर्थ छोड़कर भाग जाना कदापि नहीं है। वह तो आसक्ति के क्षरण की प्रक्रिया है। वस्तु पास रहे, किंतु मन उसका बंधक न बने। सफलता मिले, किंतु अहंकार न फूले। सम्मान प्राप्त हो, किंतु उसके खोने का भय भीतर घर न करे। वास्तविक जीवन में त्याग के अनेक अवसर आते हैं। किसी विवाद में अपने पक्ष को अंतिम सत्य मानने का आग्रह छोड़ देना, किसी की भूल को बार-बार स्मरण न करना, संबंधों में स्वामित्व के स्थान पर सम्मान को चुनना और अपनी ही बनाई हुई धारणाओं से मुक्त हो जाना, ये सभी त्याग की गहन अवस्थाएं हैं।

हम प्रायः समझते हैं कि पाने से जीवन समृद्ध होता है, जबकि कई बार छोड़ने से जीवन अर्थवान होता है। अनावश्यक अपेक्षाओं को छोड़ना ही संबंधों को सांस देना है और अहंकार को छोड़ना ही स्वयं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना है। जब मनुष्य के पास बहुत कुछ होते हुए भी उसे कुछ पकड़कर रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वही क्षण त्याग की साधना का सच्चा फल है।

प्रेरणा अवस्थी

यात्रियों की सुरक्षा का सवाल

सुनीता मिश्रा

बीते दिनों ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एसी स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद स्लीपर बस के पुराने रिकार्ड सामने आए। इसे नियमों की लगातार अनदेखी करते हुए चलाया जा रहा था। देश में स्लीपर बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबी दूरी की यात्रा में इनके बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यात्री अक्सर रात में सो रहे होते हैं। ऐसे में दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए समय बेहद कम होता है।

स्लीपर बसों में आपातकालीन दरवाजों का समय पर न खुलना एक और बड़ी समस्या है। कई बसों में खिड़की तोड़ने के लिए न हथौड़ा और न ही कोई और साधन उपलब्ध होते हैं। इनमें अग्निशमन व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं होती। इसको देखते हुए फिटनेस प्रमाणपत्र को महज कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जा सकता। फिटनेस जांच के दौरान यह देखना जरूरी है कि आपातकालीन दरवाजे वास्तव में खुल रहे हैं या नहीं, अग्निशमन उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं और यात्रियों के बाहर निकलने का रास्ता सामान या किसी अतिरिक्त संरचना से बाधित तो नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 से 10 दिसंबर 2025 तक देश में बसों में आग लगने की 45 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें 64 लोगों की मौत हुई और 145 लोग घायल हुए।

> **सड़क सुरक्षा का अर्थ सिर्फ दुर्घटना रोकना नहीं, बल्कि दुर्घटना होने पर जान बचाने की पूरी तैयारी रखना भी है**

ये हादसे केवल चालक की लापरवाही तक सीमित नहीं हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस बस के खिलाफ दर्जनों चालान हो चुके हों, वह यात्रियों के लिए वास्तव में कितनी सुरक्षित है? अगर किसी वाहन के खिलाफ बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हों तो क्या केवल चालान काटना और जुर्माना लगाना पर्याप्त है? चालान व्यवस्था का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। ऐसे में यह तय करने की जरूरत है कि किस स्तर के उल्लंघन के बाद वाहन की दोबारा फिटनेस जांच, परमिट की समीक्षा या अस्थायी रोक जरूरी होगी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए बसों में जरूरत से ज्यादा सीटें लगा दी जाती हैं। ऐसे में बंद आपातकालीन दरवाजे, सीटों के बीच सामान, जगह की कमी और अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के कारण होने वाले हादसों में कई यात्रियों की जान चली जाती है। यदि किसी यात्री की चेतावनी समय रहते सुन ली जाए, बस को तत्काल रोक दिया जाए और आपातकालीन दरवाजे जरूरत के समय खुल जाएं तो कई परिवारों को जीवन भर का दुख झेलने से बचाया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बदलती जलवायु की गंभीर तस्वीर

'अस्थिर मौसम की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय बदलती जलवायु की गंभीर तस्वीर सामने रखता है। बिडेनवा यह है कि जिस समय देश के पर्यावरण एवं मौसम विज्ञानी सुपर अल नीनो की आशंका के चलते भीषण सूखे की चेतावनी दे रहे थे, उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब यानी निम्न वायुदाब 'अंबर' और उसके साथ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के मौसम का रुख बदल दिया। इसके प्रभाव से हुई लगातार बारिश से शहरों और गांवों में जलभराव हो गया, घरों और सामान को नुकसान पहुंचा तथा खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित हुईं। पहाड़ों में बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो जाने से यातायात बाधित हुआ है। बदरीनाथ, केदारनाथ और आदि कैलाश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब मौसम के चलते चारधाम और आदि कैलाश यात्राएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी हैं। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली तथा संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कच्चे मकानों के ढहने से जान-माल का नुकसान हुआ है, जबकि दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। तापमान में अचानक गिरावट से सर्दी-जुकाम, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों के मामलों में भी वृद्धि की आशंका बढ़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यही है कि जलवायु परिवर्तन को केवल बढ़ते तापमान के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कभी सूखे की आशंका और कभी कम समय में अत्यधिक बारिश-मौसम की यह बढ़ती अनिश्चितता कृषि, शहरों, परिवहन और आपदा प्रबंधन, सभी के लिए चुनौती है।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

मेलबाक्स

इंटरनेट मीडिया का क्रेज

इंटरनेट मीडिया ने लोगों को अपनी गिरफ्त में इस कदर जकड़ा हुआ है कि वे लाइक्स और फोलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर नाम और पैसा कमाने की होड़ में कानून, नियम, सामाजिक मूल्य, नैतिकता सब दरकिनार कर दी है। रील एवं वीडियो बनाने के चक्कर में वे न अपनी सुरक्षा देखते हैं और न इस बात पर गौर करते हैं कि लोगों को असहज महसूस हो रहा होगा। सड़क के बीचोंबीच रील बना यातायात बाधित करना या दिक्कत में डालना कहां तक सही है? इंटरनेट के क्रेज में युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसे स्टंट, सड़कों पर यातायात बाधित कर रील बनाने पर सरकार को सजा का प्रविधान रख अंकुश लगाना चाहिए। माता-पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों की सही परवरिश करें, नैतिक मूल्यों, सामाजिक दायरे, नियमों की पालना, अच्छे संस्कार दें। बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएं। 18 की उम्र से पहले बच्चों को वाहन चलाने देना सरासर माता-पिता की गलती है। इंटरनेट मीडिया पर ऐसे स्टंट या गैर कानूनी सामग्री डालने पर कानून बनाना चाहिए जिससे हादसों को रोका जा सके।

abhilasha19gupta@gmail.com

सड़क दुर्घटना की चिंतनीय स्थिति

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023-24 रिपोर्ट झारखंड के लिए गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करती है। दुर्घटना-गंभीरता के मामले में राज्य लगातार दूसरे वर्ष देश में तीसरे स्थान पर रहा। 2023 में झारखंड में दुर्घटना-गंभीरता 78.5 और 2024 में 79.2 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 2023 में केवल 36 था। झारखंड में 2023 में 4,173 और 2024 में 4,114 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। मौतें बताती हैं कि समस्या केवल यातायात व्यवस्था की नहीं, बल्कि व्यापक सड़क-सुरक्षा संकट की है। तेज गति, असुरक्षित ओवरटेकिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी पर नियंत्रण जरूरी है। दुर्घटना-प्रवण स्थानों की पहचान, इंजीनियरिंग सुधार और त्वरित ट्रामा-केयर की एकीकृत कर ही झारखंड की सड़कें व सुरक्षित बनाई जा सकती हैं।

हेमंत कुमार, हवाई नगर, रांची

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615600, E-mail: delhi@ndi.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

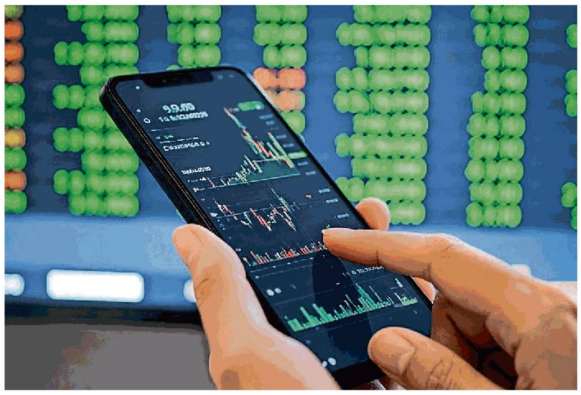


अजय वंसल
आर्थिक मामलों के जानकार

टाटा संस

विरासत से बाजार की निगरानी तक

टाटा समूह की पहचान केवल कारोबार से नहीं, बल्कि उस कारोबारी परंपरा से भी जुड़ी है जिसमें उद्योग, सामाजिक दायित्व और दीर्घकालिक संस्थागत सोच एक-दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में टाटा समूह की मूल होल्डिंग कंपनी टाटा संस का शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना महज एक कारोबारी घटना नहीं होगी। यह उस संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिसके माध्यम से इस समूह की अनेक बड़ी कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण संचालित होता है



हाल के दिनों में कारपोरेट से जुड़ी घटनाओं के प्रति निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। प्रतीकात्मक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा टाटा संस के कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआइसी) के रूप में पंजीकरण समाप्त करने के आवेदन को इसी माह अस्वीकार किए जाने के बाद यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल आरबीआइ ने टाटा संस को ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) के लिए लागू नियमों का पालन करने को कहा है, जिसका प्रमुख परिणाम शेयर बाजार में सूचीबद्धता की जरूरत है।

यहां यह समझना जरूरी है कि टाटा संस स्वयं टाटा समूह की अधिकांश उपभोक्ता-परिचित कंपनियों की तरह कोई सामान्य परिचालन कंपनी नहीं है। यह टाटा समूह की प्रधान निवेश होल्डिंग कंपनी और प्रवर्तक है। टाटा समूह की विभिन्न कंपनियां अपने-अपने निदेशक मंडल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जबकि टाटा संस उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने और समूह के व्यापक ढांचे को जोड़ने वाली केंद्रीय संस्था है। टाटा समूह आज 31 कंपनियों वाला वैश्विक कारोबारी समूह है, जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। वर्ष 2024-25 में टाटा समूह की कंपनियों का संयुक्त राजस्व 180 अरब डालर से अधिक था और इन कंपनियों में दस लाख से अधिक लोग कार्यरत थे। समूह की 26 कंपनियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं और 31 मार्च, 2025 को उनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण 328 अरब डालर से अधिक था।

लेकिन इन सूचीबद्ध कंपनियों के ऊपर टाटा संस की अलग भूमिका है। टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी परोपकारी टाटा ट्रस्टों की है। इन ट्रस्टों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कला-संस्कृति और अन्य सामाजिक कार्यों को समर्थन मिलता है। यही तथ्य टाटा संस की प्रस्तावित सूचीबद्धता को सामान्य आइपीओ से अलग बनाता है।

मामले की जड़ भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीएफसी संबंधी नियमन में है। आरबीआइ ने सितंबर 2022 में टाटा संस को एनबीएफसी-यूएल यानी अपर लेयर एनबीएफसी की श्रेणी में रखा। इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं पर सामान्य एनबीएफसी की तुलना में अधिक कठोर नियामकीय आवश्यकताएं लागू होती हैं। आरबीआइ के नियमों के तहत ऐसी संस्था को निर्धारित अवधि में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है। टाटा संस के मामले में तीन वर्ष की समयसीमा 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हो गई। यहीं से टाटा संस और नियामक के बीच असली पेच शुरू हुआ। टाटा संस का तर्क यह था कि यदि वह सीआइसी के रूप में आरबीआइ के दायरे से बाहर निकल जाए तो अनिवार्य सूचीबद्धता की जरूरत नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से कंपनी ने मार्च 2024 में आरबीआइ के पास अपना सीआइसी पंजीकरण स्वेच्छा से वापस करने का आवेदन किया। कंपनी ने इस दिशा में अपनी वित्तीय स्थिति बदली और अपना कर्ज चुकाया। लेकिन आरबीआइ ने इस आवेदन पर तत्काल निर्णय नहीं दिया।

इस बीच सितंबर 2025 में सूचीबद्धता की समयसीमा समाप्त हो गई, लेकिन टाटा संस शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुई। आरबीआइ की ओर से उस समय यह स्पष्ट किया गया कि किसी संस्था का पंजीकरण तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उसे औपचारिक रूप से रद नहीं किया जाता। यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पक्ष है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई यह मान सकता है कि यदि टाटा संस ने अपना कर्ज चुका दिया और स्वयं बाजार से धन नहीं जुटा रखी, तो उसे एनबीएफसी के रूप में क्यों रखा जाए? लेकिन आरबीआइ के नियमन में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कंपनी के ऊपर सीधे कितना कर्ज है।

आरबीआइ के नियमों के अनुसार सीआइसी मूलतः ऐसी एनबीएफसी है जिसका प्रमुख कारोबार समूह की कंपनियों में निवेश रखना है। नियमों में समूह कंपनियों में निवेश की संरचना और सर्वजनिक धन तक पहुंच को महत्वपूर्ण माना गया है। आरबीआइ की व्याख्या में परोक्ष रूप से सार्वजनिक धन तक पहुंच को भी महत्व दिया गया है। यानी यदि समूह की अन्य कंपनियां बैंक ऋण, डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र जैसे साधनों से धन जुटाती हैं, तो केवल टाटा संस के अपने कर्ज-मुक्त होने से नियामकीय प्रश्न स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। यही वह बिंदु है जिसने टाटा संस की डी-रजिस्ट्रेशन की कोशिश को कठिन बनाया।

दूसरा बड़ा पक्ष : इस विवाद में टाटा ट्रस्टों के साथ शापूरजी पालोनजी समूह की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार टाटा संस के दो प्रमुख शेयरधारक समूहों की सूचीबद्धता को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं। टाटा ट्रस्टों की ओर से सूचीबद्धता के प्रति आपत्ति की खबरें सामने आई हैं, जबकि शापूरजी पालोनजी समूह सूचीबद्धता के पक्ष में रहा है। इस अंतर का आर्थिक कारण भी समझना जरूरी है। सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य स्पष्ट होता है और शेयरधारक नियामानुसार अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचकर पूंजी जुटा सकते हैं। इसलिए टाटा संस की सूचीबद्धता उसके मौजूदा शेयरधारकों के लिए केवल नियामकीय विषय नहीं, बल्कि पूंजी और स्वामित्व से जुड़ा प्रश्न भी है।

क्या बदलेगा : सबसे बड़ा बदलाव पारदर्शिता का होगा। सूचीबद्ध कंपनी के रूप में टाटा संस को बाजार और निवेशकों के सामने कहीं अधिक नियमित वित्तीय तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक करनी होंगी। दूसरा प्रभाव मूल्यांकन पर पड़ेगा। टाटा संस के पास टाटा समूह की अहम कंपनियों में हिस्सेदारी है। इसलिए बाजार टाटा संस की हिस्सेदारी का मूल्यांकन करके उसकी अपनी कीमत तय करेगा। तीसरा प्रभाव कारपोरेट गवर्नेंस पर होगा। सूचीबद्धता के बाद शेयरधारकों, संस्थागत निवेशकों व बाजार नियामकों की निगरानी बढ़ेगी। कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर सूचना और जवाबदेही की अपेक्षा भी अधिक होगी। चौथा पहलू पूंजी जुटाने से जुड़ा है। सूचीबद्धता का लाभ यह होगा कि टाटा संस को अनिवार्य रूप से बड़ी राशि जुटानी ही होगी। लेकिन सार्वजनिक बाजार में मौजूदगी भविष्य में पूंजी बाजार तक पहुंच के विकल्प बढ़ा सकती है।

कारपोरेट गवर्नेंस में एक नया अध्याय

पिछली लगभग एक सदी से टाटा समूह भारतीय बिजनेस के एक खास माडल का प्रतिनिधित्व करता रहा है- एक ऐसा माडल जो लांग-टर्म ओनरशिप, संस्थागत नेतृत्व और ऐसी सोच पर बना है जिसमें अक्सर मुनाफे के साथ-साथ मकसद को भी अहमियत दी गई है। टाटा संस की लिस्टिंग अब एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो मार्केट के दायरे से कहीं आगे जाता है- जब निजी नेतृत्व में बनी कोई संस्था पब्लिक-मार्केट के दायरे में आती है, तो क्या होता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि लिस्टिंग से ज्यादा जानकारी सामने आएगी और निवेशकों व मार्केट की तरफ से निगरानी बनी रहेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस कारण गवर्नेंस को लेकर बातचीत में क्या बदलाव आते हैं।

आज, टाटा संस कई तरह के बिजनेस के विस्तृत इकोसिस्टम के केंद्र में काम करती है। इसके फैसलों का असर टेक्नोलाजी, आटोमोबाइल, स्टील, पावर, हास्पिटैलिटी, केंज्यूमर बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है। कंपनी का दायरा और जटिलता बढ़ने के साथ यह सवाल भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसी संस्था का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। कारपोरेट गवर्नेंस के एक विशेषज्ञ का यह मानना है, 'पब्लिक ओनरशिप और ईस्टीट्यूशनल कैरेक्टर का एक-दूसरे के उलट होना जरूरी नहीं है। लिस्टेड होने के बाद भी टाटा संस में एक बड़ा कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर बना रह सकता है। साथ ही, पब्लिक शेयरहोल्डर्स संस्थान में अतिरिक्त जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड एक लिस्टेड कंपनी के लिए लागू नियमों के तहत काम करेगा, वहीं निवेशकों की अधिक आसानी से जानकारी मिलेगी और कंपनी के मूल्य का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मार्केट प्रणाली होगी।' वहीं एक कारपोरेट गवर्नेंस के एक अन्य जानकार के अनुसार, 'टाटा संस को एक निजी संस्थान के बजाय लिस्टेड कंपनी में बदलने से बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी। कंपनी के फैसलों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी हो जाएगा। साथ ही बोर्ड को कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर्स के हितों के बीच संतुलन भी बनाना होगा। इससे हितधारकों के हितों का प्रबंधन ज्यादा स्पष्ट रूप से हो सकेगा।'

इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू निरंतरता का भी है। टाटा समूह की संस्थागत पहचान समीक्षा के अभाव में नहीं बनी है। बल्कि यह दीर्घकाल में बने स्वामित्व और नेतृत्व पर आधारित है। पब्लिक लिस्टिंग से जांच-पड़ताल का एक नया रूप सामने आएगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस नजरिये को छोड़ दिया जाए। इसके बजाय, इससे यह तय किया जा सकेगा कि क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं। कहा जा सकता है कि कारपोरेट भरत के लिए, संभावित लिस्टिंग एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन सकती है कि कैसे स्थापित संस्थान पारदर्शिता, जवाबदेही व शेयरहोल्डर की भागीदारी के बारे में बदलती उम्मीदों के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। इसलिए, टाटा संस के आइपीओ को केवल इस सवाल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि यह कितना पैसा जुटाता है या मार्केट इसे क्या वैल्यूएशन देता है। इसकी महत्ता संभवतः इस बात में है कि यह स्वयं उस संस्था से क्या उम्मीद रखता है। इस कदम से बाजार में नए अवसर पैदा होंगे और करोड़ों निवेशकों के लिए भागीदारी के रास्ते बनेंगे।

(अजय वंसल)

खरी-खरी

अंधानुकरण

विनय कुमार पाठक

भेड़ियाधसान एक शब्द है जिसका भेड़िया से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है भेड़ों से। इसका मतलब है भेड़ों की तरह आगे वाले का आंख मूंदकर अनुकरण करना। यानी आगे वाला भेड़ यदि कुएं में कूद गया है तो पीछे वाले भी कूदेंगे ही, बिना यह विचार किए कि इसका क्या हश्र होने वाला है। वैसे यह प्रवृत्ति भेड़ों की अपेक्षा मनुष्यों में अधिक पाई जाती है। अभी पिछली सदी के नौवें दशक में जाने की प्रवृत्ति इसका उदाहरण है। शायद ही कोई शख्स होगा जो खुद को पिछली सदी के नौवें दशक में न ले गया होगा ट्रेंड का अनुसरण करते हुए। कुछ खुद की लीक से अलग हटकर चलने वालों ने तब की अपने फोटो को ही डाल दिया। यानी वे इस ट्रेंड से प्रभावित तो हुए पर उस हद तक नहीं कि उनके इस कृत्य को भेड़ियाधसान की श्रेणी में सटीकता से डाला जा सके।

मनुष्यों की इस प्रवृत्ति को बाजार बहुत अच्छी तरह से जानता है। और इस प्रवृत्ति को भुनाने के लिए उसके पास विज्ञापन नामक अमोघ अस्त्र है। और विज्ञापन के लिए साधन? वह तो यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां-कहां है। तो किसी भी ट्रेंड को विज्ञापन के द्वारा चालू कर दो और पांचों उंगलियां घी में। जेन जी का तो इस मामले में कोई सानी नहीं है। नए ब्रांड का गैजेट लेने के लिए वे खुद को और अपने परिवार को भी बेधक रखने के लिए तैयार हो जाते हैं।

'अर्ली एडाप्टर' बनने के गर्व पाने के लिए सभी मनुष्य बेताब हो जाते हैं। नया गैजेट, एप, ट्रेंड कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता आज का मनुष्य। भले ही उसका मोबाइल फोन बिलकुल बकाया की तरह सारे काम करता हो, पर चूंकि विज्ञापन में फोल्डेबल मोबाइल का विज्ञापन देख लिया तो फिर अपने बकादार मोबाइल को छोड़कर फोल्डेबल मोबाइल की और दौड़ लगा दी। भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। 'लव के लिए सारा कुछ भी करेगा' कुछ कुछ इसी तर्ज पर।

इनमें कई चीजें हैं जो बाद में घर के किसी एक कोने में पड़ी रह जाती हैं। पर बाजार को तो लक्ष्मी की जो कृपा चाहिए थी वह मिल गई। 'अर्ली एडाप्टर' बनने के चक्कर में बेचारा आम आदमी भले ही गले तक कर्ज में डूब जाए।

पोस्ट

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मामले में सिर्फ भ्रम है। कुछ स्पष्ट है तो यह 'हिंसा' है।
अशित प्रकाश@AshitPrakash4

खबर है कि पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाना कम कर कार्बन डेडिक्स के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बेहतर कदम है।
आरके विज@ipsvijrk

उज्जैन में विकास पर उन्माद का पलथ। एक तरफ सीएम मोहन यादव ने सड़क चौड़ीकरण के लिए खुद अपने पैतृक घर को तोड़ने की मिसाल दी। वहीं शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाने के दौरान उग्रदर्शनों ने कर दिया भारी पथराव।
अरुण शिवहरे@ArunShivhare100

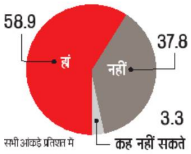


चीन भारत के उभार से क्यों नफरत करता है? क्योंकि यदि एक लोकतंत्र महाशक्ति बन जाएगा तो इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का माडल सवालों में आ जाएगा। अमेरिका भारत के उभार से क्यों नफरत करता है? उसे डर है कि भारत आर्थिक रूप से एक और चीन बन सकता है और 2050 तक भारत व चीन मिलकर अमेरिकी वर्चस्व समाप्त कर सकते हैं।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या निर्वाचन आयोग की बैठक यह दर्शाने वाली रही कि आयोग में सब ठीकठाक है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या लंबित ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जोड़े जाने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

खड़ी निरंतर कर रहे शतक-रनों की लाट,
बैटर बड़े कमाल के सचमुच बधु विराट।
सचमुच बधु विराट नजर न कोई लगाए,
सबसे बड़ा रिकार्ड आपकी झोली आए।
इनकी क्षमता देख विरोधी कापें थर-थर,
ये रिकार्ड की लाट कर रहे खड़ी निरंतर!
-ओम प्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी



जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

ममता का नया दांव, रंग से परे राजनीति

राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर विचारधाराएं स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन सत्ता और परिस्थितियां जब करवट बदलती हैं तो वही राजनीति नए समीकरण गढ़ती है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया रुख इसी बदलाव की मिसाल है। कभी वामपंथ के खिलाफ अपने राजनीतिक अस्तित्व की नींव रखने वाली ममता अब उसी वाम खेमे, विशेषकर एमए बेबी से संवाद कर रही हैं। साथ ही, राहुल गांधी के साथ उनकी बढ़ती सक्रियता यह संकेत देती है कि भाजपा के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता को लेकर नया प्रयोग शुरू हो चुका है।

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर उठा बिवाद, जिसे विपक्ष एक बड़े संवैधानिक संकट के रूप में पेश कर रहा है। यही मुद्दा अब 'आइएनडीआइए' गठबंधन के पुनर्गठन का आधार बनता दिख रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित बैठक को इसी कड़ी के अहम माना जा रहा है, जहां विपक्ष अपनी रणनीति को नए सिरे से तय करने की कोशिश करेगा। ममता बनर्जी का ताजा बयान- 'कौन किस रंग का है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा जनता का होना चाहिए'- दरअसल उनकी राजनीतिक सोच में आए बदलाव का सार्वजनिक प्लान है।

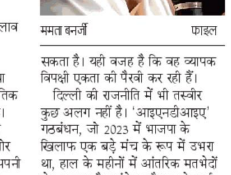
इस बदलाव को केवल वैचारिक लचीलापन कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे गहरी राजनीतिक मजबूरी और रणनीतिक समझ भी है। बंगाल में सत्ता खोने के बाद तृणमूल कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ा है, जबकि भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में अकेले लड़ना ममता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि वह व्यापक विपक्षी एकता की पैरवी कर रही हैं।

दिल्ली की राजनीति में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। 'आइएनडीआइए' गठबंधन, जो 2023 में भाजपा के खिलाफ एक बड़े मंच के रूप में उभरा था, हाल के महीनों में आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगियों के बीच टकराव सामने आ चुका है। ऐसे में ममता बनर्जी का सक्रिय होना इस गठबंधन को फिर से ऊर्जा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब वह ममता नहीं जो 2023-24 में थीं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टक्कर देने वाले प्रमुख चेहरे के रूप में माना जाता था। अब वे न तो उनके पास सत्ता है और न ही एकजुट पार्टी संगठन है। यही वजह है कि वह भाजपा विरोधी दलों की और देख रही हैं। ममता का यह प्रयास केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है। उन्होंने वाम दलों, विशेषकर माकपा के साथ भी संवाद शुरू किया है। मोहम्मद सलीम जैसे नेताओं ने साफ कर दिया है कि बंगाल में तृणमूल के साथ समझौता नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ 'बड़े संघर्ष' के लिए सहयोग से इन्कार नहीं किया है। यह द्वंद्व राजनीति की उस जटिलता को दिखाता है जहां राज्य और केंद्र की राजनीति अलग-अलग दिशा में चलती है।

ममता बनर्जी और माकपा के बीच यह संभावित नजदीकी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह संकेत देता है कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई अब वैचारिक सीमाओं को पार कर रही है। हालांकि, यह रास्ता आसान नहीं होगा। दशकों की राजनीतिक दुश्मनी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच टकराव इस एकता की राह में बड़ी बाधा बन सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर उठाए गए सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस को तेज कर रहे हैं।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा वास्तव में विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? या यह केवल एक अस्थायी रणनीतिक गठजोड़ बनकर रह जाएगा? इतिहास बताता है कि भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता अक्सर चुनावी जरूरतों तक सीमित रहती है। विचारधारात्मक मतभेद और नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं इसे स्थायी रूप नहीं लेने देतीं। ममता बनर्जी की पहल को इसी संदर्भ में समझना होगा। यह एक और उनकी राजनीतिक पुनर्स्थापना की कोशिश है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने की रणनीति भी।

आने वाले दिनों में दिल्ली की बैठक इस पूरी रणनीति की दिशा तय करेगी। अगर विपक्ष अपने मतभेद भुलाकर एक साझा एजेंडा बनाने में सफल होता है, तो यह भाजपा के लिए एक चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर यह प्रयास विफल होता है, तो ममता बनर्जी का यह 'रंग से परे' दांव भी भारतीय राजनीति के उन कई प्रयोगों की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, जो उम्मीदें तो जगाते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव नहीं ला पाते। फिलहाल इतना साफ है कि भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां पुराने विरोधी भी नए साथी बन सकते हैं- अगर परिस्थितियां और जरूरतें उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करें।



ममता बनर्जी फाइल

मंथन



अजय कुमार राय
ajayrai@nda.jagran.com

जन-जन की मांग बने विकसित भारत

भारत निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। परंतु पंक्ति में खड़े देश के अंतिम नागरिक को भी यह महसूस होना चाहिए कि भारत वास्तव में विकसित हो गया है। इसके लिए विकसित भारत यात्रा शुरू करने और इसे एक अभियान बनाए जाने की जरूरत है



यात्रा से टूटती है जड़ता। फाइल

गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की शासन प्रणाली में बदलाव और प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधार पर गहन विचार-विमर्श के लिए अपने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ चिंतन शिविर का आयोजन किया। समाचारों के अनुसार, इसमें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हुई। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। गत एक दशक में इसके लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। यहां से एक छलांग भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करा सकती है, वहीं एक फिसलन इसे मुश्किल भंवर में फंसा देगी। वैसे आगे की राह अनुकूल नहीं, बल्कि फिसलन एवं उथल-पुथल भरी ही अधिक नजर आ रही है।

वस्तुतः अभी देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर एक साथ कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-ईरान युद्ध हर रोज हमारी आर्थिकी, रणनीति एवं कूटनीति की परीक्षा ले रहे हैं। वहीं कुछ ताकतें देश में अराजकता फैलाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती दिख रही हैं। इससे रह-रहकर कानून-व्यवस्था और नीतिगत पहलों के पटरी से उतरने की आशंका पैदा हो रही है।

ऐसे समय में विकसित भारत के लिए एक देशव्यापी यात्रा निकालने या अभियान छेड़ने की आवश्यकता बढ़ गई है। केंद्र सरकार की अगुआई में सभी दलों के जनप्रतिनिधि जैसे कि सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच आदि और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में इस यात्रा को निकालें तो अच्छा होगा। सरकार को सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और संघ के स्वयंसेवकों का सहयोग लेना चाहिए। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर क्षेत्र में युवाओं खासकर जेन-जी के नेतृत्व में जागरूक लोगों की एक टीम बनाई जा सकती है। जिस तरह चुनाव के समय उम्मीदवार घर-घर जाते हैं, वैसे ही इस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, मोहल्ला, समाज, क्षेत्र तक पहुंचना होगा। यदि जरूरत पड़े तो जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी हर गांव, चौक-चौराहे, गली-मोहल्ले में कैंप लगाकर बैठें। इस यात्रा के दौरान लोगों की विकसित भारत का मतलब बताया जाना चाहिए, उनकी और उनके क्षेत्र, समाज की समस्याओं को जानने-समझने के साथ-साथ मौके पर ही उनका समाधान भी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की विकसित भारत के लिए एक कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि इस अभियान के दौरान लोगों की मांग पर विकास एवं जनकल्याण के सभी तरह के काम एक तय अवधि में किए जा सकें।

यदि यह यात्रा प्रत्येक जन, परिवार और क्षेत्र तक पहुंचती है और यहां से निकले विचार दीर्घकालिक नीतियों का आधार बनते हैं तो देश को इन दोनों मोर्चों पर खड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। अभी देश में एक तरह की निराशा का माहौल है। उसे निराशा से निकाल नई उम्मीद जगाने और ऊर्जावान बनाने में भी यह यात्रा मददगार हो सकती है। अभी विकसित भारत का सपना केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सिमटा हुआ है। इसे वहां से निकालकर जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी इस यात्रा की महती आवश्यकता है, क्योंकि यह काम अकेले सरकार के प्रयास से नहीं होने वाला है। इसमें जनता की भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। जनता जागरूक होकर इसकी मांग करेगी तो यह काम आसान होगा। विकसित भारत का लाभ जन-जन को पता हो, तब वे इसमें दिलचस्पी लेंगे और भागीदार बनेंगे।

विकसित भारत की ऐतिहासिक मांग जमीन से हो तो मोदी सरकार की इस मुहिम के लिए अच्छा रहेगा। सबके सहयोग से बना विकसित भारत टिकाऊ भी होगा। आजादी की लड़ाई इसका सबसे सफल उदाहरण है। कुछ स्वतंत्रता सेनानी अपने-अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गांधी जी जैसे राजनेता इसे जनता के बीच ले गए और जन-जन को आजादी का अर्थ बताया, फिर उनमें इसको पाने की ली जली जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। जनशक्ति इतिहास की दिशा को मोड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन मानी जाती है। वैसे भी यात्राएं सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने का नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं एवं दुख-दर्द से एकाकार होने और जन-जागरण यानी चेतना जगाने का उत्तम माध्यम भी होती हैं।

अभी गांव, समाज और देश की चेतना में एक तरह का ठहराव दिख रहा है। उसे कहां जाना है, इसको लेकर उलझन में है। विकसित भारत यात्रा इस जड़ता को तोड़ेगी और उनकी दृष्टि का विस्तार करेगी। देश को अगले 20-25 वर्षों के लिए दिशा देने और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह अभियान जरूरी नजर आ रहा है।

आज जब विपक्ष हावी है और तरह-तरह के आरोप लगाकर सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में यह यात्रा मोदी सरकार और स्वयं भाजपा की भी जनता के बीच अपना विश्वास मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उसके प्रति समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। यह अभियान पूरे देश में कम से कम दो साल चलना चाहिए। तब देश केवल आर्थिक अर्थशास्त्र के मानकों जैसे प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी के आकार के आधार पर ही विकसित नहीं बनेगा, बल्कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को महसूस होगा कि उसका भारत विकसित हो गया है।

सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री तीन प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली: जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री तीन प्रतिशत बढ़कर 1,00,220 इकाई रही है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 97,080 इकाई थी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनराक के अनुसार, यह वृद्धि मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन, बेंगलुरु और हैदराबाद में बेहतर मांग के कारण हुई है। मूल्य के लिहाज से जुलाई-सितंबर के दौरान कुल बिक्री दो प्रतिशत बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये रही है। (प्रेट्र)

वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करना सभी के लिए फायदेमंद है। इससे सीमारेखा पर मौजूद और भी लोग सामाजिक सुरक्षा उपायों के दायरे में आ सकेंगे।
– चंद्रभूषण कुमार, सचिव, श्रम मंत्रालय



सेंसेक्स	72,771.72 ▼ 1,124.02	निफ्टी	22,780.25 ▼ 360.25	सोना प्रति दस ग्राम	₹1,50,000 ▼ ₹2,600	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹2,32,000 ▼ ₹5,000	डालर	₹95.97 ▲ ₹0.22	क्रूड प्रति बैरल	$108.3

टाटा संस को लिस्टिंग से बचाने के लिए ट्रस्ट्स का नया प्रस्ताव

- सबसे बड़ी शेयरधारक ने होल्डिंग कंपनी के दो अन्य कंपनियों के विलय की बात कही
- इससे टाटा संस को एनबीएफसी के दायरे से हटाए जाने में मिलेगी मदद



होल्डिंग कंपनी को लेकर ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड में मतभेद बढ़े

ट्रस्ट्स ने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद यह पक्का करना है कि पुनर्गठित टाटा संस एनबीएफसी या मूल निवेश कंपनी के लिए नियामकीय शर्तों को पूरा नहीं करे। यह रीस्ट्रक्चरिंग योजना ऐसे समय में आई है जब टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड के बीच इसके भविष्य के ढांचे को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। अक्टूबर 2024 से नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट्स ने टाटा संस को सूचीबद्ध करने का विरोध किया है और जुलाई 2025 में एकमत से यह तय किया कि कंपनी को एक गैर सूचीबद्ध निजी कंपनी के तौर पर बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। यह स्थिति तब और जरूरी हो गई जब आरबीआइ ने 2022 में टाटा संस को एक उच्च स्तर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत कर दिया। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसके लिए सूचीबद्धता की जरूरत होती है। टाटा संस ने एनबीएफसी फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आरबीआइ ने सितंबर में उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली, ब्रेट : टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड से प्रस्ताव पर विचार करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसमें करना शामिल है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड से प्रस्ताव पर विचार करने और जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसमें प्रस्तावित विलय के लिए आरबीआइ से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना भी शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक, 31 मार्च, 2026 तक संयुक्त कंपनी का संचालन राजस्व 105,043 करोड़ रुपये होगा और यह कुल आय का 64.3 प्रतिशत होगा। जबकि वित्तीय संपत्तियों से आय 40,072 करोड़ रुपये होगी। पुनर्गठित इकाई के पास 2,00,158 करोड़ के शुद्ध संपत्तियां होंगी, जिसमें से ग्रुप कंपनियों में निवेश 1,77,120 करोड़ रुपये होगा, जो कुल शुद्ध संपत्तियों का 90 प्रतिशत से कम है। ट्रस्ट्स के अनुसार, इसका मतलब होगा कि यह एनबीएफसी के लिए मुख्य कारोबार मानदंड के लिए लागू शर्तों को पूरा नहीं करेगा।

आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे पीयूष गोयल

नई दिल्ली, प्रेट्र: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 29 सितंबर से पांच अक्टूबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वे जी 20 बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत आगे बढ़ाने पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ चर्चा करेंगे।

गोयल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के बुलावे पर 30 सितंबर और एक अक्टूबर को विस्कान्सिन के मिल्वाकी में जी20 के व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। गोयल अमेरिका के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। यह एक संतुलित और आपसी लाभ वाले भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और सात फरवरी, 2026 के संयुक्त घोषणा के मुताबिक एक अंतरिम समझौते की अंतिम रूप देने की चल रही कोशिशों का हिस्सा है।

3.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची आइपीओ पाइपलाइन

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत का प्राथमिक बाजार यानी आरंभिक सर्वजनिक निर्गम (आइपीओ) अभूतपूर्व उछाल का अनुभव कर रहा है। उद्योग संगठन एसोसिएशन आफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आफ इंडिया (एआइबीआइ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेनबोर्ड आइपीओ की पाइपलाइन 3.86 लाख करोड़ रुपये के असाधारण स्तर पर पहुंच गई है, जो 2026 में अब तक 84 आइपीओ के जरिये जुटाए गए 1.10 लाख करोड़ रुपये की तुलना में तीन गुना से अधिक है। यह कंपनियों की सार्वजनिक बाजारों में निवेश करने की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

एआइबीआइ के अनुसार, पाइपलाइन में शामिल करीब 130 कंपनियों को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से आइपीओ लाने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, 75 कंपनियों ने मसौदा दस्तावेज जमा कर दिए हैं और रेगुलेटर की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। एआइबीआइ के चेयरमैन महावीर लुनावत के अनुसार, कुल पाइपलाइन में सेबी से मंजूरी प्राप्त कंपनियों का हिस्सा लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये है, जबकि मंजूरी का इंतजार कर रही कंपनियों की हिस्सेदारी 1.44 लाख करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक बाजार अब एक गहरे और अधिक स्थायी पूंजी निर्माण इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, मेनबोर्ड आइपीओ ने 2016 से 2026 तक कुल मिलाकर 8.36 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस दौरान वार्षिक फंडिंग 2026 की 26,494 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1.76 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 2026 में अब तक 84 मेनबोर्ड आइपीओ के जरिये 1.10 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। 2016 में कुल आइपीओ की संख्या 26 थी, जो 2025 में बढ़कर 103 हो गई है। 2025 में एसएमई श्रेणी में कुल 267 आइपीओ आए थे। 2026 में 156 आइपीओ आ चुके हैं।

1.10 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए आइपीओ के जरिये 2026 में अब तक

8.36 लाख करोड़ रुपये के आइपीओ आ चुके हैं 2016 से अब तक



10 वर्ष में मर्चेंट बैंकरों की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ी

बीते 10 वर्षों में पंजीकृत मर्चेंट बैंकरों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सितंबर 2016 में पंजीकृत मर्चेंट बैंकों की संख्या 188 थी, जो सितंबर 2026 में 250 हो गई है। इसी तरह, निवेशकों की भागीदारी भी व्यापक बनी हुई है।2026 में अब तक औसत सब्सक्रिप्शन योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) के लिए लगभग 49 गुना, उच्च-नेटवर्थ निवेशकों के लिए 86 गुना और खुदरा निवेशकों के लिए 26 गुना रहा है।

तीन कंपनियों को मिली आइपीओ की मंजूरी

सेबी से तीन कंपनियों- पायनियर फिल-मिड, टीबो इमेजिंग इंडिया और फंक्शनल एंड इनोवेटिव फूड्स को आइपीओ लाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे उपकरण बनाने वाली पायनियर फिल-मिड के 500 करोड़ रुपये के आइपीओ में 250 करोड़ के नए शेयर और 250 करोड़ के प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। टीबो इमेजिंग इंडिया का आइपीओ पूरी तरह से प्रमोटर शेयर बिक्री पर आधारित है और इसमें 1,80,85,246 शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इसी तरह, फंक्शनल एंड इनोवेटिव फूड्स के आइपीओ में 60 लाख नए शेयर और 25 लाख प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे।

एक नजर में

अदाणी समूह की चार कंपनियों ने विवाद निपटाया

बेंगलुरु: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने सोमवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और समूह की चार कंपनियों को 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों के उल्लंघन से जुड़े विवाद को निपटाने की मंजूरी दे दी। सेबी ने कहा कि गौतम अदाणी समेत 14 कथनी निदेशकों और चार कंपनियों ने कुल 1.48 करोड़ रुपये का भुगतान करके मामलों का निपटारा कर लिया है। इस संबंध में अदाणी समूह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेबी को वर्ष 2020 में अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी ट्रांसमिशन के खिलाफ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का पालन न करने संबंधी शिकायत मिली थी। (रायटर)

रियल एस्टेट, डाटा सेंटर में 9.5 अरब डालर का निवेश

नई दिल्ली: इस वर्ष जुलाई-सितंबर में देश के रियल एस्टेट, डाटा सेंटर और हास्पिटैलिटी क्षेत्र में 9.5 अरब डालर का रिकार्ड इक्विटी निवेश हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई के अनुसार, यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में दोगुना से अधिक है। जुलाई-सितंबर 2025 के दौरान इन क्षेत्रों में 4.4 अरब डालर का निवेश हुआ था। सीबीआरई के अनुसार, यह किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निवेश है। कुल निवेश में से 57 प्रतिशत राशि डाटा सेंटर क्षेत्र को मिली है। (प्रेट्र)

आडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सोमवार को कारपोरेट करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) और आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि में 21 दिन की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब कारपोरेट करदाता 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार, आडिट रिपोर्ट 30 सितंबर के बजाय 21 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। नागिया एंड कंपनी एलएलपी के सीनियर पार्टनर अमित अग्रवाल ने कहा कि विभाग ने करदाताओं की चुनौतियों को देखते हुए समय-सीमा में बढ़ोतरी की है। (प्रेट्र)

छह महीने के निचले स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी

कच्चे तेल के दाम में तेजी और वैश्विक अनिश्चितता से सेंसेक्स में 1,124 अंकों की गिरावट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कच्चे तेल के दाम में तेजी, वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक रुख से स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट आई और तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1,124.02 अंक यानी 1.52 प्रतिशत लुढ़क कर 72,771.72 अंक पर बंद हुआ। यह 30 मार्च, 2026 के बाद इसका सबसे निचला बंद स्तर है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 360.25 अंक यानी 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ करीब छह महीने के निचले स्तर 22,780.25 अंक पर बंद हुआ। सिर्फ एक दिन में निवेशकों की संपत्ति करीब आठ लाख करोड़ रुपये घट गई है, जो किसी एक दिन में शेयर बाजार के इतिहास में निवेशकों को लगी सबसे बड़ी चपत में से एक है। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले एक महीने में यह नुकसान 17.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

72,771.72 पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

360 अंक गिरकर 22,780.25 पर आया एनएसई निफ्टी

खास बातें

- विशेषज्ञ शेयर बाजार के निकट भविष्य को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं
- आरबीआइ अक्टूबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरों को बढ़ाने का कर सकता है फैसला
- अगर ऐसा हुआ तो पिछले दो सालों से जारी गिरावट का दौर आगे भी रह सकता है जारी



08 लाख करोड़ रुपये घट गई निवेशकों की संपत्ति

7.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है निवेशकों को एक महीने में

9.5 प्रतिशत की गिरावट आई है सेंसेक्स में पिछले एक साल के दौरान

7.6 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई है एनएसई निफ्टी में एक वर्ष में

निफ्टी में शामिल 50 में से 47 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए

सोमवार को मंदी का दौर चौतरफा रहा। शायद ही कोई सेक्टर हो जिसके शेयरों के भाव नीचे ना आए हों। निफ्टी में शामिल 50 में से 47 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि केवल तीन में बढ़त रही। इससे पता चलता है कि बाजार में बिकवाली व्यापक रही। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 29 में गिरावट रही।

> अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव खारिज करने से पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका बढ़ी है। इससे निकट अवधि में तेल आपूर्ति के लंबे समय तक प्रभावित होने तथा जिस कीमतों में वृद्धि का जोखिम बढ़ा है। अमेरिकी बांड रिटर्न बढ़ने से भारत-अमेरिका के बीच बांड रिटर्न का अंतर कम हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ सकती है। **-हिमांद्र नाथर, रिसर्च हेड,** जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सोना 2,600 तो चांदी 5,000 रुपये गिरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डालर के मजबूत होने के बीच सोमवार को सोने की कीमतें 2,600 रुपये गिरकर 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। चांदी भी शुक्रवार के 2.37 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 5,000 रुपये गिरकर 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अगस्त में औद्योगिक उत्पादन आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत थी। अगस्त 2025 में औद्योगिक उत्पादन 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने कहा कि अगस्त 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) ने साल-दर-साल आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और इसे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के नौ प्रतिशत और इलेक्ट्रिसिटी व गैस सप्लाई सेक्टर के 12.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का समर्थन मिला है। पिछले महीने खनन क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अगस्त 2025 में इसमें 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जुलाई के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत किया गया है।

5जी के महंगे होने से 4जी स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: 5जी स्मार्टफोन के महंगा होने से चालू कैलेंडर वर्ष में 4जी स्मार्टफोन की बिक्री में सुधार का संकेत दिख रहा है। काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 4जी की थोक बिक्री में साल-दर-साल तीन प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। 2025 में 4जी स्मार्टफोन की बिक्री में 48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

कुल बाजार में 4जी स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 2025 के 11 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 13 प्रतिशत और 2027 में अनुमानित 15 प्रतिशत हो सकती है। महंगे कलपुर्जों की लागत बढ़ने से 4जी और 5जी स्मार्टफोन के बीच कीमत का अंतर बढ़ गया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए 5जी स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 10 हजार रुपये से कम और 10-20 हजार रुपये की श्रेणी के उपभोक्ता कम कीमत में जैसे संवेदनशील मार्गों में व्यवधान से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की उपलब्धता उनकी सबसे बड़ी चिंता है और इसके लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।

- थोक बिक्री में साल-दर-साल तीन प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद
- 2025 में 4जी की बिक्री में 48 प्रतिशत की गिरावट आई थी

बेहतर फीचर और अधिक मूल्य के लिए 4जी उपकरण का रुख कर रहे हैं। काउंटरप्वाइंट के मुताबिक कंपनियां इस मांग को पूरा करने और 5जी फोन के महंगे होने से पैदा हुई कमी को भरने के लिए 10-20 हजार रुपये के दायरे में अपने 4जी स्मार्टफोन खेंड का विस्तार कर रही हैं। काउंटरप्वाइंटरिसर्च के शोध निदेशक तरुण पाठक ने कहा, 'यह वृद्धि केवल स्मार्टफोन की ऊंची कीमतों की वजह से आया अल्पकालिक बदलाव नहीं है, बल्कि 4जी की भूमिका में व्यापक बदलाव को दर्शाती है। कलपुर्जों की कीमतें जल्द सामान्य होने के आसार नहीं हैं।

जियो-बीपी, नायरा ने डीजल की खुदरा बिक्री की सीमा तय की

नई दिल्ली, प्रेट्र: जियो-बीपी और नायरा एनर्जी के खुदरा पेट्रोल पंपों से एक निश्चित सीमा से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि औद्योगिक और दूसरे थोक ग्राहक सस्ते खुदरा मूल्य का लाभ उठाने के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए खोले गए पंप से डीजल भरवा रहे हैं, जिसके चलते आपूर्ति और खुदरा नेटवर्क पर दबाव पड़ रहा है।

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जियो-बीप आउटलेट ने डीजल खरीदने की सीमा हर ग्राहक के लिए एक दिन में 50 लीटर तय की है जबकि नायरा एनर्जी ने यह सीमा 70 से 200 लीटर तय की है। माना जा रहा है कि जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी ईंधन की मात्रा पर सीमा तय कर सकती हैं।

होर्मुज बंद रहा तो 120 डालर तक जा सकती हैं कच्चे तेल की कीमतें

- विकवर्क रेटिंग्स के मुताबिक-दूसरी छमाही में क्रूड की औसत कीमत 95-110 डालर रहने की उम्मीद
- रुपया डालर के मुकाबले 94-98 रुपये और खुदरा महंगाई पांच से साढ़े पांच प्रतिशत रहने का अनुमान



नई दिल्ली, प्रेट्र: पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक कच्चे तेल की कीमतें 120 डालर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ब्रिकवर्क रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य स्थिति में दूसरी छमाही में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 95 डालर से 110 डालर प्रति बैरल के बीच रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में इस बात का भी अनुमान लगाया गया है कि इस इलाके में टिकवर्ते आगे भी बनी रहेंगी, जबकि पाइपलाइन और शिपिंग संचालन में स्थिति थोड़ी सुधर सकती है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के रिसर्च हेड राजीव शरण ने कहा, ब्रेंट फ्यूचर्स एक महीने में 20 प्रतिशत बढ़कर 15 सितंबर को लगभग 109 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि प्रतिशत और निफ्टी में 7.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.81 प्रतिशत उछलकर 108.3 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

रूस से कच्चे तेल का आयात पांच महीने के निचले स्तर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय रिफाइनरी कंपनियों द्वारा अपनी खरीद में विविधता लाने से सितंबर में रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो अप्रैल के 15.8 लाख बैरल प्रतिदिन के बाद सबसे कम है। हालांकि, इस दौरान देश का कुल कच्चा तेल आयात औसतन करीब 53 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) रहा। यह अगस्त के छह लाख बीपीडी और सितंबर 2025 के सात लाख बीपीडी से अधिक है।

फिजिकल ब्रेंट 130.80 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया जो कम स्प्लाई का संकेत है। फिजिकल ब्रेंट उस वास्तविक भौतिक कच्चे तेल और उसके हाजिर या फारवर्ड बाजार को कहते हैं, जिसका उतरी सागर से उत्पादन और वास्तविक लेनदेन होता है।

राष्ट्रीय फलक

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति को संभाला

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- केंद्रीय मंत्री के अनुसार, 27 की जगह 41 देशों से खरीद जा रहा कच्चा तेल
- भारत ने विकसित की 5.33 मिलियन टन की रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता



हरदीप पुरी। फाइल फोटो

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और स्ट्रेट आफ होर्मुज में आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बावजूद भारत ने अब तक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन भारत ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी की थी।

कोलकाता में मर्चेंट्स चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए पुरी ने कहा कि भारत अब 27 की जगह 41 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। देश की रिफाइनिंग क्षमता 215 से बढ़कर 267 मिलियन टन सालाना हुई है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 5.33 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसी एक क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने का जोखिम कम हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट में मुख्य समस्या वैश्विक स्तर पर तेल की कमी नहीं, बल्कि आपूर्ति की है। स्ट्रेट आफ होर्मुज

बंगाल में होगा इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन

हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इंडिया एनर्जी वीक 2027 गत संस्करणों की तुलना में इस बार और बड़े स्वरूप में आयोजित होगा। देश के इस सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के पांचवें संस्करण का बंगाल पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। पुरी ने कोलकाता में इसके कर्टेन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि आयोजन से करीब पांच मह पहले ही प्रदर्शनी के लिए करीब 17 हजार वर्ग मीटर जगह की बुकिंग हो चुकी है। इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 28 से 31 जनवरी तक कोलकाता में न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज जुटेंगे।

जम्मू में नकली नोट बनाने का भंडाफोड़, तीन आरोपित दबोचे

जागरण संवाददाता, जम्मू: पुलिस ने सोमवार देर शाम जम्मू में नकली नोट तैयार करने के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट बनाने का पूरा खेल शहर के चौआदी क्षेत्र में एक किराए के मकान में चल रहा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 13,500 रुपये के जाली नोट, स्केनिंग मशीन, प्रिंटर, कंप्यूटर और अन्य सामग्री के साथ एक धारदार हथियार बरामद किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों में विजय साहनी मूल निवासी सिवान, बिहार, राहुल अहिरवार मूल निवासी छतरपुर, मध्य प्रदेश और ईदरपाल कुमार मूल निवासी साहिबगंज, झारखंड शामिल हैं। वर्तमान में तीनों जम्मू में रह रहे थे।

महाराष्ट्र एफडीए ने 30 फूड लाइसेंस को किया निलंबित

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

- संजय राउत ने एफडीए अधिकारियों पर लगाए उगाही के आरोप

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने त्योहारों के मौसम में राज्यभर में की गई कार्रवाई के तहत 23 से 27 सितंबर के बीच 30 फूड लाइसेंस निलंबित किए। उसने 1.19 करोड़ रुपये कीमत का 50,601.78 किलोग्राम फूड स्टाक को जब्त भी किया। सोमवार को एफडीए के एक बयान में कहा गया कि मुंबई में 13, कोंकण में छह, पुणे में आठ और छत्रपति संभाजीनगर में तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित किए गए।

वहीं एफडीए के अधिकारियों पर होटल और विवक कामर्स कंपनियों से कथित उगाही करने का गंभीर आरोप लगा है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे को पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की आड़ में कारोबारियों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं।

संजय राउत ने अपने पत्र में दावा किया है कि बांद्रा स्थित एफडीए मुख्यालय और ठाणे कार्यालय में कथित तौर पर उगाही का खेल चल रहा है। आरोप है कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अनिवार्य नोटिस और सुनवाई की व्यवस्था को दरकिनार कर कारोबारियों पर दबाव बना रहे हैं।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

ट्रम्प यांची अवस्था केविलवाणी

'निमंत्रणाचा नेम!' हे संपादकीय (२८ सप्टेंबर) वाचले. ट्रम्प सारेच शिष्टाचार बाजूला सारून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्या स्वागतास सपत्नीक हजर का राहिले असावेत, या मुद्द्यावर राजकीय मंचावर चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले आहे. यातून अमेरिका-चीन मैत्रीचे नवे पर्व उदयास आल्यास, युक्रेनविरोधात रशिया आणि इराण यांना दिलेला राजकीय मदतीचा हात चीन आखडता घेईल, अशी ट्रम्प यांना आशा असावी.

एका महाशक्तीच्या प्रमुखाने यातील गांभीर्य ओळखणे महत्त्वाचे आहे. पण मिरवण्याच्या नादात ट्रम्प यांची अवस्था मोदींसारखीच झाली. व्हाइट हाऊसमध्ये सीएनएनवर घातलेली बंदी उठवावी लागणे हे ट्रम्प यांच्या राजनैतिक कौशल्याची पिसे काढणारे आहे. या बाबतीत मात्र त्यांना मोदींना मात देता आलेली नाही. शंभर टक्के आयात शुल्कावर जिनपिंग यांनी मौन बाळगले असले, तरी ट्रम्प यांनी मात्र चीनच्या भूमीत आढळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांबाबत सामंजस्याने पावले टाकली. व्यापाराच्या क्षेत्रात ट्रम्प यांनी चिनी राष्ट्राध्यक्षांसमोर पायघड्या घातल्या. आजवरच्या अमेरिकी राष्ट्रपतींच्या इतिहासात असा केविलवाणा प्रसंग कधीही घडला नसावा.

■ **डॉ. नूतनकुमार पाटणी,** चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

जिनपिंग यांची धूर्त खेळी

'निमंत्रणाचा नेम!' हा अग्रलेख वाचला. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या भूमीवर जाऊन 'कोण ट्रम्प', असा जो पवित्रा घेतला तो वाखाणण्याजोगाच आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुराभिमानाला ते चोख प्रत्युत्तर ठरले. रशिया विरुद्ध युक्रेन, इस्रायल विरुद्ध इराण हा संघर्ष संपता संपेना झाला आहे. ट्रम्प यांची अवस्था दोघांच्या भांडणात अडकल्यासारखी झाली आहे.

■ **सुनील समडोळीकर,** कोल्हापूर

संस्था बळकट राहणे महत्त्वाचे

'''जंतर-मंतर २.०'च्या रेट्याची प्रतीक्षा... ' हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. कोणत्याही समृद्ध लोकशाहीचा पाया हा तिचे संविधान आणि त्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या स्वतंत्र, घटनात्मक संस्थांवर आधारलेला असतो. निवडणूक आयोग ही अशीच एक स्वायत्त संस्था आहे, जिच्यावर देशातील संपूर्ण मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी असते. निवडणुकांसारख्या प्रचंड व्याप्ती असलेल्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे आक्षेप किंवा शंका असणे हे लोकशाहीत नैसर्गिक आहे. परंतु या शंकांचे निरसन करण्यासाठी संविधानाने योग्य ती कायदेशीर चौकट आणि न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत. ठोस पुराव्यांसह न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याऐवजी, केवळ राजकीय हेतूने किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी रस्त्यावर उतरून अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.

संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आणि राजकीय पक्षाला आंदोलनाचा हक्क दिला आहे, यात शंका नाही. मात्र या आंदोलनांचा उद्देश संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा असावा की लोकांचा या यंत्रणांवरील विश्वास उडवणे, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. जर प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर किंवा राजकीय अपयशानंतर केवळ आरोपांची राळ उठवून संस्थांना लक्ष्य केले गेले, तर सामान्य जनतेचा संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेवरूनच विश्वास उडू शकतो. न्यायालयात कायदेशीर लढा न लढता, केवळ जनमताचा दबाव आणण्याच्या नावाखाली संस्थांची प्रतिमा मलिन करणे म्हणजे लोकशाहीच्या पायावरच आघात करण्यासारखे आहे. कारण लोकशाहीत संस्था बळकट राहिल्या तरच देश मजबूत राहतो.

■ **क्षितिज महाजन,** विठ्ठलनगर (बीड)

सरकार बदलण्याचा अधिकार आयोगालाच

'''जंतर-मंतर २.०'च्या रेट्याची प्रतीक्षा... ' हा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. मतदानाचा मूलभूत अधिकार हा तर एका लोकशाही राष्ट्रात सर्वांत महत्त्वाचा असतो, मात्र निवडणूक आयोगाच्या एकतर्फी वागण्याने, मतदार यादीत फेरफार, एसआयआरचा वापर करून मतदारांना हटवणे, नवमतदारांचे अधिकार हिरावून घेणे यामुळे कितीही ठरवले तरी मतदार सरकार बदलूच शकणार नाहीत, कारण सरकार ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाकडेच केंद्रित झालेला आहे.

जेन झी, विद्यार्थ्यांचे महिनाभर चाललेले जंतर-मंतरवरील आंदोलन चांगलेच तापले व जगभरात त्याची नोंद घेतली गेली. सीजेपीच्या आंदोलनात विद्यार्थी, जनतेचा प्रचंड सहभाग, विद्यार्थ्यांना देशभरातून, जगभरातून मिळणारा पाठिंबा, तसेच जनतेने ज्याप्रकारे निर्भीडपणे रस्त्यावर उतरून पोलिसांना व सरकारला न घाबरता अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन केले त्यावरून जनतेच्या मनातील सरकारची भीती गेल्याचे दिसून आले. त्यात भर म्हणून मतदानासारख्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असताना व निवडणुकीतील गैरव्यवहार ज्याप्रकारे समोर आले त्यावरून संतप्त जनता आता नक्कीच 'जंतर-मंतर २.०' ची आतुरतेने वाट पाहताना दिसते.

■ **सई खैरे,** नाशिक

केवळ कोणाची तरी जिरवण्यासाठी?

नुकताच गणेशोत्सव पार पडला. यावर्षी चर्चेत विषय होता तो पुण्याचे बापट आणि डीजे, डॉल्बीच्या दणदणाटाचा. शांतताप्रेमी नागरिकांच्या समस्यांना बापट यांनी सामाजिक आवाज दिला, त्यामुळे यावर्षी अनेक ठिकाणी डीजे, डॉल्बी वर बंदी घातली गेली, मात्र पुण्यातील पोलिसांनी ढणढणाटाला मुक्त परवानगी दिल्याचे दिसले. त्यामुळेच पुण्यात तब्बल ३४-३५ तास विसर्जन मिरवणूक सुरू होती. या काळात प्रचंड ध्वनिप्रदूषण करत रस्ते अडवले गेले. विसर्जन मिरवणुकीत बापटांची हेटाळणी करणारे 'कशी जिरवली' असे फलकदेखील झळकत होते हा नाहक डिवचण्याचा प्रकार नेमका कशासाठी केला गेला? आवाजाचा त्रास पोलिसांनादेखील होत होता. नागपुरात एका पोलीस अधिकाऱ्याचा अतिताणामुळे मृत्यू झाला. धार्मिकतेच्या नावाखाली होणाऱ्या धांगडधिंग्याला रोखण्याची कोणाचीच इच्छा वा मानसिकता दिसली नाही. कायदे, नियम, अटी-शर्ती या जणू पाळण्यासाठी नसतात अशा आविर्भावात काही जण धार्मिक सण उत्सव साजरे करतात. सामाजिक जबाबदारीचे भान बाळगण्याची कोणालाच गरज वाटत नाही. कुणाची तरी जिरवण्यासाठी उत्सव साजरे केले जाणे अयोग्य.

■ **अनंत बोरसे,** शहापूर (ठाणे)

छठपूजेसाठीही कृत्रिम तलाव हवेत

गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महापालिकेने केलेल्या कृत्रिम तलावांच्या सुविधेमुळे चौपाट्यांवरील विसर्जन काही प्रमाणात कमी झाले आहे. याच धर्तीवर छठपूजेच्या वेळीही महापालिकेकडून काही ठिकाणी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था केली जाते. मात्र ही सुविधा अधिकाधिक ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. समुद्रकिनारी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर होणारी गर्दी व त्यामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून भाविकांना या पर्यायी व्यवस्थेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करावे.

■ **दीपक गुंडये,** वरळी

दुष्काळग्रस्तांसाठी वेतनावर पाणी सोडाल?

राज्यात विरोधी पक्षात असंबद्ध बडबड करणारे नेते आहेतच पण त्यापेक्षा अधिक हास्यास्पद आणि काही वेळा लज्जास्पद वक्तव्ये करणारे नेते मंत्रिमंडळात आणि सत्ताधारी पक्षात आहेत. दर दहा-पंधरा दिवसांनी याचा एकतरी नमुना सादर केला जातोच. 'राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने लग्न साध्या पद्धतीने करा.

करोनाकाळात साध्या पद्धतीने लग्न झालेल्यांनाही मुले झालीत,' असे विचित्र वक्तव्य अहिल्यानगर येथे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतेच केले. आता, लग्न कशा पद्धतीने झाले, किती खर्च झाला, यावर मुले होणे न होणे अवलंबून असते असे विखे पाटील यांना कुणी सांगितले? दुष्काळी परिस्थिती असल्याने लग्न साध्या पद्धतीने करण्याची सूचना अयोग्य नाही पण त्यापुढील वाक्य गरजेचे नव्हते. त्याऐवजी राज्यातील आमदार वर्ष-सहा महिने वेतन घेणार नाहीत असे विखे पाटील म्हणाले असते तर ते योग्य ठरले असते, पण ड्रायफ्रुट खात खात दुष्काळावर चर्चा करणाऱ्यांकडून तशी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थच. राज्याच्या प्रमुख नेत्यांकडूनही मंत्रिमंडळातील आणि स्वपक्षीय नेत्यांना वेसण घालण्याचे काम होईल अशी अपेक्षाही व्यर्थच.

■ **मनमोहन रोगे,** ठाणे

ईपीएफ सुधारणेतून सामाजिक सुरक्षेकडे...

ईपीएफओ वेतन मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कामगारांना आकस्मिक संकटाच्या परिस्थितीत किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येईल असा निधी मिळावा, ते कर्जाच्या विळख्यात सापडू नयेत हाच विचार या संपूर्ण व्यवस्थेचा गाभा आहे...

पहिली बाजू

व्ही. अनंथ नागेश्वरन, श्रुती सिंग

कामगार आणि कारागिरांचा गौरव करणाऱ्या विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) वेतन मर्यादेत सुधारणा करून ती दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. खरे तर ही सुधारणा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की, वेतन मर्यादेत केवळ दहा हजार रुपयांची वाढ झाल्याने नेमके काय बदलणार आहे? या सुधारणेची गरज काय होती? आणि या निर्णयाचा कामगारावर किंवा नियोक्त्यांवर कसा परिणाम होणार आहे? हीच बाब समजून घेण्यासाठी आपण अगदी मूलभूत बाबींपासून सुरुवात करू या.

२५ हजार रुपयांची ही वैधानिक वेतन मर्यादा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (ईडीएलआय- एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्युरन्स) या तीन योजनांच्या अनिवार्य संरक्षणासाठीची पायाभूत पातळी ठरणार आहे. या तीन योजना भारतातील वेतनावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा गाभा आहेत. निवृत्ती किंवा आकस्मिक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठीचा निधी, नियोक्त्यांच्या योगदानातून उभी राहणारी आणि निवृत्तीनंतर कामगारांना ठरावीक निधी देण्यासंबंधीची निवृत्तिवेतन योजना आणि मृत्यू ओढावल्यास कुटुंबाला आधार देण्यासाठी मालकाच्या योगदानातून चालणारी जीवन विमा योजना, अशा विविध माध्यमांतून ही सामाजिक सुरक्षा पुरवली जाते. खरे तर वेतन, किमान वेतन आणि दैनंदिन जगण्याचा खर्च सतत वाढतो आहे, अशा वेळी २०१४ पासून एकाच मर्यादेत गोठवलेल्या आकड्यांवरच संरक्षणाची ही व्यवस्था टिकवून ठेवणे योग्य नव्हतेच.

यापूर्वीच्या मर्यादेनुसार, दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर रुजू होणारा कोणताही नवा कर्मचारी अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या संरक्षणातून वगळला जात असे, कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेसाठी अपात्र ठरत असे आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या संरक्षणाच्या बाहेरच राहात असे. काळाच्या ओघात ज्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे वेतन या मर्यादेपलीकडे गेले, त्यांना मिळणारे संरक्षण कायम राहिले, मात्र कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तिवेतनयोग्य वेतन मात्र १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवरच अडकून पडलेले होते. आता यासंदर्भात जास्त वेतन असलेले कर्मचारी स्वेच्छेने संरक्षणाचा पर्याय निवडू शकत होते असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतोच. मात्र स्वेच्छेने नोंदणी करण्यासाठी संयुक्त पर्यायाअंतर्गत नियोक्त्यांची संमती आवश्यक होती. त्यामुळे या संरक्षणाची हमी मिळण्याऐवजी हे संरक्षण वाटाघाटींचा विषय झाला. मात्र आता या वाढवलेल्या वेतन मर्यादेमुळे हे संरक्षण हा वैधानिक अधिकार ठरला आहे.

वाढवलेल्या मर्यादेमुळे कामगारांच्या सर्वच अडचणी सुटणार आहेत असेही नाही, पण त्यामुळे औपचारिक सुरक्षेच्या कवचाला अधिक न्याय्य आणि थोडे अधिक व्यापक स्वरूप नक्कीच मिळू शकणार आहे. यामुळे ५१ लाख अतिरिक्त कामगार सामाजिक सुरक्षा कवचाअंतर्गत येणार आहेत, आणि ही निश्चितच लहान संख्या नाही. या वाढीमुळे मिळणारे लाभ मिळवण्यासाठी कामगाराला स्वतःहून काहीही करावे लागत नाही.



खरे तर आपल्या भविष्याचे नियोजन करण्यात माणसे कमीच पडतात. कोणीही आपण वयाच्या पासष्टीला पोहचलो आहोत, अशा दृष्टिकोनातून स्वतःसाठी आर्थिक नियोजन करताना दिसत नाही. बहुतेकांचा कल हा भविष्यात मिळणाऱ्या मोठ्या लाभापेक्षा अल्पावधीत मिळणाऱ्या छोट्या लाभांकडेच असतो. याच सवयीला वर्तन अर्थशास्त्रात हायपरबोलिक डिस्काउंटिंग म्हणतात. म्हणूनच तर, मर्यादित उत्पन्नात, तात्कालिक गरजा भागवण्यापेक्षा आपल्या भविष्यातील आयुष्यासाठी- स्वतःसाठी बचत करणे आणि नियोजन करणे अनेकदा अधिक कठीण जाते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर ईपीएफओसारख्या यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या अनिवार्य स्वरूपाच्या सामाजिक संरक्षण योगदानाची व्यवस्था महत्त्वाची आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था कामगारांच्या बचत करण्याच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून न राहता राबवली जाते ही सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. कामगारांचे उत्पन्न त्यांच्या खात्यात पोहोचण्याआधीच निवृत्तिवेतनचे योगदान बाजूला काढले जाते. स्वाभाविकपणे जे कधी दिसतच नाही त्यामुळे ते खर्चही करता येत नाही. आणि हळूहळू, दरमहा, वेतनाचा एक छोटा भाग बाजूला काढला जातो, त्यातूनच या कामगारांच्या निवृत्तीसाठीचा निधी उभा राहतो. या निधीचा वापर त्यांना आकस्मिक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत करता येतो, यासोबतच जीवन विमा संरक्षणाचे कवचही मिळते. महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांनी स्वतःहून काहीही वेगळे न करता हे सगळे घडते.

अर्थात आता मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात केलेल्या सुधारणेमुळे नियोक्त्यांवरील खर्चाचा भार वाढला आहे. अनिवार्य मर्यादा वाढवली असल्याने नियोक्त्यांना अधिक मोठ्या मनुष्यबळाला ईपीएफचे संरक्षण द्यावे लागणार आहे, स्वाभाविकपणे त्यांच्या मासिक योगदानाचे दायित्वही वाढणार आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण दरमहा २२ हजार रुपये कमावणाऱ्या आणि आधी अनिवार्य संरक्षणाबाहेर असलेल्या एका कामगाराचे उदाहरण घेऊ या. आता नियोक्त्यांना या कर्मचाऱ्याला कायदेशीररीत्या हे संरक्षण द्यावेच लागणार आहे. या संरक्षणापोटी नियोक्त्यांना कामगारांच्या वेतनाच्या १२ टक्के योगदान द्यावे लागते. हे योगदान नंतर कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना आणि कर्मचाऱ्याच्या स्वतःच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात विभागले जाते. म्हणजेच प्रति कर्मचारी दरमहा दोन हजार ६४० रुपये किंवा वर्षाला ३१ हजार ६८० रुपये इतक्या प्रमाणात. अशा २० कर्मचाऱ्यांमागे वर्षाला सहा लाख ३३ हजार ६०० रुपयांचा अतिरिक्त वेतनखर्च येतो. यात कर्मचारी ठेव संलग्न विम्याच्या योगदानाची भर पडते. अर्थात तुलनेने या योगदानाचे प्रमाण लहान असले तरी या सुधारणेनंतर मात्र ते उच्च वेतनाच्या आधारावर मोजले जात आहे.

आता यावरून कंपनीसाठीचा खर्च वाढला असल्याचा ढोबळ निष्कर्ष काढला जाऊ शकतोच. पण नीट पाहिले तर हा केवळ प्राथमिक टप्प्यावरील परिणाम आहे आणि रोजगार बाजारपेठ ही प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक बहुआयामी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे व्यापक संरक्षण म्हणजे तितक्याच प्रमाणात नोकरभरतीही होत असल्याचा एक सकारात्मक संकेतच आहे. यामुळे नवे उमेदवार आपल्या नोकरीचे मूल्यमापन केवळ मासिक वेतनापुरता विचार न करता त्यापलीकडच्या लाभांचाही विचार करतात, परिणामी अधिक कुशल आणि अधिक उत्पादक कामगार रोजगाराच्या बाजारपेठेकडे वळतात. या संरक्षणामुळे कामगार टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. निवृत्तिवेतन आणि विमा संरक्षण असलेला कामगार अधिक काळ टिकून राहण्याची शक्यता तर वाढेलच, त्याबरोबरच अधिक सुरक्षिततेसह आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात करण्याची संधीही त्यांना मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे दूरदृष्टी असलेल्या नियोक्त्यांनी या गोष्टीची दखल आधीपासूनच घेतलेली असते आणि आपल्याकडे अधिक कुशल मनुष्यबळ यावे यासाठी ते स्वेच्छेने अशा प्रकारच्या संरक्षणाचा लाभ देतात.

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ही एखाद्या ट्रॅम्पोलिनसारखी (ज्यावर उडी मारल्यावर माणूस पुन्हा उंच उसळी घेतो अशा स्प्रिंगांच्या चौकटीला जोडलेल्या ताणलेल्या लवचीक कापडाचे) काम करते. जेव्हा तुम्ही पडता तेव्हा ही व्यवस्था केवळ तुम्हाला झेलतच नाही, तर तुम्हाला पुन्हा उसळी घेण्यासाठीही सक्षम करते. खरे तर कामगारांना आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही संकटाच्या परिस्थितीत किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येईल असा निधी मिळावा आणि त्यांच्यावरचे ते तात्पुरते संकट त्यांच्या आयुष्यातले कायमचे संकट होऊ नये, ते कर्जाच्या विळख्यात सापडू नयेत हाच विचार या संपूर्ण व्यवस्थेचा गाभा आहे.

देशातल्या आरोग्यसेवा क्षेत्राला अधिक परवडणारे आणि सहज उपलब्ध असलेले स्वरूप मिळवून देणारे 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'सारखे उपक्रम या संरक्षणाच्या व्यवस्थेला बळ देणारे आहेत. आज रोजगारांचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे आणि त्या दृष्टीने आपण सज्ज रहणे गरजेचे आहे. यासाठी कौशल्यवृद्धी, पुनर्कौशल्य आणि नवकौशल्यांच्या बाबतीत उद्योग क्षेत्राची भक्कम नाळ जोडलेली असेल अशी कौशल्यविषयक परिसंस्थाही देशात उभारली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर 'अटल निवृत्तिवेतन योजने'च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा धोका पत्करण्यास तसेच आर्थिक आणि बाजारपेठांच्या विकासाचे वाटेकरी होण्यासाठी तयार असलेल्यांकरिता, योगदानावर आधारित निवृत्तिवेतनाच्या संरक्षणाचे कवच उत्पन्नाच्या आणखी खालच्या स्तरापर्यंत झिरपणार आहे. थोडक्यात सामाजिक संरक्षणरूपी हे ट्रॅम्पोलिन एक एक स्प्रिंग जोडत अधिक भक्कम केले जात आहे.

(व्ही. अनंथ नागेश्वरन हे भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत आणि श्रुती सिंग या भारतीय आर्थिक सेवेतील अधिकारी आहेत.)

कुतूहल

सीटबेल्ट का वापरावेत?

गाडीत बसल्यावर इंजिन सुरू करण्यापूर्वी आपण सर्वप्रथम सीटबेल्ट लावतो, नाही का? पण तो का लावतो? अनेकांना तो केवळ वाहतुकीचा एक नियम वाटतो. प्रत्यक्षात मात्र सीटबेल्ट हा आपल्या जिवाचं रक्षण करणारा सर्वात महत्त्वाचा सुरक्षा साथीदार आहे. अपघाताच्या वेळी तो गंभीर दुखापतीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करतो आणि अनेकदा प्राणही वाचवतो. हे कसं घडतं ते समजून घेऊ या.



गाडी वेगात असताना आपलं शरीरही त्याच वेगानं पुढे जात असतं. अचानक ब्रेक लागला किंवा अपघात झाला, तर शरीर पुढे फेकलं जाऊन डॅशबोर्ड किंवा काचेवर आदळू शकतं. सीटबेल्ट आपल्याला सीटवर घट्ट धरून ठेवतो आणि गंभीर दुखापतीपासून संरक्षण करतो. तसंच, आजच्या गाड्यांमधील एअरबॅग सीटबेल्टच्या जोडीनं काम करण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. त्यामुळे सीटबेल्ट लावला असेल, तरच एअरबॅग योग्य संरक्षण देतात. म्हणून 'एअरबॅग आहे, मग सीटबेल्ट कशाला?' हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे.

एक मोठा गैरसमज म्हणजे मागे बसलेल्या प्रवाशांनी सीटबेल्ट लावण्याची गरज नसते. प्रत्यक्षात मागच्या सीटवर बसलेल्यांनाही तितकाच धोका असतो. अपघाताच्या वेळी मागचा प्रवासी जोरानं पुढे फेकला जातो. तो पुढच्या सीटवर किंवा पुढच्या प्रवाशावर आदळू शकतो. म्हणून पुढे आणि मागे बसलेल्या प्रत्येकानं सीटबेल्ट लावणं तितकंच आवश्यक आहे. लहान मुलांसाठी तर अधिक काळजी घ्यावी लागते. त्यांना मोठ्यांसारखा साधा सीटबेल्ट पुरेसा सुरक्षित नसतो. त्यांच्या वयानुसार आणि उंचीनुसार योग्य 'चाइल्ड सीट' वापरणं अधिक सुरक्षित ठरतं.

सीटबेल्टचं तंत्रज्ञानही खूप रंजक आहे. तुम्ही बेल्ट हळू ओढलात तर तो सहज बाहेर येतो. पण झटक्याने ओढला, तर तो लगेच अडकतो. कारण त्यामध्ये एक विशेष लॉकिंग यंत्रणा असते. गाडीला अचानक धक्का बसला किंवा जोरात ब्रेक लागला, की ही यंत्रणा क्षणार्धात कार्यरत होते. त्यामुळे बेल्ट पुढे सरकत नाही आणि प्रवाशाला सीटवर घट्ट धरून ठेवतो.

आजच्या काही आधुनिक गाड्यांमध्ये अधिक स्मार्ट सीटबेल्ट वापरले जातात. यात 'प्री-टेन्शनर' अपघाताच्या वेळी बेल्ट घट्ट करतो तर 'लोड लिमिटर' आवश्यक तेव्हा शरीरावरील दाब कमी करतो. काही प्रगत गाड्यांमध्ये 'इन्फ्लेटेबल सीटबेल्ट' आणि 'व्हायब्रेशन अलर्ट'सारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्येही उपलब्ध असतात. थोडक्यात सांगायचं तर सीटबेल्ट ही केवळ कायद्याची अट नसून जीवनाची हमी आहे. गाडीत पुढे बसला असाल किंवा मागे, प्रत्येकाने सीटबेल्ट लावलाच पाहिजे. ही एक छोटी सवय अपघात टाळू शकत नाही, पण अपघातात आपले प्राण मात्र नक्की वाचवू शकते.

– **गिरीश घाटे**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

त्यांना करू दे तत्त्वावर काम!

*'**काय गरज** होती त्या निलाच्या विजयावर प्रतिक्रिया द्यायची? आपण भाजपत गेलो म्हणजे सगळ्या जगावर भाष्य करण्याचा अधिकार मिळाला असे समजण्याचे कारणच काय? आपटलो ना तोंडावर. आता स्पष्टीकरणे देत फिरावे लागतेय सर्वत्र. यांच्या भावकीत भांडणे आहेत हा संदेश सर्वदूर गेला तो वेगळाच.' रागाने फणफणत असलेले वडील ताडताड बोलत होते व मुलगा मान खाली घालून गपगुमान ऐकत होता. 'घराण्याचे नाव झाले म्हणून मी फक्त तिचे अभिनंदन केले. तेवढा तर अधिकार आहे ना मला.' हे ऐकताच ते आणखी खवळले. 'अरे, नुसते अभिनंदन करून तू थांबला थोडीच. इकडे पराभव झाला तरी तिकडे विजय झाला असे म्हणायची काय गरज होती? जणू काही तूच गेला होता तिच्या प्रचाराला. शेवटी मारला ना तिने टोला, तुमच्यासारखी पक्षबदलू नाही म्हणून. काय इज्जत राहिली आपली? त्या काँग्रेसवाल्यांनी म्हटले तर एक वेळ सहन करून घेता येईल पण आपल्याच घरातली एक मुलगी म्हणते, यासारखा दुसरा अपमान नाही.*

अरे, जगात कुठे होत नाही असे राजकारण केवळ भारतात होते. त्यात टिकून राहत आपले साम्राज्य सांभाळायचे असेल तर सत्तेच्या वळचणीशिवाय पर्याय नाही. इथे ज्याच्या हाती सत्ता तोच यशस्वी. हे सूत्र राबवायचे असेल तर तत्त्वांना मुरड घालावीच लागते. स्वीडनसारख्या विकसित देशातले राजकारण तत्त्वावर चालणारे. हे ठाऊक असूनही तिच्या विजयाच्या बातमीत नाक खुपसायची गरज काय होती? तिच्या टोमण्यामुळे आपल्या घराण्यातली एक पाती अजून तत्त्वनिष्ठ आहे असा प्रचार झाला ना नाहक. यातून आपली तत्त्वहीनता उघडी पडली त्याचे काय? तिच्या प्रत्युत्तरानंतर 'आम्ही फलक लावले काय? सत्कार घेतला काय?' असे बोलायची गरज नव्हती. तू असाच वाद वाढवत नेला तर ती घरातला कलह आणखी चव्हाट्यावर आणेल हेही तुझ्या लक्षात आले नाही काय?' बोलता बोलता धाप लागल्याने ते थांबले.

संधी साधून तो बोलता झाला. 'चुकले माझे. मी नंतरची प्रतिक्रिया द्यायला नको होती. पण तिनेही मोठे मन दाखवून शुभेच्छांचा स्वीकार केला असता तर मूठ झाकली राहिली असती. शेवटी घराण्याची प्रतिष्ठा सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वांचीच असते की!' ऐकून ते पुन्हा चिडले. 'अरे, ते आधीच दुखावलेले. वार करण्याची संधी कशाला सोडतील. हे साधे आकलन तुला होत नाही म्हणजे कमालच झाली. किमान आता तरी पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर ये. जगाची चिंता सोड व मतदारसंघाकडे लक्ष दे. प्रतिक्रिया देण्याची एवढीच हौस असेल तर देशातल्या घडामोडींवर बोलत जा. आपण हाती घेतलेला हिंदुत्ववादाचा वसा कसा पुढे नेता येईल त्यावर विचार कर व पाहिजे तेवढे आक्रमक बोल. तो संग्राम बघ किती पुढे निघून गेलाय. तू आपला लंके लंकेच करत बसलायस. भविष्यात सत्तेच्या राजकारणात टिकायचे असेल तर आक्रमक धर्मवादी अशी प्रतिमा निर्माण कर. तो स्वीडन काय, इवलासा देश. करू दे तिला तिथे तत्त्वावर काम. तू निवडून आलास की तुझ्या तोंडचे काहीही खपून जाईल. हीच रीत आपल्या देशाची. आता तिचा विषय बंद.' एवढे बोलून ते दुष्काळी दौऱ्यावर निघाले. नंतर सहज म्हणून त्याने समाजमाध्यम उघडले तर त्यावर एक कॉमेंट होती. 'जे न देखे सुजय विखे, ते देखे निला विखे.' वाचून त्याने रागारागाने फोनच बंद केला.

राजवाडे विचारविश्व

पाटण येथील मराठी शिलालेख

राजवाडे यांच्या अभिलेखसंशोधनाचा आढावा घेताना ज्या शिलालेखाची आवर्जून सविस्तर दखल घेतलीच पाहिजे असा अभिलेख म्हणजे पाटण येथील शक ११२८मधील (इसवी सन १२०६ मधला) मराठी शिलालेख होय. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातील एक विख्यात प्राच्यविद्यापंडित डॉ. भाऊ दाजी लाड ह्यांनी तो शिलालेख इ.स. १८६४ मध्येच प्रकाशात आणला होता, तथापि त्या शिलालेखातील मराठी मजकूर नीट वाचता न आल्यामुळे बऱ्याच चुका झाल्या आहेत, हे अभ्यासकांच्या लक्षात आले होते. 'एपिग्राफिया इंडिका'च्या पहिल्या खंडामध्ये त्याची दोन छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. त्यावरून दुसरे जर्मन विद्वान डॉ. लोरेन्झ फ्रान्झ किलहॉर्न (Dr. Lorenz Franz Kielhorn) यांनी काही दुरुस्त्या करून तो पुन्हा छापला होता. तरीदेखील त्या शिलालेखाचे समाधानकारक वाचन झालेले नाही, असे वाटल्यावरून राजवाड्यांनी ती जबाबदारी स्वयंप्रेरणेने स्वीकारली आणि १९०६ साली धुळ्याच्या 'प्रभात'मधून आपला प्रदीर्घ लेख त्यांनी प्रसिद्ध केला.

शिलालेखाची पार्श्वभूमी व प्राथमिक माहिती देत त्यांनी लिहिले, 'खानदेशांतल्या चाळीसगांव तालुक्यांत डोंगरखपाटींत पाटण नांवाचे एक उद्ध्वस्त शहर आहे. शालिवाहनाच्या अकराव्या व बाराव्या शतकांत निकुंभनामक राजांची ती राजधानी होती. शहराची लांबी दोन मैल व रुंदी दीड मैल असावी. शहरालगत एक प्रचंड डोंगरी किल्ला असून ते तीन बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले होते. शहर डोंगराच्या खपाटींत व माचीवर वसले असल्याकारणाने, त्याच्यामधून अनेक ओढे वाहत होते. पैकी एक ओढा सर्वांत मोठा असून, त्याच्या कांठी प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय ज्योतिषी जो भास्कराचार्य त्याचा नातू जो चांगदेव त्याने आपल्या आजाचे ग्रंथ पढण्याकरितां एक मठ शके ११२८च्या पूर्वी केव्हातरी बांधला असावा. ११२८मध्ये पाटणास हेमाडिदेव नावाचा निकुंभ राजा राज्य करीत होता. त्याने त्या मठाच्या योगक्षेमाकरितां जे उत्पन्न करून दिले, त्याचा निर्देश प्रस्तुत शिलालेखांत केला आहे. शिलालेख सरासरी अडीच फूट रुंद व दीड फूट उंच आहे. पुढे आणखी काही लिहावयाचे राहिले नसावे, असे मजकुराच्या पूर्णतेवरून वाटते...शिलालेखाच्या २६ ओळींपैकी सबंध २१ ओळी व २२व्या ओळीतली पहिली पाच अक्षरे इतका मजकूर संस्कृतमध्ये आहे. पुढे २६व्या ओळीच्या शेवटपर्यंतचा मजकूर मराठीत आहे. त्या मराठी मजकुराशीच सध्या आपल्याला कर्तव्य आहे...'

आपला मर्यादित हेतू स्पष्ट करताना राजवाड्यांनी त्यामागचे कारण सांगितले, ते महत्त्वाचे होते. जेमतेम काही ओळींच्या मराठी मजकुराचा अर्थ व अन्वयार्थ लावायला आपण का प्रवृत्त झालो, ते स्पष्ट व्हावे म्हणून त्यांनी लिहिले, 'डॉ. भाऊ दाजीला हा मराठी भाग नीट वाचता आला नाही. मजकूर मराठी- जुना मराठी- आहे, हे त्याला कळले होते; परंतु अक्षरे नीट न लागल्यामुळे व ज्ञानेश्वरकालीन मराठी भाषेशी परिचय जसा असावा तसा नसल्यामुळे, त्याला अर्थ कळला नाही व शब्द नीट तोडता आले नाहीत. कीलहार्नने भाऊ दाजीपेक्षा मजकूर बराच नीट वाचला, परंतु जुन्या मराठीशी परिचय नसल्यामुळे शब्द तोडण्यात त्याच्याकडून काही चुका झाल्या आहेत, शिवाय काही अक्षरेहि त्याला नीट लागली नाहीत. भाषा बिलकूल येत नसता कोणताहि शिलालेख वाचण्यांत पुराण्यांत पुराणाक्षरवाचनपटुत्वाची खरोखरच परीक्षा होण्याचा प्रसंग येतो. भाऊ दाजी व कीलहार्न ह्या दोघांनी शिलालेखाचा हा मराठी भाग कसा वाचला, ते या दोघांनी केलेले उतारे खाली देऊन दाखवितो व मी प्रत्यक्ष शिळेवरून घेतलेला उतारा तुलनेकरिता शेवटी देतो...'

नंतर भाऊ दाजींनी वाचलेल्या मजकुराचा सलग एका परिच्छेदाचा उतारा तसेच किलहॉर्नचा सहा ओळींगणिक परिच्छेद पाडलेला अधिक व्यवस्थित उतारा राजवाड्यांनी दिला आणि पाठोपाठ फेब्रुवारी १९०६त स्वतः केलेला उताराही दिला... तो अधिक नीटनेटका असल्याचे सहज स्पष्ट होत होते.

– **आनंद हर्डीकर**
anand47.hardikar@gmail.com

बदल बरवे... बापट!

सुधारणा सुचवणाऱ्याने त्यांच्या पालनाचा आग्रह धरायचा नसतो. शहाणपण कशात ते सांगायचे. समोरच्याने ऐकले तर ऐकले. नाही तर तो आणि त्याचे 'नशीब'!

हे बापट फार रागावलेले दिसतात. सध्या उभ्या- आणि आडव्याही- महाराष्ट्रात दखल घ्यावी असे एकच एक बापट आहेत. इतिहासात ते सेनापती होते. इतिहासानंतर वर्तमानापर्यंतच्या बेचक्यात या बापटांचा वसंत फुलून त्यांनी कविता-बिविता लिहिल्या. वर्तमानात मात्र ते विद्यानंद बनून मूढ जनांस मार्गदर्शन वगैरे करू पाहतात. बापटांतील हा बदल महाराष्ट्रातील सामाजिक बदलती परिस्थिती दाखवतो. तो होणे अपरिहार्य. सर्वच बदलत असताना सामाजिक परिस्थितीही बदलणारच. हा बदल वर्तमानातील विद्यानंद बापटांनी लक्षात घेतलेला नसावा. तो घेतला असता तर ते असे त्रागा करते ना. जनसामान्यांच्या आरोग्यासाठी, स्वास्थ्यासाठी इतके मूलगामी विचार आपण मांडतो, त्यासाठी बहुमताचा रोष पत्करतो, लोकप्रिय भावभावनांविरोधात जाण्याचा धोका पत्करतो आणि तरीही ज्यांच्यासाठी हे आपण करतो त्यांना काही फिकीर नसावी हे पाहून बापटांच्या हृदयास घरे पडणे साहजिक. त्यामुळेच लोक किती अक्कलशून्य आहेत, सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धक लावणाऱ्यांचा मेंदू गुडघ्यातच काय, घोट्यातही नसतो इत्यादी शेलकी विशेषणे वाहून त्यांनी आपला सात्त्विक संताप व्यक्त केला. तसे करण्याची गरज वाटणे नैसर्गिक. बुद्धिदात्या गणेशास ११ दिवस पुजल्यानंतरही काही फरक पडत नाही असे लक्षात आल्यानंतर त्यांचे विसर्जन करताना काही मंडळांनी बापटांची दृकश्राव्य माध्यमांतून जाहीर टिंगल केली. त्यामुळे बापटांस राग आला. या मंडळांवर अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशारा त्यामुळे ते देते झाले. अशा अब्रूनुकसानी दाव्यांचा दांडगा अनुभव असल्याने या बापटांस चार शब्द सुनावणे 'लोकसत्ता'चे कर्तव्यच.

अहो बापट... हे जरा अतिच झाले म्हणायचे. शहाणपणाचा सल्ला देणे आणि तो संबंधितांकडून प्रत्यक्षात येणे या दोन भिन्न बाबी आहेत, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. हा असा सल्ला गंभीर आजारावरील औषधासारखा जीवनावश्यक नसतो. त्यामुळे डॉक्टरांकडून दिल्या जाणाऱ्या गोळ्या-औषधांप्रमाणे तो लगेच घेतला जाईल आणि लगोलग गुण दिसेल, असे होण्याची शक्यता नाही. आणि अहो बापट, तुम्ही सल्ला तरी कोणता देताय? आणि कोणास? ज्या पुण्यात पेठापेठांतील नाक्यानाक्यांवर महामहोपाध्याय एका 'कटिंग'वर ज्ञानाचा रतीब घालत असतात आणि तेथील अरुंद रस्त्यांवर या वाहत्या ज्ञानगंगेमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असतो त्या पुण्यात तुम्ही 'आवाज कमी करा' असे सांगताच कसे? तुम्ही पुणेकरांस सल्ला देण्याच्या फंदात पडलात आणि तिथेच उघडे पडलात. तोपर्यंत तुम्हास समस्त महाराष्ट्र पुणेकर मानत होता. तुमचे रूपही पुणेकर म्हणवून घेण्याजोगे. त्यात घारे डोळे. म्हणजे मिसळच्या (कमी तिखट) तर्रीवर तूपच जणू! असे पुणेकर म्हणवून घेण्यासाठी सर्व काही जेथल्या तेथे असताना तुम्ही पुणेकरांस सल्ला दिला आणि पुणेकर नाही हे सिद्ध करून बसलात. न्यूयॉर्कचे महापौर, रशियाचे अध्यक्ष, हार्वर्डचे कुलगुरू, ऑक्सफर्डचे रसायनशास्त्रप्रमुख इत्यादी इत्यादींस अनुक्रमे शहर नियोजन, साम्यवाद का फसला, पीएचडीचे प्रबंधलेखन, बेन्झीन रिंगांचा अमोनिया संयुगांवर होणारा परिणाम वगैरे वगैरे अनेक मुद्द्यांवर पुणेकर सल्ला देतील. मार्गदर्शनही करतील. पण पुणेकर कधीही स्वनगरबांधवांस कसलाही सल्ला देत नाहीत. तसे करणे किती अव्यापारेषु व्यापार हे त्यांस ठावकी असते. पण तुम्हांस ते कळले नाही. पुणेकरांस मार्गदर्शन करायला गेलात आणि स्वतःचे अ-पुणेपण दाखवून बसलात. असो. जे झाले ते झाले. पण त्यातून तुमची शोभा झाली.

...आणि काय हो बापट, पुण्यातील गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुका ३०-३० तास चालतात म्हणून नाराजी कसली व्यक्त करता? या मिरवणुकांतील ध्वनिकल्लोळाने कासावीस काय होता? देशाचे भवितव्य वगैरे असलेला तरुण वर्ग या मिरवणुकांत वेळ वाया घालवतो म्हणून अस्वस्थ होताच कसे तुम्ही? या मिरवणुकांत नाचण्यात, बोंबलण्यात वेळ नाही घालवायचा तर मग उद्याच्या या भारतभाग्यविधात्यांनी करायचे तरी काय? आपले कुलदीपक/ दीपिका या मिरवणुकांत मंडळ-चरणी सेवा अर्पण करतात, स्थानिक नगरसेवकादी महानुभाव त्यांना त्यांच्या प्रतिमेच्या वस्त्रप्रावरणांनी (पक्षीः टीशर्ट) सन्मानित करतात हे पाहून त्यांच्या पालकांस काय धन्य धन्य वाटते याची बापट तुम्हास कल्पना नाही. एरवी गावचे (किंवा पेठेतील) उकिरडे फुंकत हिंडणारे आपले कार्टे/ कार्टी या निमित्ताने बऱ्या कपड्यांत काही करत असतील तर त्यांच्या पालकांचा ऊर अभिमानाने दाटून येत असेल. परत; दुसरे बरे आणि स्वतःचे काही दाखवण्यास 'या ठिकाणी' नसल्यामुळे 'त्या ठिकाणी' विसर्जन मिरवणुका थेट प्रक्षेपित थेट करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांमुळे या आपल्या सुपुत्र/ सुपुत्रींचे नृत्यकौशल्य सर्वदूर जात असेल याचाही अभिमान या पालकांस असणार. हे तरुण/ तरुणी आपले बहुमूल्य ३०-४० तास या मिरवणुकांत खर्ची घालतात हेदेखील या बापट आणि अन्य तत्समांस अमान्य. या अशा लांबलेल्या मिरवणुकांमुळे शहरी व्यवस्थेवर म्हणे ताण येतो. बापट... तुम्ही अगदीच 'हे' आहात. अहो... हे तरुण/ तरुणी ३०-४० तास रस्त्यांवर असतात हे खरे, शहरी व्यवस्था ताणली जाते हेही खरे. पण अहो नंतर हे तरुण/ तरुणी यापेक्षाही अधिक काळ आराम फर्मावतात; त्यामुळे ते घराबाहेरच पडत नाही आणि पडले असले तर घरी परतत नाहीत, त्यामुळे रस्त्यावरची वाहतूक-गर्दी कमी होते त्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करता. चंद्राचे चांदणे न पाहता त्यावरील डाग तेवढे पाहायचे हे शोभत नाही तुम्हांस बापट!

> ...हे बापटांच्या लक्षात कसे येत नाही? अब्रूनुकसानीचे दावे त्या मंडळांवर कसले करायचे? याच पुण्यात जिवंतपणी प्रेतयात्रा निघाल्यानंतरही सुधारकाग्रणी आगरकर शांतच होते, हेही आठवत नाही?

तुमच्यामुळे संस्कृतीचा अपमान होतो असे तुमचे टीकाकार म्हणतात. बरोबर आहे त्यांचे. अहो तुम्हास कळत कसे नाही... धर्म, देश, संस्कृती हे अभिमान मिरवणाऱ्यांचे 'लो हँगिंग फ्रूट्स'. म्हणजे बुटक्यांतील बुटक्यांससुद्धा तोडता येतील इतक्या 'उंची'वर फळे लागतात ती झाडे. बापट तुम्ही बहुश्रुत आहात असे 'हे जे आहेत' ते वृत्तनिवेदक म्हणतात. अर्थात वृत्तनिवेदकांच्या प्रमाणपत्रांस किती गांभीर्याने घ्यावे हे तुम्हास कळत असेलच. त्यांनी तुम्हास दिलेल्या प्रमाणपत्रावर विसंबायचे तर आर्थर शोपनहॉअर या जर्मन तत्त्वचिंतकाबद्दल तुम्हास विचारायला हवे. तुम्हास तो माहीत असेलच. ''इतरांस अभिमानाने दाखवावे असे स्वकर्तृत्वाने मिळवलेले ज्याच्या ठायी नसते ती व्यक्ती देशप्रेम इत्यादी मिरवते. कारण ते सगळ्यात स्वस्त असते'', असे हा शोपनहॉअर म्हणून गेला. तेव्हा या असल्या गोंगाटात, दणदणाटात 'गर्व से कहो...' अभिमान बाळगणारे दुसरे काय करू शकणार? तेव्हा दुर्लक्ष करा त्यांच्याकडे बापट.

राहता राहिला मुद्दा अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा. तुमची बदनामी केली म्हणून काही मंडळांवर तुम्ही खटला भरणार आहात म्हणे. खरे की काय? हे खरे असले तर तुमच्या शहाणपणावर उगाच विश्वास ठेवला म्हणायचे! अहो बापट तुमची टिंगल करणारी ध्वनिचित्रफीत काय ती फक्त काही मंडळांनी दाखवली. पण याच पुण्यात साधारण १३५ वर्षांपूर्वी याच पुणेकरांनी गोपाळ गणेश आगरकर यांची त्यांच्या डोळ्यादेखत अंत्ययात्रा काढली होती, हा इतिहास आहे बापट. तुम्हास माहीत असेलच. त्या वेळी गोपाळरावांनी हे कृत्य करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. दावा वगैरे ठोकला नाही त्यांच्याविरोधात. गोपाळरावांना माहिती होते इतिहासात आपली नोंद होणार आहे, या प्रतिगाम्यांची नव्हे. तेव्हा तुम्ही या फंदात पडू नका.

सुधारणा सुचवणाऱ्याने त्यांच्या पालनाचा आग्रह धरायचा नसतो. शहाणपण कशात ते सांगायचे. समोरच्याने ऐकले तर ऐकले. नाही तर तो आणि त्याचे 'नशीब'. चांगले बदल बरवे असतात... ते सहज होत नाहीत बापट...!

कामकाज लोकांच्या नजरेआड कशासाठी?

लेख

ॲड. प्रतीक राजूरकर
prateekrajurkar@gmail.com

> या प्रश्नाला व्यापक संदर्भ आहेच, पण न्यायपालिकेच्या संदर्भातही हा प्रश्न आला तेव्हा २६ सप्टेंबर २०२२ पासून २४ जुलै २०२६ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच भूमिकांमध्ये असा कोणता फरक पडला, याची माहिती (प्रकरणाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वीसुद्धा) जाणून घेणे गरजेचे आहे... कारण या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचा निकाल कसा येतो, यावर सार्वजनिक जीवनातील 'खुलेपणा'च्या व्याख्याही ठरत राहणार आहेत...

'**न्यायालयीन कामकाजाचे** थेट प्रक्षेपण हा जनतेचा अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकार' अशा अर्थाचा निकाल २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ('स्वप्निल त्रिपाठी वि. सर्वोच्च न्यायालय' या प्रकरणात) दिला. कालांतराने जगभरात कोविड आपत्ती फैलावली आणि न्यायालयांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कामकाज सुरू केले. मग कोविडच्या सरत्या काळात, न्यायालयांनी स्वप्निल त्रिपाठी प्रकरणातील निकालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आणि तसे धोरण प्रत्यक्षात आले. घटनापीठांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज अनुभवण्याचे जनतेचे स्वप्न पूर्णत्वास गेले. मात्र २०२६ साली हर्षिता ग्रोव्हर यांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जुलैच्या आदेशानुसार न्यायालयीन कामकाजाचे कुठल्याही प्रकारे ध्वनिमुद्रण अथवा छायाचित्रण वापरण्यास प्रतिबंध केला. अनुच्छेद २१ मध्ये अभिप्रेत असलेला अधिकार कायम ठेवूनही आम्ही ही स्थगिती देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून त्यामुळे, न्यायालयाचे कामकाज प्रसारमाध्यमांवरून थेट प्रक्षेपित होऊ शकत नाही. असे का झाले?

स्वप्निल त्रिपाठी प्रकरण

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निकाल दिला होता. स्वप्निल त्रिपाठी यांच्या याचिकेसह इतर तीन याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली, त्या याचिकांमध्ये न्यायालयीन कामकाज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपित व्हावे अशी विनंती होती. यावर २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी याचिकेत दोन स्वतंत्र निकाल देण्यात आले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. खानविलकर यांचा एकत्रित निकाल व न्या. चंद्रचूड यांचा स्वतंत्र निकाल अशा एकंदर १०६ पानांच्या निकालाने न्यायालयीन प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांनी प्रक्षेपणाची प्रक्रिया, कॅमेराचा रोख याविषयी विविध निर्देश दिले. लैंगिक अत्याचार, वैवाहिक न्यायालयीन वाद, अल्पवयीनांची प्रकरणाचे थेट प्रक्षेपण वगळण्यात येतील असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते. न्या. खानविलकर यांच्या निकालपत्रात अन्य देशांतील न्यायालयीन प्रकरणांच्या होणाऱ्या थेट प्रक्षेपणांचा आढावा आहे. त्या त्या देशातील प्रक्षेपणाचे नियम, कायदे यांचाही संक्षिप्त आढावा न्या. खानविलकर यांनी घेतला आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४५ चा (न्यायालयाचे नियम न्यायालयानेच ठरवण्याबाबत) संदर्भ देऊन या दोन्ही निकालांनी थेट प्रक्षेपणाला परवानगी दिली. निकाल, सुनावणी ही खुल्या न्यायालयात व्हावी असे अपेक्षित असण्याकडे लक्ष वेधले आहे. 'खुले न्यायालय' याची व्याख्या विशद करताना न्या. चंद्रचूड यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ३२७ व दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५३-ब चे विश्लेषण केले. न्यायालयीन कामकाज व होणारे थेट प्रक्षेपण यात दहा मिनिटांचे अंतर असावे अशी अपेक्षा न्या. खानविलकर यांच्या निकालात आहे; तर न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालात हे अंतर दोन मिनिटांचे असावे असे म्हटले आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचा उल्लेख 'खुली न्यायव्यवस्था' असा करून, न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण ही आदर्श पद्धती कशी ठरेल याचे विश्लेषण केले. त्यांच्याही निकालात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भ नमूद आहेत. भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची व स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची आकडेवारी मांडताना न्यायालयांनीसुद्धा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा पुरस्कार केला. लैंगिक अत्याचार, वैवाहिक न्यायालयीन वाद, अल्पवयीनांची प्रकरणे यांचे थेट प्रक्षेपण वगळण्यात यावे, याचा पुनरुच्चार न्या. चंद्रचूड यांच्या स्वतंत्र निकालात आढळतो.

भलती प्रसिद्धी

न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाची सुरुवात २७ सप्टेंबर २०२२ पासून झाली. त्या दिवशी 'सुभाष देसाई वि. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधिमंडळ', 'आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण' व 'ऑल इंडिया बार एग्झामिनेशन' या तीन प्रकरणांचे कामकाज प्रक्षेपित झाले. मात्र गेल्या चार वर्षांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात काही अप्रिय प्रसंग घडले. तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर वकिलानेच जोडे फेकण्याचा प्रयत्न, कधी अशिलांचे अयोग्य वर्तन, १० जुलै २०२६ रोजी एका अशिलाने न्या. विश्वनाथन व न्या. आराध्ये यांच्या समक्ष अर्वाच्य भाषा वापरून केलेले गैरवर्तन, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या तोंडी 'कॉक्रोच' या शब्दाने समाजमाध्यमात प्रचंड वाद... अशा मोजक्या आणि न्यायालयीन कामकाजाऐवजी भलत्याच ठरणाऱ्या घटनांचे चित्रीकरण वेगाने पसरले. वास्तविक कोणत्याही थेट प्रक्षेपणादरम्यान काही दुर्दैवी प्रसंग घडू शकतातच. पण बातम्या समाजमाध्यमांवरून 'पाहिल्या' जाण्याच्या काळात 'व्हायरल' काय होणार यावरच काहींचा भर असावा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे २०२४ साली पाठदुखीने त्रस्त असताना त्यांनी बसण्याची पद्धत बदलली, त्यावरही त्यांना या थेट प्रक्षेपणाच्या आधारानेच लक्ष्य करण्याचा प्रकार घडला. उपलब्ध असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रणांचे समाजमाध्यमात झालेले विद्रूपीकरण अत्यंत अशोभनीय होते यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

पूर्वपरवानगीची अट

हर्षिता ग्रोव्हर या 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या माजी पत्रकार आणि त्यानंतर नीती आयोग, लोकसभा टीव्ही आदींसाठी काम करणाऱ्या माध्यमकर्मी. त्यांनी जून २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रण वापरण्यास नियमावली, मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत, अशी मागणी करण्यात आली. 'न्यायालयीन कामकाजाच्या छायाचित्रणाचा स्वैर गैरवापर न्यायालयीन प्रतिष्ठेला बाधक' असल्याचे हर्षिता ग्रोव्हर यांनी याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका दाखल करून घेऊन २४ जुलै २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जायमाल्य बागची व न्या. मोहना यांच्या न्यायपीठाने न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रण कोणालाही वापरण्यास प्रतिबंध करणारा अंतरिम आदेश दिला. याच प्रकरणात सुनावणी सुरू असताना न्या. बागची यांनी 'न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाबद्दल पुनर्विचार होणे गरजेचे' अशा अर्थाचे तोंडी मतही व्यक्त केले आणि बहुधा या सरसकट बंदीच्या समर्थनार्थ, 'न्यायालये ही २४ तास मनोरंजनाचे माध्यम नाहीत' असेही विधान त्यांनी केले. याचिकेतील मुद्द्यांना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सरकारतर्फे पाठिंबा दिलाच, शिवाय न्यायालयीन कामकाज प्रक्षेपणाला तात्पुरती स्थगिती द्या, अशी मागणीही मेहतांनीच केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली ती यानंतर. त्यामुळे माध्यमांना आता न्यायालयीन कामकाजाचे छायाचित्रण पूर्वपरवानगीशिवाय वापरता येत नाही.

'पूर्वपरवानगी' जाचकच

हर्षिता ग्रोव्हर प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत अंजली भारद्वाज व अमृता जोहरी यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला- म्हणजे, आमचेही मत जाणून घ्या/ ऐका असा अर्ज. हा अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला आहे. भारद्वाज व जोहरी यांच्या मते हा विषय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पारदर्शक न्याय तसेच माहितीच्या अधिकाराशी निगडित असल्याने तो व्यापक स्वरूपाचा आहे. संविधानातील केवळ अनुच्छेद २१ मधल्या जीवितस्वातंत्र्याशीच नव्हे, तर अनुच्छेद १९ (१)(अ) मधल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात माहिती व मतांचा जो मुक्त प्रवाह अपेक्षित आहे, त्या मूलभूत अधिकाराशीही 'पूर्वपरवानगी'ची अट सुसंगत नाही. अशी परवानगी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (रजिस्ट्रार जनरल अथवा सेक्रेटरी जनरल) मर्जीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे याचिकेतील विषय स्थगितीऐवजी योग्य पद्धतीने हाताळता येऊ शकतो. हा हस्तक्षेप अर्जही दाखल करून घेऊन न्यायालयाने, सूचना मांडण्यास परवानगी दिली आहे. 'समाजमाध्यम आणि तंत्रज्ञानाचा आजचा वापर बघता व्यावसायिक पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील रेषा बहुतांशी पुसली गेली आहे.

मान्यताप्राप्त माध्यमे आणि मान्यता नसलेली माध्यमे असा भेदभाव ठोस कायद्याच्या अभावी करता येणे अशक्य आहे' असेही प्रतिपादन हस्तक्षेप अर्जात आहे, हे विशेष!

व्यापक प्रश्न

न्यायालयीन कामकाजाच्या चित्रीकरणाचा गैरवापर करणाऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचेच आहे याबाबत कुठलेही दुमत नाही. परंतु सरसकट स्थगिती हा पर्याय सांविधानिक ठरू शकतो का?

आज प्रत्येक नागरिकाच्या हाती मोबाइल फोन आले आहेत. मुंबई, गुजरात व इतर काही उच्च न्यायालयांनी शासकीय कामकाजाचे, अधिकाऱ्यांचे छायाचित्रण करण्याचे सामान्य नागरिकांचे अधिकार अनेकदा अधोरेखित केले आहेत. न्यायालयीन कामकाज आणि शासकीय अधिकारी यांच्यातील तुलना करता येणार नाही, परंतु समानतेच्या निकषावर वस्तुस्थितीची कायदेशीर चिकित्सा होणे अपेक्षित आहे. देशाच्या कायदेमंडळाचे थेट प्रक्षेपण होते, देशाचा प्रत्येक नागरिक त्याला याबाबत माहिती नसूनही घराबाहेर पडल्यावर सीसीटीव्हीच्या टप्प्यात असतो. या पार्श्वभूमीवर खुला, पारदर्शक न्याय होत असताना त्यावर प्रतिबंध सांविधानिक निकषावर कितपत ग्राह्य धरला जाईल?

प्रश्न गंभीर आहेतच पण वैचारिकता अवघ्या चार वर्षांत बदलते कशी, हाही मुद्दा आहे. चार वर्षांपूर्वी- ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोणाला तरी मोबाइल फोनने न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रीकरण करताना बघितले, एका क्षणी त्यांच्या मनात विचार आला की ही व्यक्ती असे कसे चित्रीकरण करू शकते, परंतु दुसऱ्याच क्षणी त्यांच्या लक्षात आले ठीक आहे तसेही हे खुले न्यायालय आहे, इथे काहीच गोपनीय नाही! - ही माहिती न्या. चंद्रचूड यांच्या हवाल्याने माध्यमांनी प्रसारित केली होती. या व्यापक विचारावर सध्या न्यायालयाकडूनच मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत. त्या कायम राहतात की अधिक व्यापक होतात हे हर्षिता ग्रोव्हर प्रकरणाचा अंतिम निकाल आल्यावरच स्पष्ट होईल.

अन्वयार्थ

'लव्हली' संस्थानाची आलबेल अफवा!

'**लव्हली प्रोफेशनल** युनिव्हर्सिटी'चे वर्ग पुढले दहा दिवस बंद, त्या काळात होणारी परीक्षाही रद्द आणि या खासगी विद्यापीठाच्या वसतिगृहांत राहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'आतच राहा' असा आदेशवजा सल्ला... अशी सामसूम आता पसरलेली आहे. त्याआधीचे २२ तास या आवारात आणि त्यालगतच्या महामार्गावर घोषणाबाजी, रास्तारोको आणि ठिय्या, जाळपोळ, मोडतोड, काहीजणांकडून लूटसुद्धा आणि पोलिसी लाठीमार असे हिंसक वातावरण होते. कारण घडले ते पंजाबच्या फगवाडा शहरातील या विद्यापीठात एका मुलीवर विद्यापीठाबाहेरील कुणा इसमाने अतिप्रसंग केला आणि विद्यापीठ प्रशासनाने हा प्रकार दडवून ठेवून त्या मुलीलाच बाहेर काढले, अशा कथित अफवेचे. ही अफवा अर्थात समाजमाध्यमांवरून पसरली. अशीच अफवा चंडीगड-पतियाळ महामार्गावरल्या 'चित्कारा युनिव्हर्सिटी' या खासगी विद्यापीठात अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी पसरल्याने तिथल्या विद्यार्थ्यांनीही असंतोष व्यक्त केला होता, त्यापेक्षा 'लव्हली'तला असंतोष हिंसक. कदाचित तो हिंसक असल्यामुळेच, प्रशासन 'अफवा' ठरवत असलेल्या कथित बलात्काराबद्दल पोलिसांनी गुन्ह्याची खबर (एफआयआर) नोंदवली आणि 'विशेष तपास पथक'सुद्धा स्थापन केले. त्याआधी सलग काही तास घडत राहिलेल्या हिंसाचाराचे समर्थन कुणीही केलेले नाही, करूही नये- पण झाल्या प्रकाराचा निषेध करणाऱ्यांनी राजकीय हिशेब चुकते करण्याची संधी सोडली नाही. सध्या माध्यमांत सुरू आहे ते 'दोन खासगी विद्यापीठांत हे प्रकार घडवण्यामागे कुणाचा हात?' या वळणाचे चर्वितचर्वण. या गदारोळात, विद्यार्थी इतके अस्वस्थ कशामुळे आहेत - त्यांना काय म्हणायचे आहे, काय सांगायचे आहे- हे मुद्दे गौणच ठरणार की काय?

मुलीवर अत्याचार झाला, असे काही विद्यार्थी सांगतात. 'अत्याचार झाला नाही' असे विद्यापीठ-पुरस्कृत व्हीडिओत सांगणाऱ्या मुलींनीही 'असे बोलण्यास आम्हाला प्रशासनाने सांगितले' असे म्हटल्याचे वृत्त आहे. पण हा मुद्दा केवळ एका मुलीवरल्या अत्याचारापुरता नव्हता. या विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी आत्महत्या केल्या, तेव्हा तीही प्रकरणे दडपण्यात आली असा आरोप अनेक विद्यार्थी आता कॅमेऱ्यांसमोर करताहेत. 'इथे प्राध्यापकापेक्षा सुरक्षा रक्षकांचा रुबाब अधिक'- असेही म्हणताहेत. दाबलेली वाफ बाहेर पडावी तसे परवाच्या आंदोलनावेळी घडले.

अखेर हे खासगी विद्यापीठ. म्हणजे स्वतःच्या प्रतिमेवर, 'रेटिंग'वर त्यांचा व्यवसाय अवलंबून असणारे संस्थानच! 'आम्हीच हा रोबोटिक कुत्रा निर्माण केला' असे धडधडीत असत्यकथन करणारी अन्य कुणा खासगी विद्यापीठाची प्रसिद्धीप्रमुख हे या प्रतिमा-संवर्धन खटाटोपाचे एक टोक असेल, तर दुसरे टोक हे 'नकारात्मक काहीच नको' असे असणारच. ते किती वेळा गाठले जाते आणि त्यामुळे किती गळचेपी होते यांतला फरक फक्त तपशिलाचा.

विद्यार्थ्यांची ही खदखद रास्त असली तरी इतक्या हिंसक थराला जावे का, हा प्रश्न योग्यच. पण त्याची उत्तरेही आजकाल जटिल झालेली आहेत...२०२०च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात घुसून मोडतोड करणाऱ्या पोलिसांपासून ते दिल्लीतल्याच २०२६ च्या 'जंतर मंतर आंदोलना'च्या वेळी पेलेट गोळीबाराचा आदेश कोणी दिला हे दडवणाऱ्या यंत्रणांपर्यंत; आणि कुणाच्याही तोंडी काहीही बोल घालू शकणाऱ्या 'डीपफेक' पासून ते विद्यार्थिनींना इन्कार करणे भाग पाडणाऱ्या प्रशासनापर्यंत असा हा सगळा जटिल प्रदेश गेल्या काही वर्षांत तयार झाला आणि याच प्रदेशातून 'जेन-झी'ला वाटचाल करावी लागणार आहे. फक्त 'लव्हली' विद्यापीठाबद्दलच बोलायचे तर 'हिंसाचार बाहेरच्यांनीच केला- त्यापैकी काहीजणांनी वसतिगृहांत घुसून फोन, आयपॅडही लुटले' असे सांगणारे विद्यार्थी खरे की 'पोलिसांच्या पाच गाड्या जाळल्या गेल्या' असे सांगणारे पोलीस खरे, हे ठरायचे तेव्हा ठरेल. तोवर 'आता कॉक्रोच जनता पार्टी गप्प कशी?' किंवा 'सत्ताधारी 'आप'नेच विद्यार्थ्यांना भडकवण्याचे उद्योग केले'- असे समाजमाध्यमी राजकारण होत राहील. या 'लव्हली' विद्यापीठाचे संस्थापक-कुलपती राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल हे मूळचे 'आप'चे, पण एप्रिल २०२६ पासून राघव चड्ढांसह भाजपवासी. 'आम्हालाच लक्ष्य केले जाते' हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यात भाजप वाकबगार. पण मित्तल यांच्या सत्तासंबंधामुळे दहा दिवसांनंतर या 'लव्हली' विद्यापीठात सारे काही आलबेल दिसल्यास नवल नाही. एरवीही 'सगळे सकारात्मक दिशेनेच' असल्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवला जातोच की!

इंजिनीअरिंग, फार्मसी प्रवेशांसाठी बारावी, सीईटीच्या गुणांना समान महत्त्व?

विश्लेषण

चिन्मय पाटणकर
chinmay.patankar@expressindia.com

> अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बारावीचे गुण आणि सीईटीचे पर्सेंटाइल एकत्रित विचारात घेण्याबाबत धोरण आखण्याची शक्यता पडताळण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली; त्याबद्दल...

समितीचे स्वरूप काय आहे?

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी गुणवत्ता यादी निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये आवश्यक बदल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या आयुक्तांनी २ सप्टेंबर रोजी शासनास सादर केला. त्या अनुषंगाने या प्रवेशांसाठी राज्याच्या सामाईक प्रवेशपूर्व परीक्षेचे अर्थात 'एमएचटी-सीईटी'चे पर्सेंटाइल, बारावी परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी यांचा विचार करून गुणवत्तायादी निश्चित करण्याचे धोरण ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवाल सादर करण्यास १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.

समितीची कार्यकक्षा काय?

प्रवेशासाठी बारावी परीक्षेतील शैक्षणिक कामगिरी आणि एमएचटी-सीईटी परीक्षेतील कामगिरीला योग्य प्रमाणात महत्त्व देऊन गुणवत्ता यादी निश्चित करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे; अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र या दोन्ही परीक्षांच्या निकालांमध्ये समतोल साधता येईल, गुणानुक्रम निश्चित करण्याची पद्धत पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ व सर्व उमेदवारांसाठी समतोल राहण्यास मदत होईल, या उद्देशाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी सीईटी कक्षाद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता यादीसाठी बारावीचे गुण, सीईटीतील पर्सेंटाइल प्रमाण निश्चित करणे; बारावीचे गुण आणि सीईटीतील पर्सेंटाइल याचे प्रमाण गृहीत धरून गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचा सकारात्मक विचार झाल्यास बारावी आणि 'सीईटी'ची तयारी करण्यास उमेदवारांना पुरेसा अवधी राहील याचा विचार करून त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करता येईल, याची शिफारस करणे या बाबी समितीने कराव्यात, असे नमूद आहे.

यातून बारावीच्या गुणांना महत्त्व मिळेल?

यंदाच्या एमएचटी-सीईटी प्रवेश प्रक्रियेत काही विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेत कमी गुण असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे केवळ एमएचटी-सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश मिळवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. केवळ अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमासाठी आयआयटी, एनआयटीसारख्या केंद्रीय संस्थांतील प्रवेशासाठी बारावीला किमान ७५ टक्के गुण मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांना तितकेसे महत्त्व नाही. औषधनिर्माणशास्त्रासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पीसीएम गटात ५० टक्के, तर राखीव प्रवर्गासाठी ४५ टक्के, अभियांत्रिकीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पीसीएम गटात ४५ टक्के, तर राखीव प्रवर्गासाठी ४० टक्के एवढीच अट आहे. त्यामुळे या गुणांचे फारसे महत्त्वच विद्यार्थ्यांच्या लेखी उरलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, सीईटीच्या पर्सेंटाइलसह बारावीच्या गुणांचे महत्त्व विचारात घेण्याबाबत धोरण ठरवण्याचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा उद्देश असल्याचे दिसून येते.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

'समिती नेमण्याचा निर्णय सकारात्मक आहे. बारावीचे गुण आणि सीईटीच्या गुणांना समान महत्त्व असावे किंवा बारावीला किमान ६० टक्के अनिवार्य असणे अशा काही उपाययोजना करता येऊ शकतात,' असे तज्ज्ञ मार्गदर्शक हरीश बुटले यांनी सांगितले. 'विद्यार्थी सीईटीसाठी शिकवणी लावतात, खर्च करतात. मात्र, त्यात बारावीच्या परीक्षेचे गांभीर्यच राहत नाही. दोन वर्षांचे महाविद्यालयीन शिक्षण वाया जाते. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेचे महत्त्व टिकण्यासाठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व दिले पाहिजे. बारावी व सीईटीचे ५०-५० टक्के गुण विचारात घेतले जावेत,' असे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.

संपादकीय

मणिपूरची आग विझणार कधी?

मणिपूर जळत आहे, हे वाक्य आता बातमी राहिलेले नाही, तर ते अंगवळणी पडले आहे. हिंसेची सवय होणे ही सर्वात मोठी धोक्याची घंटा असते. मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात २६०हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे आणि सुमारे ६० हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारने सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा म्हणजेच 'अफस्पा'ला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. हा कायदा सैनिकांना शोध, अटक आणि गोळीबाराचे व्यापक अधिकार देतो. वर्षानुवर्षे 'अफस्पा' लागू असूनही शांतता प्रस्थापित होत नाही, याचा अर्थ तो उपाय नसून, केवळ लक्षणांवरचा उपचार आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे संघर्षाचे स्वरूपच बदलले आहे. आजवर संघर्ष प्रामुख्याने मैतेई आणि कुकी-झो यांच्यात सुरू होता; पण आता नागा-कुकी-झो संघर्ष सुरू झाला आहे आणि मैतेई-कुकी संघर्षही संपलेला नाही. एप्रिलमध्ये विष्णुपूरमधील बॉम्बस्फोटात दोन लहान मुले मारली गेली आणि पुन्हा हिंसा उसळली. म्हणजे एक आग पूर्ण विझण्याआधीच दुसरी पेटली आहे. फेब्रुवारीत उखरूलच्या लितान गावातील एका वादाचे रूपांतर दोन्ही समुदायांनी एकमेकांची घरे जाळण्यात झाले. हे घडले वर्षभराच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर सत्तेत आलेल्या खेमचंद सिंह सरकारच्या पहिल्याच आठवड्यात! नव्या राजवटीत शांततेचा मार्ग खुला होणे अपेक्षित होते; उलट फेब्रुवारीपासून उफाळलेल्या नव्या संघर्षात ४० पेक्षा जास्त बळी गेल्याचे वृत्त आहे. एकट्या सप्टेंबरमध्येच किमान १३ जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या गुरुवारी कामजोंग जिल्ह्यात म्यानमार सीमेजवळील पिलोंग गावात पितापुत्रासह चार तांगखुल नागा नागरिक मारले गेले. त्यानंतरच्या दोन दिवसांतच सेनापतीत आणखी दोन नागा नागरिकांची हत्या झाली. या सहा नागा नागरिकांच्या अपहरण आणि हत्येचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे आहे. दोषींवर कारवाईचे आश्वासन मिळाले आहे; पण ते प्रत्यक्षात कधी येणार? पोलिसांना हिंसाचारासाठी म्यानमारमधील बंडखोर गटावर संशय आहे, तर नागा संघटना कुकी गटांना जबाबदार धरतात. तीन वर्षांनंतरही व्यवस्थेकडे उत्तरे नसणे, हेच राज्यसंस्थेच्या अपयशाचे सर्वात स्पष्ट लक्षण आहे. जमीन, ओळख आणि प्रतिनिधित्व हे या संघर्षामागील मूळ प्रश्न आहेत. राजकीय तोडग्याशिवाय हे सुटू शकत नाहीत. बलपूर्वक दडपले, की ते अधिक जहाल रूपात परत येतात. जखमा तीन आहेत आणि तिन्हींवर मलमपट्टी झालेली नाही. पहिली म्हणजे लुटलेली शस्त्रे! तीन वर्षांपूर्वी लूट झालेल्या सहा हजारांहून अधिक शस्त्रांपैकी सुमारे अडीच हजारच परत मिळाल्याचे वृत्त आहे. उरलेली कोणाच्या हातात आहेत, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. दुसरी जखम म्हणजे 'सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स' करार! त्या अंतर्गत छावण्यांमध्ये राहणे अपेक्षित असलेल्या गटांचे बंडखोर हिंसाचारात सहभागी असल्याचा आरोप असून, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी नागा संघटना करत आहेत. हा करार केवळ कागदावरच आहे का, हा प्रश्न टाळता येणार नाही. तिसरी जखम सीमेची! सीमापार अस्थिरता व शस्त्रांचा प्रवाह, ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे. त्याची किंमत सामान्य माणूस मोजतो आहे. प्रत्येकच समुदायाला असुरक्षित असल्याचे वाटते आणि म्हणून प्रत्येक समुदाय आपापले ग्राम स्वयंसेवक उभे करतो. सुरक्षेचे असे खासगीकरण झाले, की राज्यावरचा विश्वास संपतो. संयुक्त नागा परिषदेने तीन महिन्यांहून जास्त चाललेली नाकेबंदी २६ सप्टेंबरला तात्पुरती स्थगित केली; पण त्याचे सुमारास हत्या सुरूच होत्या. संवाद सुरू झाला, की हिंसा थांबते, हा भ्रम ठरला आहे. नाकेबंदी उठणे आणि हिंसा थांबणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडाव्या लागतात आणि त्यासाठी दोन्ही बाजूंना जबाबदार धरणारी यंत्रणा हवी. गुवाहाटीतील त्रिपक्षीय चर्चेसारखे प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत; पण ते प्रत्येक हत्याकांडानंतरची प्रतिक्रिया ठरू नयेत. सर्व समुदायांना सामावून घेणारी कालबद्ध राजकीय प्रक्रिया, शस्त्रे परत घेण्याची पारदर्शक मोहीम, प्रत्येक हत्येचा निकाल लागेपर्यंत खटला चालवण्याची हमी आणि सीमेवर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे. सरकार कोणाचीही बाजू घेत नाही, असे प्रत्येक समुदायाला वाटले पाहिजे. ईशान्येकडील राज्ये, नागा शांतता प्रक्रिया आणि म्यानमारमधील अस्थिरता एकमेकांशी जोडलेली आहे. मणिपूर केवळ नकाशावरचा एक कोपरा नाही, तर तो देशाच्या संघराज्यीय वचनाची कसोटी आहे. तीन वर्षे उलटूनही उत्तर सैन्याच्या विशेषाधिकारांच्या मुदतवाढीत शोधले जात आहे. हे उत्तर नसून, अपयशाची कबुली असल्याचे मान्य करण्याची वेळ आली आहे.

ज्ञानेश कुमार, तत्काळ खुर्ची खाली करा!

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देणे केवळ अपेक्षित नाही, तर आवश्यक आहे. जनतेच्या शंका दूर करण्यासाठी केवळ निवेदन पुरेसे नाही.



कपिल सिब्बल
ज्येष्ठ विधिज्ञ, राज्यसभा सदस्य



भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांसारख्या घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या पदावरील कार्यकाळात फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती यांना अनुक्रमे राज्यघटनेतील कलम ६१, ९२४(४) आणि २९८ मध्ये नमूद केलेल्या विशेष प्रक्रियेद्वारे पदावरून दूर करता येते.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्तींना लागू असलेल्या प्रक्रियेसारखीच आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना फौजदारी कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण राज्यघटनेने दिलेले नाही. असे असतानाही केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कालावधी) कायदा केला. या कायद्याने ९९१९ च्या आधीच्या कायद्याची जागा घेतली. या नव्या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरील कार्यकाळापुरतेच नव्हे, तर त्यानंतरही फौजदारी कारवाई सुरू करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

अशा संरक्षणामागे दोन संभाव्य कारणे असू शकतात. एक म्हणजे, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक दायित्व पार पाडताना त्यांच्यावर कोणत्याही बाह्य दबावाचा प्रभाव पडू नये. दुसरे कारण मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अधिक प्रकर्षाने जाणवते. घटनात्मक पदाचा वापर आपल्या पक्षीय राजकीय हितासाठी करायचा असेल, तर त्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला संरक्षण आवश्यक आहे, असे सत्ताधारी व्यवस्थेला जाणवले असावे. या संरक्षणामुळेच जनक्षोभ निर्माण व्हावा, अशा गोष्टी सहज करण्याचे धाडस मुख्य निवडणूक आयुक्तांना झाले असावे.

२०२३ च्या कायद्यात निवडणूक आयुक्तांनी निर्णय शक्यतो एकमताने घ्यावेत, अशी तरतूद आहे. एकमत न झाल्यास बहुमताचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी निर्णय घेत होते आणि त्यातून लाखो मतदारांची नावे अनधिकृतपणे वगळली किंवा नव्याने समाविष्ट केली जात होती, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीने समोर आणले आहे. ही प्रक्रिया अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधाला न जुमानता राबविण्यात आल्याचेही ही बातमी सांगते.

दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेला सर्वात गंभीर आक्षेप आयोगाच्या एकात्मिक पोर्टलच्या, म्हणजे ECINETच्या, केंद्रीकरणाबाबत आहे. मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आयोगाच्या पातळीवरून केली गेली, असा आरोप आहे. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), उपमतदार नोंदणी अधिकारी (DERO) आणि सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्या पातळीवर ERONETच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. ECINETचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा त्यातील प्रवेश मर्यादित झाला. गोव्यात पाठ्य असलेल्या ९७ मतदारांचे नावे मतदार यादीत समाविष्ट करता आली नाहीत, कारण AEROला ECINETवर प्रवेशच मिळत नव्हता.

दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेला दुसरा आक्षेप फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या एकतर्फी बदलासंदर्भात आहे. या फॉर्ममध्ये यापूर्वी मतदारांना आपल्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची माहिती देणे आवश्यक नव्हते. फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. असे असतानाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फीपणे त्यात बदल केल्याचा आरोप आहे.

तिसरा आक्षेप पश्चिम बंगालमध्ये आणखी लाखो मतदारांची नावे वगळण्यासाठी मोठ्या संख्येने अपील दाखल करण्यास दिलेल्या परवानगीशी संबंधित आहे. न्यायाधीकरणांनी केलेल्या मर्यादित छाननीनुसार, येथे ९३ टक्के मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पातळीवरून विशिष्ट मतदारांची नावे वगळण्याचे निर्देश दिले गेले असावेत, असा स्पष्ट संशय निर्माण होतो. हे सारे केंद्रात सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठीच केले गेले, असा संशय निर्माण झाला आहे.

या सर्व मुद्द्यांमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या प्रामाणिकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने भारतातील तरुणांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांनीही या शंकांचे निरसन करण्याची मागणी केली आहे.

२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेले निवेदन हा तर त्रुटींचा कबुलीनामाच होय. हे निवेदन म्हणते, आता ज्या व्यक्तींना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या घरी बूथस्तरीय अधिकारी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती EROच्या निर्णयासाठी ECINETवर अपलोड करतील. अशा व्यक्तींना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावले जाणार नाही. ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा अधिक सक्षम केली जाईल. त्याचबरोबर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ECINET वर प्रवेश दिला जाईल. याचा अर्थ, यापूर्वी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना असा प्रवेश नव्हता.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देणे केवळ अपेक्षित नाही, तर आवश्यक आहे. जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्यासाठी केवळ निवेदन पुरेसे नाही.

अन्वयार्थ

साखर कारखाने लवकर सुरू करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण...

आधीच साखर कमी, त्यात सणांसाठी २८ लाख टन साखर खर्ची पडणार म्हणून लवकर हंगाम सुरू करण्याची काठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठी हाणली आहे!



विश्वास पाटील
वृत्तसंपादक, लोकमत, कोल्हापूर



एल निनोच्या प्रभावाने कमी झालेला पाऊस, त्याचा ऊस उत्पादनावर होणारा परिणाम यामुळे महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला आगामी दोन साखर हंगाम कसोटीचे ठरतील, अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. त्याचे नियोजन केंद्र व राज्य शासनाने आतापासूनच करून काही पूरक धोरणे निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

देशाला वर्षाला सरासरी २८० लाख टन साखरेची गरज असते. यंदाच्या हंगामात एवढे साखर उत्पादन होईल का याबद्दलच शंका आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी हंगाम सुरू होताना आरंभीचा साठा जो लागतो तो अत्यल्प असेल. यावर्षी दुष्काळामुळे ऊस पीक कमी झाले तर पुढील हंगामही (२०२७-२८) अजून अडचणीचा असेल. संभाव्य साखर उत्पादन व तापर याचा अंदाज घेतल्यास साखर तुटवडा जाणवू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर चढेच असल्याने आयात साखर परवडणारी नाही. जेव्हा जेव्हा भारताला साखरेची आयात करावी लागली आहे तेव्हा जगाच्या बाजारपेठेतील दरही चढेच असतात असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

पुरेशी साखर शिल्लक नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारने यंदाचा हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे परंतु त्याला शेतकरी व कारखानदारही तयार नाहीत. आपल्याकडे साखर उत्पादनासाठी १५ नोव्हेंबर ते १५ एप्रिल हा सोयीचा हंगाम समजला जातो. कारण ऊस परिपक्व झालेला असतो. उसाची वाढच पुरेशी नाही झाली तर टनेज घटते. उतारा घटला तर कारखान्यांना नुसते पाणीच उकळावे लागते आणि प्रक्रियेचा खर्च जास्त येतो. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना टनाला ५०० रुपये अनुदान, साखरेचा खरेदी दर ५० रुपये आणि इथेनॉलला लिटरला ७० रुपये द्या अशा मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. सरकार सांगत असले तरी हंगाम १५ ऑक्टोबरला सुरू करूच नका असे ते कारखानदारांच्या धरी भेट देऊन सांगू लागले आहेत. आतापर्यंत 'कारखान्यांचे आम्हाला काही माहीत नाही, आमच्या उसाला अमुक दर द्या' अशी भूमिका घेऊन संघर्ष करणारे शेट्टी आता कारखान्यांच्या प्रश्नांसाठीही रस्त्यावर उतरले आहेत. ही त्यांची नवी भूमिका आहे. त्यामुळे जर कारखानेच सुरू झाले नाहीत तर सरकारची कोंडी होऊ शकते.

साखरेची एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) दरवर्षी वाढली परंतु २०१९ पासून साखरेचा क्विंटलचा दर ३,१०० रुपयेच राहिला आहे. त्यात वाढ न झाल्याने कर्जे काढून शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यावी लागत आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला. आता त्यातून रिलिफ म्हणून पुन्हा राज्य सरकार त्यांना हजारो कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन देत आहे म्हणजे हा सारा उफराटा व्यवहार झाला. त्यापेक्षा साखरेची खरेदी किंमत वाढवली तर सगळेच प्रश्न सुटतात परंतु केंद्र सरकारला मध्यमवर्गीय ग्राहकाला दुखवायचे नसल्याने अशी वेळ आली की सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीत काठी हाणते.

गेल्या दहा वर्षांत कडधान्य व अन्य अन्नधान्यांची ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली. साखरेची दरवाढ मात्र २६ टक्केच झाली आहे. परंतु ऊस उत्पादक शेतकरी हा प्रस्थापित आहे, तो पैसेवाला आहे असा मोठ्या वर्गाचा समज वर्षानुवर्षे करून ठेवला आहे. त्यामुळे सरकार साखर कारखानदारीला काही मदत करायची म्हटल्यावर कायमच हात आखडता घेते. साखर पिकवणारा देखील शेतकरीच आहे, ऊसासाठी लागणाऱ्या खत, बीज, पाणी आणि मजुरीच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यात निसर्गाचा फटका बसला तर त्याच्या हातात काहीच राहत नाही याचा विचार कधी होत नाही. आता देशात ३० ते ३५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. दसरा-दिवाळीसाठी त्यातील २८ लाख टन द्यावी लागेल. त्यामुळे हंगाम सुरू होताना ५ ते ७ लाख टनच साखर हातात असेल. त्यासाठी सरकारला हंगाम लवकर सुरू करायचा आहे परंतु त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे मरण आहे याचा विचार करायला कोणीही तयार नाही, हे मोठेच दुर्दैव म्हणायचे!

vishwas.patil@lokmat.com

जगभर

अचाट साहसाच्या शोधात ९१ वर्षीय आजोबा!

'जगण्यात साहस हवं' अशी अपेक्षा धरून जी माणसं जगतात त्यांना म्हातारपणातही साहसाची हौस स्वस्थ बसू देत नाही. अमेरिकेत टेनिसी येथे राहणारे डेल सॅण्डर्स हे ९१ वर्षांचे आजोबा. त्यांनी केलेलं साहस तरुणांनाही अचंबित करणारं आहे. ॲपलाचियन ट्रेल पूर्ण करणारे सर्वात वयोवृद्ध गिर्यारोहक होण्याचा विक्रम त्यांनी स्वत:च्या नावावर केला आहे. दुर्गभ्रमंतीच्या रस्त्यावर 'ग्रे बिअर्ड'... पांढरा दाढीवाला.. या नावाने सॅण्डर्स यांना ओळखलं जातं.

अनेक आव्हानांचा सामना करून ते काटाडिन शिखरावर पोहोचले आणि त्यांचं ॲपलाचियन ट्रेल पूर्ण झाला. त्यांची वर्षभराची मेहनत सार्थकी लागली.

ॲपलाचियन ट्रेल हा अमेरिकेच्या पूर्व भागातील एक प्रसिद्ध आणि जगातील सर्वात लांब असा केवळ हायकिंगसाठी असलेला ट्रेल आहे. अमेरिकेच्या जॉर्जिया राज्यापासून सुरू होऊन १४ राज्यांतून प्रवास करताना डोंगराळ प्रदेश आणि घनदाट जंगलं लागतात. ३५०० किलोमीटरचा हा मार्ग कोणत्याही क्रमाने एका वर्षात पूर्ण करणं हे भल्याभल्यांसाठी आव्हानात्मकच असतं.

सॅण्डर्स यांची ॲपलाचियन ट्रेल पूर्ण करण्याची दुसरी वेळ आहे. वयाच्या ८२ व्या वर्षी हा ट्रेल त्यांनी पहिल्यांदा पूर्ण केला. तेव्हाही त्याची नोंद ॲपलाचियन पार करणारा जगातील सर्वात वयोवृद्ध गिर्यारोहक अशीच झाली होती. पहिल्या ट्रेलचा अनुभव गाठीशी होता, त्यामुळे आताचा ट्रेल त्यांना सहज वाटला असेल असं कोणालाही वाटू शकतं. पण प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. हा ट्रेल पहिल्या ट्रेलच्या तुलनेत तीन पट कठीण होता असं खुद्द सॅण्डर्स म्हणतात.

त्यांनी ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी वेस्ट व्हर्जिनिया इथून प्रवास सुरू केला. माउंट काटाडिन गाठेपर्यंत ३५३० किलोमीटरच्या प्रवासात सॅण्डर्स ७१ वेळा



पडले. एकदा तर त्यांची नस दबली गेल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. पण त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. अंतिम ध्येय गाठायला केवळ २३० किलोमीटर बाकी असताना दोन आठवडे आधी 'आता बास, घुडे नाही जाऊ शकत', असे वाटून ते थांबणारही होते. पण सॅण्डर्स यांच्या पत्नीने आणि मदत करणाऱ्या टीमने त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि सॅण्डर्स यांच्या थांबू पाहणाऱ्या पायांनी पुन्हा जोर पकडला.

ॲपलाचियन मोहीम मोठी आणि खडतर असल्याने सॅण्डर्स यांना वाटेत अनंत अडचणी आल्या. पण अडचण आली की सॅण्डर्स यांना त्यातून मार्ग काढण्याचं स्फुरण चढायचं. आयुष्यात साहसासोबतच नावीन्य शोधणारे सॅण्डर्स हे माजी सैनिक.

सैन्यातून निवृत्त झाल्यावर मनोरंजन क्षेत्रात त्यांनी दीर्घ काळ काम केलं. हे काम करत असतानाच त्यांना क्षमता आणि ऊर्जेचा कस पाहणाऱ्या वेगवेगळ्या मोहिमा करण्याचं वेड लागलं. त्या जितकं वृद्धत्वाकडे झुकत होतं तितके वेगवेगळे विक्रम त्यांच्या नावावर जमा होत होते. २०२० मध्ये वयाच्या ८५ व्या वर्षी 'ग्रेंड कॅनियन' ही विशाल दरी एका काठावरून दुसऱ्या काठावर चालत जाऊन पार करणारी जगातली सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती होण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. २०२२ मध्ये ८७ व्या वाढदिवशी ते मिसिसिपी नदी ८७ दिवसात नौकानयन करून पार करण्याच्या मोहिमेवर निघाले. हा विक्रम करणारे सॅण्डर्स हे जगातील सर्वात वयोवृद्ध व्यक्ती होते.

जनमन

दुष्काळग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी



महाराष्ट्रातील काही भागात दुष्काळी परिस्थिती चिंताजनक आहे. प्रसारमाध्यमांतून शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था दाखविली जात आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळ तसा नवा नाहीच, पण साधारणपणे दर तीन ते चार वर्षांनी अशी गंभीर परिस्थिती दुष्काळामुळे होत असते. महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग तर जिल्हा जवळजवळ ठरलेला आहे. राज्यातील दुष्काळी भागात माणसाच्या सोबत जनावरांचे देखील अतोनात हाल होत आहेत. पिण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शेतकरी सतत कर्जबाजारी होत असल्यामुळे हतबल झाला आहे. शेतकऱ्यांना जी काही मदत मिळणार आहे ती फक्त शासनाच्या मार्फत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले, त्यांची विचारपूस करून आले, आता इतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येणे, पाहणी करणे आणि दुष्काळी भागाचा दौरा करणे गरजेचे आहे. दुष्काळामुळे पिके करपणे, पाण्याची तीव्र टंचाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडतो. शेतीचे व पिकांचे नुकसान होते. भूजल पातळी खालावल्यामुळे विहिरी व कूपनलिका आटतात. परिणामी, गावोगावी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. पिण्याच्या पाण्यासोबतच पाळीव जनावरांसाठी चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण होतो. उत्पन्नाचे साधन नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढतो. यामुळे ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण तयार होते. मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील इतरही दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना शासनाने अतितातडीची उपाययोजना करून मदत करायला हवी.

- संजय सुनिता गंगाराम साळगांवकर, कुर्ला, मुंबई

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

शहर नोंदी

पॉप्युलर कल्चरमधील 'गाँव की छोरी' आणि 'शहरी बाबू'चं गृहीतक

हिंदी सिनेमानं गावातल्या मुली आणि शहरातल्या मुलांचं एक अतिशय बाळबोध चित्र रंगवलं, पण चित्र इतकं काळंपांढरं कधीच असत नाही.



मेघना भुस्कुटे
ब्लॉगर, भाषांतरकार

हिंदी सिनेमातली आणि खरं तर पॉप्युलर कल्चरमधलीच - शहराची संकल्पना अगदी नव्वदीपर्यंत बरीच बाळबोध होती, नाही? 'गाँव की छोरी' एकदम भोळीभाबडी, निरागस, देशी संस्कारांनी घडवलेली; तर 'शहरी बाबू' म्हणजे दिलेला शब्द सोयीस्करपणे विसरून जाऊ शकणारा, आधुनिक कपडे नि फॅशन करणारा, 'येस-पपेस' बोलणारा.. असं एक गृहीतक असायचं.

'राम तेरी गंगा मैली' ते 'मौसम' ते 'जिस देश में गंगा रेहता है'... किती म्हणून उदाहरणं सांगावीत! नि खरं तर फक्त हिंदी सिनेमाला तरी कशाला दोष द्यावा, 'मुंबईचा फौजदार' हा गाजलेला मराठी चित्रपट घ्या.

त्यातही मुंबईच्या मुलाची निर्दयी आधुनिकता आणि गावाकडच्या साध्याभोळ्या नायिकेचा देशीपणा यांच्यातलाच सामना होता. या एका दोपदर आधारित ढिगांनी सिनेमे सापडतील. अगदी नव्वदीतल्या 'परदेस'मध्ये अमेरिकेतून भारतातल्या खेड्यात आलेल्या नक्यामुलाची कशी दैना होते नि अखेर तो कसा 'वाईट चालीचा निघतो' ते आठवतंय ना? शहरातल्या लोकांबद्दल अजून एक मजेशीर ग्रह म्हणजे 'ते बदमाश असतात!' गावाकडून शहरात आलेल्या, बहुतकरून शेतकरी कुटुंबातल्या, भोळ्याभाबड्या नायकाला शहरातले लफंगे बघता बघता मामा बनवतात आणि लुटतात, हाही ट्रोप कितीतरी वेळा सिनेमात वापरलेला दिसतो.

हीच समजूत स्त्रियांच्या बाबतीत थोड्या निराळ्या वळणानं जाते. 'शहर की लडकी' म्हणजे साडी नि कुंकवाबिकवाला फाटा देऊन तोकडे कपडे घालणारी, भरपूर मेकअप करणारी, सिगरेट फुंकणारी, इंग्रजीत बोलणारी नि शिव्याही देणारी, तथाकथित 'बिगडी हुई' लडकी! नेमाडज्यांच्या पांडुरंग सांगवीकरनं पुण्यातल्या तोंड रंगवणार्या स्त्रियांना तर थेट वेश्याच म्हणून टाकलं. जणू भारतीय संस्कृतीतला सगळा निरागसपणा, सगळी सुसंस्कृतता, सगळं पावित्र्य खेड्यांच्या नि शेतांच्या मातीत एकवटलं होतं; आणि उलटपक्षी सगळा बदमाशपणा, सगळी संस्कारहीनता, आणि सगळा भ्रष्टाचार ही शहरांची मिरासदारी होती. चित्र इतकं काळंपांढरं कधीच असत नाही, हे कुठल्याही शहाण्या माणसाला कळतं. तरी शहराबद्दलचं हे कव्य लोक अगदी आत्ताआत्तापर्यंत उराशी बाळगून होते, अजूनही असतील कदाचित.



रान आणि स्वच्छंदी जगणं मागे राहणं, त्यात पिढ्यानपिढ्यांची जगण्याची पद्धत सोडून द्यावी लागणं, आपल्या हक्काच्या मातीतून उखडलं जाणं, गेल्या शतकभरात न भूतो न भविष्यति असा वाढलेला शहरीकरणाचा वेग, तिथली विषमता-गर्दी-वेग, आधी औद्योगिक क्रांतीनं, मग इंटरनेटनं, आणि आता आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सनं अक्षरशः उलट-सुलट ढवळून काढलेलं जग... या सगळ्यातून आलेला अविश्वास, अप्रीती असेल कदाचित. कारण भारतातच नव्हे, हे जगभर कमीअधिक प्रमाणात अनुभवाला येतं. हेच सगळं पॉप कल्चरमध्ये प्रतिबिंबित झालं असणार. ते सहजासहजी मोडीत तरी कसं काढावं, आणि काहीच न म्हणता स्वीकारावं तरी कसं? नेहमीप्रमाणेच दोन्ही खरं असणार. सत्याचे कण दोहोंच्या मधल्या विस्तीर्ण प्रदेशात कुठेतरी विखुरलेले असणार.

असं म्हणतात, आधुनिकता येते तेव्हा ती परंपरा की प्रगती अशा एका द्वंद्वाला जन्म देते. वारसा-नतनिर्मिती, करुणा-कठोरता, स्त्री-पुरुष अशी द्वंद्वही सोबतच येतात. गाव - शहर हे असंच एक अपरिहार्य द्वंद्व आहे बहुतेक.

meghana.bhuskute@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे



हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८५ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पूर्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४०००७० येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०५७०४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. ९०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५३०, ०२२- ४७७०७४४१ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४५९९०५, २५३८५७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पूर्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४०००७०. फोन : ०२२ ४६०५७०४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे व्यापारचिन्ह आहे.

हवा जहरीली न हो

राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत में प्रदूषण के चरम दिन फिर आ रहे हैं। इस मोर्चे पर समय रहते दिल्ली और हरियाणा की तैयारी खासतौर पर ध्यान खींच रही है। पराली जलाने पर रोक के लिए हरियाणा ने उपाय किए हैं, तो दिल्ली ने भी व्यापक योजनाओं की घोषणा की है। ध्यान रहे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खेतों में खड़े धान के अवशेष को आग के हवाले करके जल्दी से जल्दी अगली फसल की तैयारी की अंधी होड़ शुरू हो जाती है। हर साल उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। पराली जलाने की घटनाएं 15 सितंबर के आसपास शुरू हो जाती हैं और इस बार भी शुरू हो गई हैं। प्रदूषण का सबसे घातक समय हम नवंबर के महीने में देखते हैं, जब उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर जहरीली धुंध छाई रहती है। जाहिर है, पराली जलाने की गलत परिपाटी को रोकने के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों को ठोस व कठोर कदम उठाने चाहिए।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जिन उपायों की घोषणा की है, उनकी सराहना होनी चाहिए। समय रहते की गई घोषणाओं का जमीनी असर अवश्य दिखना चाहिए। दिल्ली में निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। यह भी स्वागतयोग्य है कि यह दोगुना शुल्क 28 फरवरी 2027 तक ही प्रभावी रहेगा। दिल्ली में मोटर वाहनों की अत्यधिक संख्या अपने आप में बड़ी समस्या है। ऐसे में, पार्किंग शुल्क के ज्यादा होने से निजी वाहनों के इस्तेमाल में कमी आएगी। कार्यालय समय में भी बदलाव किया गया है और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मियों की संख्या को आधा करने की तैयारी है। सरकारी और निजी उपक्रमों को निर्देश दिया गया है कि वे 50 प्रतिशत कर्मियों को घर से काम की इजाजत दें। इसके अलावा, धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ की गतिविधियों और बाहरी निर्माण कार्यों को 1 नवंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक प्रतिबंधित करना जरूरी है। इन उपायों को जब ठीक से आजमाया जाएगा, तब लोग साफ हवा में सांस ले सकेंगे। हर नागरिक के लिए स्वच्छ वायु दिल्ली सरकार ही नहीं, देश की हर सरकार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। बीते दशकों में हमने स्वच्छ हवा के साथ खिलवाड़ करके खुद को मुसीबत में डाला है। उत्तर भारत की सरकारों को हर संभव प्रयास करने चाहिए कि आगामी सर्दियों में कोहरे और प्रदूषण का जानलेवा आवरण न बनने पाए।

पराली जलाने की गलत परिपाटी को रोकने के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों को ठोस व कठोर जमीनी कदम उठाने चाहिए, ताकि सबको राहत मिले।

हरियाणा सरकार भी इस बार बहुत मुस्तैद है। प्रति सौ किसान पर एक नोडल अधिकारी तय किया गया है, ताकि किसी भी किसान को पराली जलाने का अपराध न करना पड़े। हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन में सहयोग करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,200 रुपये प्रदान करेगी। किसानों के साथ अगर सहयोग और निगरानी की व्यवस्था पुख्ता हो जाए, तो प्रदूषण से राहत मिलना तय है। सरकारों के प्रयास से ही पंजाब में पिछले साल पराली जलाने की घटनाएं आधी हो गई थीं। वहां खेतों में आग लगाने की 5,114 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में भी पराली जलाने की घटनाएं 1,406 से घटकर 662 हो गई थीं। हां, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाएं बीते वर्ष कुछ ज्यादा दर्ज हुई हैं। इन सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने स्तर पर प्रदूषण रोकने के तमाम जरूरी इंतजामों को जमीन पर उतारना चाहिए, ताकि हमें सर्दियों में जहरीली हवाओं से निजात मिले।

सर्जिकल स्ट्राइक से हुआ जो हासिल



सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के दस वर्षों में हमारी प्रतिक्रिया मारकता में आगे बढ़ती गई। बालाकोट पर हवाई हमले किए गए, तो ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ।



वह 29 सितंबर, 2016 की भोर थी, जब भारतीय सेना द्वारा पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की खबर मीडिया में प्रसारित हुई। बेशक, पहले भी ऐसी सैन्य कार्रवाइयां होती रही हैं, मगर यह पहला मौका था, जब हमारी हुकूमत ने इसका खुलेआम एलान किया था। सदेश बिल्कुल साफ था, भारत अब आतंकी कृत्यों को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं और 'जैसे को तैसा' जवाब दिया जाएगा।

'सर्जिकल स्ट्राइक' उरी के सैन्य शिविर पर किए गए आतंकी हमले का जवाब था। इसे जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिनको उसी समय ढेर कर दिया गया, लेकिन तब तक वे हमारे 17 सैनिकों को शहीद कर चुके थे। दो अन्य जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरे हिन्दुस्तान में गहरी नाराजगी थी। नतीजतन, हमारे राजनीतिक और सुरक्षा नेतृत्व ने दहशतगर्दों को माकूल जवाब देने का फैसला लिया और 28-29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुई।

यह कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। एक गलत कदम न सिर्फ उप-महाद्वीप को उथल-पुथल की अंधेरी सुरंग में धकेल सकता था, बल्कि विश्व बिरादरी में हमारी किरकिरी भी करा सकता था। हमारे जवान चुनौतियों से जूझना खूबही जानते हैं। उन्होंने न सिर्फ वहां मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सफलता हासिल की, बल्कि अनुमानतः 30 से 50 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। यही नहीं, तकरीबन चार घंटे के भीतर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे, वे सकुशल वापस भी लौट आए। सैन्य व खुफिया सेवाओं में ऐसा अद्भुत तालमेल इससे पहले देश ने शायद ही सुना था। दुनिया के लिए भी यह 'नए भारत' का उद्घोष था।

यह हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारी जितनी भी जवाबी कार्रवाइयां हुईं, वे मारकता के लिहाज से एक कदम आगे बढ़ती गईं हैं। मसलन, 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट पर 'हवाई' कार्रवाई की गई, यानी सिर्फ थल सेना नहीं, बल्कि वायु सेना को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' को याद कीजिए, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में जहां पीओके के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वहीं बालाकोट में पाकिस्तान के भीतर हम दाखिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी जद में पंजाब सहित पाकिस्तान के कई अन्य इलाके भी थे।

इसका असर पाकिस्तानी मनोबल पर पड़ा है। पहले वह अक्सर 'परमाणु हमले' की धमकियां दिया करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका ने ऐसा कुछ किए जाने का संकेत हमें दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने दोटूक बता दिया कि अगर इस्लामाबाद ने ऐसी कोई हिमाकत की, तो फिर हमारा जवाब उसके लिए बहुत घातक होगा। नतीजतन, अब पाकिस्तान अपनी जमीन से उस पैमाने पर आतंकवाद का निर्यात नहीं कर पा रहा, जैसा वह पहले किया करता था। गौरतलब है, 'नॉन स्टेट एक्टर्स' के खिलाफ कार्रवाई अमूमन कारगर नहीं होती। हमास के खिलाफ इजरायली हमले में यह हम देख रहे हैं। इसलिए, हमारी सरकार ने सीधे वहां की हुकूमत को जवाब दिया, जिसका जमीनी असर पड़ा है।

हालांकि, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों के अपने खतरे भी हैं। जैसे, इसमें एक 'सरप्राइजिंग एलीमेंट' था, लेकिन बाद की कार्रवाइयों के पूर्वाभास होने लगे। पुलवामा के समय ही यह कयास तेज था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भी इससे अलग नहीं था। इसका मतलब है, जवाबी प्रतिक्रिया का अंदेशा दुश्मन देश लगाने में सफल हो सकता है। फिर जान-बूझकर उकसाने के लिए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, जिससे नुकसान हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान कभी चीन की शह पर हमें भड़काने का प्रयास करे। इसकी एक हल्की झलक हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। इसलिए, ऐसे हमलों में अब कहीं ज्यादा सावधानी की दरकार रहती है। हमें अधिक सचेत रहना होगा।

बीते दस वर्षों में सुरक्षा रणनीति में आए बदलाव ने भी सावधानी की जरूरत बढ़ा दी है। दरअसल, वह समय बीत गया, जब कोई हथियार 25-30 साल तक कारगर माने जाते थे। अब तकनीक ने जंग का पूरा चरित्र बदल दिया है। यह ड्रोन युद्ध का दौर है और यह हथियार बहुमूल्यक तीन से छह महीने तक काम करता है, क्योंकि इसे गिराने की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही 'लाइटरिंग म्यूनिशेन' का खूब इस्तेमाल हुआ। यह ड्रोन आसमान में चक्कर काटता रहता और मौका मिलते ही लक्ष्य को भेद देता था, लेकिन अब युद्ध में यह बहुत काम का नहीं रहा। अब तो कई आतंकी गुट भी ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। जाहिर है, बचाव या जवाबी कार्रवाई के लिए हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी।

अच्छी बात है, इस बाबत हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं। एक पारिस्थितिकी-तंत्र विकसित किया जा रहा है, पर कानूनी पेचीदगियों और नियामक बंधनों के कारण हमें अब भी कई कल-पुर्जे विदेश से मंगवाने पड़ते हैं, जिसके कारण उपकरणों को बनाने से कहीं अधिक सस्ता उसे खरीदना हो जाता है। इसका दोतरफा नुकसान होता है। अव्वल तो हमें हड़बड़ी में इनको खरीदना पड़ता है, फिर ऐसी खरीद आमतौर पर तात्कालीक जरूरतों के हिसाब से होती है। रोजाना विकसित होती तकनीक इन हथियारों को लंबे समय तक कारगर नहीं रहने देती, इसलिए युद्ध लंबा खिंचने पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

रूस और यूक्रेन युद्ध पर ही गौर कीजिए। बेशक, रूस के कुछ ड्रोन ही यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो पा रहे हैं, लेकिन मॉस्को के पास इतनी क्षमता तो है कि वह रोजाना भारी संख्या में नए ड्रोन बना पा रहा है। जब आपके पास हथियार बनाने की क्षमता होती है, तो दुश्मन के पास उसको गिराने की भले रणनीति हो, लेकिन कोई-न-कोई हथियार लक्ष्य पर निशाना जरूर लगा सकता है। हमें भी इसी तरह की दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी।

अब यदि पहले जैसे आतंकी हमले नहीं हो रहे, तो इसकी एक वजह हमारी जवाबी कार्रवाइयां हैं और दूसरी, सुरक्षा कवच की मजबूती। निस्संदेह, चुनौतियां लगातार रूप बदल रही हैं, लेकिन जो शांति आज हम देख रहे हैं, वह 'सर्जिकल स्ट्राइक' की ही देन है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 29 सितम्बर, 1951

रंगभेद बरकरार

दक्षिण अफ्रीका जहां संसार की एक बहुमूल्य धातु-स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, वहां रंगभेद के लिए भी कुख्यात है। काली और गोरी चमड़ी के मनुष्यों के बीच जितना भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में बरता जाता है, उतना अन्य किसी देश में शायद ही बरता जाता होगा। दक्षिण अफ्रीका में ही तो महात्मा गांधी ने इस रंगभेद के अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह के नैतिक शस्त्र का सफल प्रयोग किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तत्कालीन सरकार से भारतीयों के लिए जो अधिकार प्राप्त किये थे, वे धीरे-धीरे छीने जा चुके हैं।

दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जनरल स्मट्स की मौत ने रंगभेद से हटा दिया। उनकी पार्टी का रुख भी रंगभेद की इस समस्या के प्रति बहुत उदार नहीं था। किन्तु डा. मलान की मौजूदा सरकार तो दक्षिण अफ्रीका को गोरों की बपौती समझती है और काली जातियों को तिरस्करणीय मान कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उनका बहिष्कार करने पर तुली हुई है।

महात्मा गांधी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका गये थे, उस समय उन्हें अपमान, डांट-फटकार और जोर-जबर्दस्ती का सामना करना पड़ा था। आज आधी शताब्दि बीत जाने पर भी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। रंगभेद को वहां कानूनी जामा पहना दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीका के मूलनिवासियों को उन क्षेत्रों से हटा कर जहां यूरोपियन लोग रहते हैं, दूसरे क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। जो क्षेत्र यूरोपियनों के लिए निर्धारित कर दिये गये हैं, उनमें यदि गैर यूरोपियनों की जमीन-जायदाद है तो उसे उन्हें बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। काली चमड़ी वालों को कुछ क्षेत्रों के सिनेमाओं और पुस्तकालयों में दाखिल नहीं होने दिया जाता। डाकघरों और रेलवे स्टेशनों में उन्हें अलग रास्तों से जाना होता है और यूरोपियनों के काम निपट जाने के बाद उनकी बारी आती है। बड़ी दुकानों और दफ्तरों में भी उनके साथ ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। वे टैक्स गोरों के समान ही देते हैं, किन्तु उन्हें मताधिकार और प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया है। इस रंगभेद के अन्याय के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वार खटखटाये जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र संघ का सदस्य होते हुए भी रंगभेद की नीति का अनुसरण करके खुलेआम उसके सिद्धान्तों की अवहेलना कर रहा है।

गुजरात से कन्या कुमारी तक फैले पश्चिमी घाट की चिंता



दक्षिण एक्सप्रेस
एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

देश में बाढ़ और सूखे से सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें अब लगभग आम बात हो गई हैं। कुछ समय के लिए सदमा लगता है, वेबसी महसूस होती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। समस्या की जड़ तक जाने की इच्छाशक्ति हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन लालच और स्वार्थ के वशीभूत होते ही सामूहिक सोच खत्म हो जाती है। इन दिनों पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) पर्वत शृंखला इसी लालच और स्वार्थ की बलि चढ़ रहे हैं।

पिछले हफ्ते कर्नाटक विधानमंडल में यह कटु सच्चाई उस समय साकार हो उठी, जब केंद्र के एक मसौदे को दलगत भावना से ऊपर उठकर खारिज कर दिया गया। इस मसौदे में पर्यावरण संरक्षण के लिए पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाकों को 'पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए)' घोषित करने का प्रस्ताव था। विधानमंडल का यह फैसला पर्वत शृंखलाओं की रक्षा न कर पाने और आगामी पीढ़ियों के साथ अन्याय करने सरीखा है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट पर्वत शृंखला हिमालय के बाद दूसरे स्थान पर आती है। यहां ऐसी दुर्लभ और मूल जैविक प्रजातियों का खजाना है, जो धरती पर कहीं और नहीं पाई जातीं। यहां पर जैव-विविधता की भरमार है, यानी अलग-अलग तरह के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, जिनसे एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट के पर्वत गुजरात में ताप्ती नदी से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1,64,280 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं।

आज विकास के नाम पर जानवरों, पौधों और इंसानों की आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है।

वर्ष 2010 में प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने केंद्र सरकार को पश्चिमी घाट के सुरक्षा उपायों के बारे में रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पश्चिमी घाट के 'प्राकृतिक परिदृश्य' के तौर पर पहचाने जा सकने वाले 41 प्रतिशत भूभाग, यानी 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए के तौर पर रखने का सुझाव दिया था। यहां पर पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की विविधता, संरक्षित वन और बाघ एवं हाथी कॉरिडोर मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के दायरे में आए छह राज्यों- गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने इसे गरीबों के खिलाफ बताया और आशंका जताई कि लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे या हमेशा के लिए अपनी आजीविका खो देंगे।

आलोचनाओं को देखते हुए तत्कालीन यूपीए भी खारिज कर दिया। उनका दावा था कि जिनको प्राकृतिक, जंगली इलाका माना गया था, वे असल में खेत हैं।

गाडगिल आयोग ने ईएसए में खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और पर्यावरण पर बुरा असर डालने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाने की सिफारिश की थी। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने इसमें कुछ ढील दी। खनिज खनन, पत्थर की खदानों और रेत खनन को लाल रेखा के तहत रखा गया। रेत खनन को धीरे-धीरे खत्म करने की सिफारिश की गई और कहा गया कि किसी हाल में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कस्तूरीरंगन आयोग ने नदियों के बहाव को जांचने का तरीका भी बनाया। थर्मल पावर प्लांट पर रोक लगा दी गई और कड़ी निगरानी के साथ हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। बांधों पर फिर से नजर रखी जाने लगी।

पर्यावरणविदों का आरोप है कि अपने फायदे के लिए कुछ लोग पर्यावरण को बचाने वाले उपायों को रोक रहे हैं। उधर, ताकतवर लॉबी का दावा है कि इन उपायों से लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी। असलियत यह है कि विकास के नाम पर जानवरों, पौधों और इंसानों की आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

औसत मन की चाह

क्या समय अकेलेपन और दुख को पोंछ डालता है? क्या वे मन के गहरे तलों में दबे हुए नहीं रह जाते? आपके अचेतन दुख के कारण कहीं यही तो नहीं?

अकेलापन आपको पीड़ा नहीं देता, किंतु अकेलेपन की धारणा भय उत्पन्न करती है। आपने अकेलेपन की अवस्था का कभी अनुभव नहीं किया है। आपने सदैव इसकी ओर आशंका और आतंक की दृष्टि से देखा है। आपने हमेशा इससे दूर जाने या इस पर विजय पाने की कामना की है। इस तरह, आप इससे बचते रहे हैं। आप इसके प्रत्यक्ष संपर्क में कभी आए ही नहीं। इसे खुद से दूर रखने के लिए आपने अपने बच्चों के कार्यकलापों, उनकी सफलता में अपना पलायन खोज लिया है। उनकी सफलता आपकी सफलता बन गई, पर सफलता की इस पूजा के पीछे कोई गहरी चिंता नहीं छिपी है?

जिस चीज में आप पलायन करते हैं- रेडियो, सामाजिक गतिविधि, कोई विशिष्ट सिद्धांत, तथाकथित प्रेम आदि- वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। आपके लिए उतनी ही आवश्यक, जितनी शराबी के लिए शराब। कोई स्वयं को सफलता की पूजा में भुला सकता है अथवा किसी प्रतिमा के पूजन में या किसी आदर्श में अपने को खो सकता है; किंतु सभी आदर्श भ्रांतिजनक हैं, और अपने को भुलाने में ही चिंता निहित रहती है। यदि मैं आपको ध्यान दिला सकूं, तो आपके बच्चों की सफलता आपकी पीड़ा का स्रोत रही है, क्योंकि उनके बारे में और अपने बारे में आपको एक अधिक गहरी चिंता है। उनकी सफलता पर आपकी सराहना तथा लोगों से उनको मिली वाहवाही के बावजूद, इस सबके पीछे क्या एक प्रकार की शर्मिंदगी या निराशा नहीं छिपी है? यह पूछने के लिए मुझे क्षमा कीजिए, परंतु उनकी सफलता को लेकर क्या आप गहराई में व्यथित नहीं हैं?

मनुष्य केवल अपने आप में औसतपन से उबर सकता है, और तब शायद औरों के साथ एक भिन्न प्रकार का संबंध रूप ले सकता है। इस बात को जान लेना कि हम औसत हैं, परिवर्तन का प्रारंभ है, न? एक क्षुद्र मन जब स्वयं के विषय में सजग होने लगता है, तब वह परिवर्तन के लिए, अपने सुधार के लिए व्यग्र होकर कोशिशों में लग जाता है और यह चाह ही औसत है,

बदलने का प्रयास क्षुद्र मन से ही जन्म लेता है, इसलिए यह प्रयास भी क्षुद्र ही है। मन का प्रत्येक कर्म अल्प और सीमित होता है। उसे करना बंद कर देना होगा, केवल तभी औसतपन का अंत होता है।

मामूली है। अहं-सुधार की कोई भी आकांक्षा क्षुद्र है। जब मन यह जान जाता है कि वह औसत है और अपने साथ कुछ नहीं करता, तब वह औसतपन टूटने लगता है।

यदि कोई क्षुद्र मन यह महसूस करके कि यह क्षुद्र है, स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तो क्या वह अब भी क्षुद्र नहीं है? बदलने का प्रयास क्षुद्र मन से ही जन्म लेता है, इसलिए यह प्रयास भी क्षुद्र ही है। मन का प्रत्येक कर्म अल्प और सीमित होता है। मन को कुछ करना बंद कर देना होगा, केवल तभी औसतपन का अंत होता है।

जे कृष्णमूर्ति

सीपी राधाकृष्णन | उप-राष्ट्रपति, भारत



टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर की मदद तो कर सकती है, पर वह उसके मानवीय गुणों की जगह नहीं ले सकती। डॉक्टर होने का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उसे किसी अन्य इंसान की जिंदगी बचाने का मौका मिलता है।

नकली पनीर पर नकेल बहुत जरूरी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने असली और नकली पनीर के बीच स्पष्ट अंतर करने की दिशा में जो पहल की है, वह उपभोक्ता अधिकार, खाद्य सुरक्षा और डेयरी उद्योग- तीनों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल के वर्षों में बाजार में बड़ी मात्रा में एनालॉग पनीर ऐसे उत्पाद के रूप में बिक रहा था, जो देखने में पनीर जैसा होता है, लेकिन वह दूध के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों से तैयार किया जाता है। यही भ्रम दूर करने के लिए एफएसएसएआई ने कवायद शुरू की है।

दरअसल, एनालॉग उत्पाद बनाना अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन उसे 'पनीर' के नाम से बेचना उपभोक्ता को गुमराह करना है। ऐसे उत्पाद की पौष्टिकता और संरचना पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग होती है, इसलिए उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो खरीद रहा है, वह वास्तव में दूध से बना पनीर है या उसका विकल्प? इसीलिए यह मसौदा संशोधन जारी किया गया है, जिसके अनुसार दूध से निर्मित न होने वाले किसी भी उत्पाद को 'पनीर' नाम, लेबल या प्रचार में उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। जिन कंपनियों के पास इसका लाइसेंस नहीं है, उन्हें अपने उत्पादों से 'पनीर' शब्द हटाना होगा। इससे पहले अप्रैल 2026 में पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय ने होटल, रेस्तरां और कैटरिंग प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि यदि वे चीज या पनीर में एनालॉग का उपयोग करते हैं, तो मेन्यू और डिस्प्ले बोर्ड पर इसका स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही खरीद विभाग और शेफ को कच्चे माल की नियमित जांच व रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए थे।

इस कदम से उपभोक्ता और डेयरी किसान, दोनों को लाभ होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ऐसे में सस्ते विकल्प को असली पनीर बताकर बेचना न केवल उपभोक्ता के साथ धोखा है, बल्कि दूध उत्पादकों और डेयरी उद्योग के साथ भी अन्याय है। एफएसएसएआई ने माना है कि पनीर जैसे डेयरी उत्पादों की पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए और एनालॉग उत्पादों के लिए अलग नामकरण और कठोर मानक बनाए जाएं। जरूरत है जागरूकता फैलाने की। उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे गुणवत्ता और वास्तविकता के आधार पर फैसले ले सकें। कुल मिलाकर, एफएसएसएआई की यह पहल उपभोक्ता विश्वास की रक्षा का गंभीर प्रयास है। यदि इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो बाजार में ईमानदार प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और हर उपभोक्ता को वही मिलेगा, जिसके लिए वह भुगतान कर रहा है।

कुणाल वत्स, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
नकली पनीर



बाजार में बदलाव लाना आसान नहीं

पनीर की बढ़ती मांग के कारण वनस्पति तेल, स्टार्च, वनस्पति प्रोटीन व अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों से तैयार उत्पादों को पनीर के नाम से बेचा जाना दुखद है। इसलिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रस्तावित नियम स्वागतयोग्य है, जिसका उद्देश्य गैर-दुग्ध उत्पादों को पनीर के नाम से बेचने पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं को भ्रामक खाद्य उत्पादों से बचाना है। उपभोक्ता को यह अधिकार होना ही चाहिए कि उसकी थाली में परोसा गया भोजन वास्तव में वही हो, जिसकी जानकारी उसे दी गई है।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी सार्वजनिक विमर्श जारी है, लेकिन इसकी राह बहुत आसान नहीं है। कई व्यावहारिक चुनौतियों से इसको जूझना होगा। सबसे पहली चुनौती व्यापक जनजागरूकता की है। अधिकांश उपभोक्ता आज भी लेबल पढ़ने की आदत नहीं रखते। यदि नाम बदल भी जाए, तो लोगों को यह समझाना आवश्यक होगा कि वास्तविक पनीर और उसके विकल्प में पोषण व संरचना का अंतर क्या है। दूसरी चुनौती, छोटे निर्माताओं की है, जिन्हें नए लेबल, पैकेजिंग और मार्केटिंग के अनुसार अपने उत्पादों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए पर्याप्त समय और स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक होंगे। यह समझना होगा कि खाद्य नियमन केवल कानून बनाने से सफल नहीं होता, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। देश भर में नियमित नमूना जांच, प्रमाणित प्रयोगशालाओं की क्षमता, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं को भी समान रूप से मजबूत करना होगा। यदि निरीक्षण केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा, तो छोटे कस्बों और ग्रामीण बाजारों में भ्रामक उत्पादों की बिक्री जारी रह सकती है।

उपभोक्ताओं की भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। पनीर खरीदते समय पैकेट पर सामग्री सूची, निर्माण विवरण और उत्पाद की श्रेणी अवश्य देखनी चाहिए। खुला पनीर खरीदते समय भरोसेमंद विक्रेता का चयन आवश्यक है और असामान्य रूप से सस्ती कीमत में मिलने पर सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी उत्पाद के बारे में संदेह हो, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रारूप अधिसूचना अभी अंतिम कानून नहीं है। लोकतांत्रिक नियामक प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योग, उपभोक्ता संगठन, डेयरी विशेषज्ञ और आम नागरिक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधन किए जाने के बाद ही अंतिम नियम अधिसूचित होगा।

महेंद्र तिवारी, टिप्पणीकार

पूर्वजों के प्रति आभार जताने के दिन

श्राद्ध हमारे पूर्वजों की याद में अच्छे कर्म करने का माध्यम है। यह केवल एक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भले ही हमारे पितृ भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति आभार जताने और उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा चलती रहनी चाहिए।



अध्यात्म
श्री श्री रविशंकर

श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह पूरी श्रद्धा के साथ किया जाने वाला एक ऐसा कार्य है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परिवार के मृत सदस्यों के योगदान को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके अलावा उन्हें याद करते हुए कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से कुछ ऐसे कंपन उत्पन्न होते हैं, जो इस भौतिक संसार के दायरे से परे चले जाते हैं और इस अर्थ में दिवंगत आत्मा तक पहुंचते हैं। यदि आप कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना महसूस किए बिना केवल अनुष्ठान करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है।

पूर्वजों की याद में अच्छे कर्म

श्राद्ध हमारे उन पूर्वजों की याद में अच्छे कर्म करने का एक माध्यम है, जो अस्तित्व के इस भौतिक स्तर को पार कर चुके हैं। यह जीवित लोगों को याद कराता है, सब कुछ अनित्य है।

हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, *'यत पिंडे तत ब्रह्माण्डे'* - 'जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है।' कोई आत्मा अपने सांसारिक जगत से निकलती है, तो वह सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। यह एक निराकार और अगोचर क्षेत्र है। यह टीवी के विभिन्न चैनलों में ट्यूनिंग के कार्य के समान है। हम एक चैनल से संपर्क बनाते हैं, लेकिन उसी स्थान पर अन्य चैनलों की तरंगें भी मौजूद होती हैं, जिन्हें हम आवृत्ति बदलने पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, हम अपने दिवंगत प्रियजनों की आत्मा की उपस्थिति को तब महसूस कर सकते हैं, जब हम उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं।

शरीर और प्रकृति का एक होना

इन पवित्र अनुष्ठानों को करने की जिम्मेदारी आमतौर पर परिवार के निकटतम सदस्यों, विशेष रूप से बड़े पुत्र या पुत्री पर आती है। ये अनुष्ठान उस विशिष्ट तिथि पर मनाए जाते हैं, जब दिवंगत आत्मा ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था। इन्हें 16 दिनों की विशिष्ट अवधि के दौरान जिसे पितृ पक्ष के रूप में जाना जाता है, जो नवरात्र से ठीक पहले किया जाता है। इस पक्ष के दौरान हम जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और दिवंगत लोगों की याद में दान के कार्यों में संलग्न होते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं।

गरुड़ पुराण में आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि इस संसार को छोड़ने के बाद आत्मा 'प्रेत योनि' में रहती है। अब जब आत्मा ने शरीर त्याग दिया है, तो वह वापस लौटना नहीं चाहती। भौतिक शरीर एक त्यागे हुए खोल की तरह महसूस होता है। मृत्यु द्वारा लाया गया यह परिवर्तन इतना प्रभावशाली है और आत्मा को दूसरे लोक में रहने की आदत भी नहीं है, इसलिए वह भ्रमित रहती है। यह मध्य की स्थिति में है। इस अवस्था में ज्ञान सहायता करता है।

जब कोई चला जाता है, तो पंडित मंत्रों का जाप करते हैं। यह आत्मा को याद दिलाते हैं कि आप शरीर, मन या बुद्धि नहीं हैं, इसलिए शरीर को पृथ्वी तत्व में, अग्नि को अग्नि तत्व में और वायु को वायु तत्व में विलीन कर दें। हम शरीर को प्रकृति के साथ एक कर देते हैं। आत्मा, जो अब तक सोचती थी, 'मैं यह शरीर हूं', धीरे-धीरे जागरूक हो जाती है।' अगर मैं यह नहीं हूं, तो क्या हूं? मैं कौन हूं?' यहां ज्ञान में संलग्न होने से उन लोगों को भारी राहत मिलती है, जो पार जा चुके हैं।

ज्ञान के सहारे वैतरणी पार

कहा जाता है आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर जाती है। यहां गाय का अर्थ ज्ञान, गति और मुक्ति भी है। ज्ञान की पूंछ पकड़कर अर्थात थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करने से भी आत्मा नदी पार कर सकती है। इस मध्य अवस्था से आत्मा को 'पितृ लोक' में जाने के लिए कहा जाता है। हम दिवंगत आत्मा को पूर्वजों, पैतृक वंश के लोगों से मिलने के बारे में बताते हैं कि वे किस प्रकार उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आध्यात्मिक यात्रा का एक पड़ाव

कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों में जीवन की अलग-अलग इकाइयां होती हैं। पत्थरों में एक इकाई होती है। पानी में दो इकाइयां होती हैं। अग्नि में तीन इकाइयां होती हैं। पेड़ में छह इकाइयां होती हैं और मनुष्य में जीवन की आठ इकाइयां मानी जाती हैं। इन्हें 'अष्टवसु' कहा जाता है। जो लोग असाधारण कार्य करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनके पास जीवन की नौ इकाइयां होती हैं।

मनुष्य में जीवन की सोलह इकाइयों तक विकसित होने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह अधिक शक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, जीवन की नौ से दस इकाइयों के मध्य। उसकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और उसे कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि हम अपने पूर्वजों का आदर और सम्मान करते हैं। उनमें हम जीवित लोगों की तुलना में अधिक जीवन और चेतना है।

दिवंगत आत्माओं को याद करने की प्रथा किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। दुनियाभर में, विभिन्न परंपराओं और समुदायों के पास दिवंगत लोगों को याद करने के अपने-अपने अनूठे तरीके हैं। सिंगापुर में, यह एक उत्सव का अवसर बन जाता है। यहां ऐसा विश्वास है कि पूर्वजों को दी गई भेंट आशीर्वाद के रूप में वापस आती है।

दिवंगतों को याद करने की प्रथा, चाहे वह श्राद्ध, पितृ पक्ष या अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से हो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में गहरा स्थान रखती है। यह हमारे पूर्वजों का सम्मान करने, उन लोगों से जुड़ने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक उपाय है। यह पवित्र परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती रहे। हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाती रहे। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन करती रहे।

आस्था-अनास्था

डॉ. संजीव कुमार शर्मा

अस्त शुक्र : निर्णय लेने में सावधानी बरतें

अस्त शुक्र के बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे ?

-ध्रुव अटल शास्त्री, मथुरा



शुक्र ग्रह तुला राशि में 23 सितंबर, 2026 को अस्त हो गए हैं। 30 अक्तूबर, 2026 को यह पुनः उदय होंगे। इसी अवधि के दौरान 03 अक्तूबर, 2026 को शुक्र वक्री भी हो रहे हैं। शुक्र के अस्त होने पर सुख और वैभव में कमी आती है। इस दौरान रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आर्थिक सावधानी और बड़े निवेश, महंगी खरीदारी या पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए। अस्त शुक्र का बारह राशियों पर प्रभाव :

मेष : जीवनसाथी या पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे।

वृष : उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राएं, नए अनुबंध लाभकारी साबित होंगे।

मिथुन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थकान से बचें। करियर में काम तेजी से पूरे होंगे।

कर्क : आर्थिक स्थिति में सुधार। पुराने कर्ज या विवादों से राहत मिल सकती है। निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं।

सिंह : स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी। कार्य स्थल पर दबाव कम होगा। कार्य कुशलता बढ़ेगी। विवादों से दूर रहें।

कन्या : धन की आवक पर असर पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। किए गए प्रयासों का उचित फल मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थिरता। करियर में लाभ। नई नौकरी मिल सकती है।

वृश्चिक : खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में सहयोग बढ़ेगा।

धनु : आय के स्रोतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। लेनदेन में सावधानी रखें। करियर और व्यापार में सफलता मिलेगी।

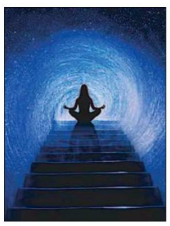
मकर : करियर और कारोबार में मेहनत का फल मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कुंभ : भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

मीन : लंबे समय से रुकी योजनाओं को गति मिलेगी। करियर में तरक्की और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिल सकती हैं।

विचार

अपने कुएं से बाहर निकलिए



दो मेंढकों की कहानी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक कुएं में गुजारा। एक दिन पहला मेंढक कुएं से बाहर कूदकर गायब हो गया। कई दिनों के बाद जब वह वापस लौटा, तो दूसरे मेंढक ने उससे पूछा कि वह कहां था? 'कुएं से बाहर एक पूरी बड़ी दुनिया है', पहले मेंढक ने कहा और उसने उन सभी स्थलों और ध्वनियों का वर्णन करना शुरू कर दिया, जिन्हें उसने देखा और सुना था।

'तुम यह सब बातें बना रहे हो।', दूसरे मेंढक ने कहा। 'इस कुएं के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम इन सभी चीजों की कल्पना कर रहे हो। यदि तुम्हारे द्वारा वर्णित सभी चीजें वास्तव में होतीं, तो वे अवश्य ही कुएं में भी होतीं। मैंने उन्हें नहीं देखा है। वे संभवतः मौजूद नहीं हो सकतीं।'

कई बार हम भी इस दूसरे मेंढक की तरह सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने देखा है, बस वही असलियत है, बाकी इस दुनिया के परे और कुछ भी नहीं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि यह जो दुनिया है, जिसमें हम सब जी रहे हैं, वही असल की दुनिया है, मगर यह जानने के बजाय कि इस दुनिया के परे कुछ और भी है, हम इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं।

कुएं में फंसे दूसरे मेंढक की तरह हम भी अपने दिमाग को बंद करके बैठे हैं। हो सकता है कि प्रयोगात्मक मानसिकता के साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैं देख सकता हूं, उससे कहीं अधिक जीवन में कुछ और भी है। मैं प्रयोग करके देखूं कि मेरे शरीर और मेरे मन के अलावा और भी कुछ है।

एक समय ऐसा था, जब लोगों का मानना था कि पृथ्वी समतल है, लेकिन खोजकर्ताओं ने उन्हें गलत साबित किया और कहा कि दुनिया गोल है। एक समय ऐसा भी था, जब वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर घूम रहा है। उनका यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ।

सदियों से ऐसी दृष्टि वाले लोग आए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है। शास्त्रों और मौखिक परंपराओं द्वारा वे अपने अनुभव उनके शिष्यों के पास छोड़ गए हैं। हम स्वयं को जानने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अभ्यास करके हम अपनी आंतरिक दृष्टि का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें केवल ध्यान-अभ्यास की तकनीक को सीखने की जरूरत है, जिससे हम अंदरूनी ज्योति और श्रुति पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें।

हमारे अंदर यह जानने की ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कि वास्तव में हम 'हम हैं कौन?' हमारे सच्चे स्वरूप को जानने के लिए हममें एक तड़प होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम गंभीरता से कुछ चाहते हैं, तब हम अपना पूरा ध्यान बाकी सब प्रलोभन से हटाकर, उस एक चीज पर लगा देते हैं।

जब हममें अपने सच्चे स्वरूप को जानने की सच्ची इच्छा जाग्रत होगी, तब हम अपना पूरा ध्यान और समय उसे पाने में लगा देंगे और अन्य सभी आकर्षण छूट जाएंगे। जब हम अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमारी आत्मा स्वयं एक धीमी पुकार करती है, जिसे हम सुन सकते हैं। तब आत्मिक शक्ति ही काम करती है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

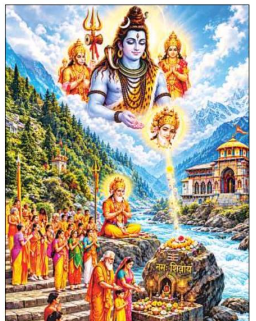
आत्मा की जितनी तीव्र पुकार होगी, उतना ही हमारा ध्यान उसकी तरफ खुद-ब-खुद खिंचा चला जाएगा। इस पुकार के साथ-साथ दुनिया के आकर्षण फीके लगने लगेंगे और हमारा ध्यान आंतरिक प्रेम, खुशी और ध्वनि की ओर खिंचा चला जाएगा।

-संत राजिंदर सिंह

ब्रह्मकपाल में मिलती पितरों को मुक्ति

तीर्थ स्थल/ब्रह्मकपाल

ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जिन पितरों को 'गया' में श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, उनका श्राद्ध 'ब्रह्मकपाल' में करने पर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ स्थित ब्रह्मकपाल में अंतिम श्राद्ध किया जाता है।



पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इनमें भी गया, पुष्कर, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में पिंडदान करने का विशेष महत्व है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ तीर्थ के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित 'ब्रह्मकपाल' क्षेत्र में श्राद्ध के दिनों में किया गया पिंडदान 'गया' तीर्थ में किए गए पिंडदान से आठ गुना अधिक पुण्यदायी है।

ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाल में अंतिम श्राद्ध किया जाता है। इसके पश्चात संबंधित व्यक्ति के निमित्त किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म या पिंडदान नहीं किया जाता है।

ऐसी मान्यता है कि जिन पितरों को गया में श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, उनका श्राद्ध यहां करने पर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा यहां ब्रह्मकपाल के रूप में निवास करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा के पाचवें सिर की आकृति की शिला आज भी मौजूद है।

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार पांडवों ने अपने कुल के नाश के दोष से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहण के समय ब्रह्मकपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। ब्रह्मकपाल की पितरों की मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च तीर्थ के रूप में महत्ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मकपाल में अपने पितरों का पिंडदान व तर्पण करने से उसके कुल के सभी पितृ मुक्त होकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं।

'ब्रह्मकपाल' भगवान बद्रीनाथ के चरणों पर बसा है, इसलिए इस स्थान पर पिंडदान करने से मृत आत्मा को तत्काल मोक्ष मिल जाता है। इस तीर्थ की इतनी महत्ता के पीछे एक कथा है। एक बार ब्रह्मा ने भगवान शिव के सामने झूठ बोल दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा का वह मुख काट दिया, जिससे उन्होंने झूठ बोला था। इस तरह ब्रह्मा के पांच की जगह चार मुख रह गए, जो चार वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का वह कटा हुआ सिर भगवान शिव के हाथ से चिपक गया। काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह सिर अलग नहीं हुआ। इस कथिन में जब शिव बद्रीनाथ में एक समतल स्थान पर पहुंचे, तो उनके हाथ से ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अलग हो गया। उस समय से ही इस स्थान का नाम 'ब्रह्मकपाल' हो गया। शिव ने इस स्थान को वरदान देते हुए कहा, जो व्यक्ति इस स्थान पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा, उसे सीधा मोक्ष मिलेगा।

-अश्वनी कुमार

सप्ताह के व्रत-त्योहार

29 सितंबर से 05 अक्तूबर 2026 तक

29 सितंबर (मंगलवार) : आश्विन कृष्ण तृतीया तिथि सायं 05.11 मिनट तक। अंगारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। भरणी श्राद्ध। तृतीया श्राद्ध।

30 सितंबर (बुधवार) : आश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि दोपहर 02.56 मिनट तक। चतुर्थी का श्राद्ध।

01 अक्तूबर (गुरुवार) : आश्विन कृष्ण पंचमी तिथि दोपहर 12.36 मिनट तक। पंचमी श्राद्ध (दोपहर 12.36 मिनट से पूर्व)। षष्ठी श्राद्ध (दोपहर 12.36 मिनट के बाद)।

02 अक्तूबर (शुक्रवार) : आश्विन कृष्ण षष्ठी तिथि प्रातः 10.16 मिनट तक। महात्मा गांधी जयंती। लालबहादुर शास्त्री जयंती। सप्तमी का श्राद्ध।

03 अक्तूबर (शनिवार) : आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि प्रातः 08 बजे तक पश्चात अष्टमी रात्रि 05.52 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर नवमी तिथि। श्री महालक्ष्मी व्रत संपन्न। जीतपुत्रिका व्रत। अष्टमी का श्राद्ध। अष्टमी तिथि का क्षय।

04 अक्तूबर (रविवार) : आश्विन कृष्ण नवमी तिथि रात्रि 03.54 मिनट तक। सौभाग्यवतीनां श्राद्ध। नवमी का श्राद्ध। मातृ नवमी।

05 अक्तूबर (सोमवार) : आश्विन कृष्ण दशमी तिथि रात्रि 02.08 मिनट तक। दशमी का श्राद्ध।

-पं. ऋभुकांत गोरवामी

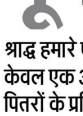
भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

रोजनामचा



पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में विदेश जाने के योग बन रहे हैं।

वृष : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मिथुन : आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

कन्या : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि होगी। सेहत का भी ध्यान रखें।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

वृश्चिक : पढ़ाई के कार्यों में मन लगेगा। कारोबार में बदलाव हो सकता है। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

धनु : मन प्रसन्न तो रहेगा, फिर भी बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मकर : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

कुंभ : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

मीन : वाणी में मधुरता तो रहेगी, परंतु मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

वर्ग पहेली : 8466



बाएं से दाएं

1. जीवट दिखाना; जोखिम भरा काम करने का प्रयास करना; हिम्मत करना (3,3)
5. स्वप्न; ख्वाब (3)
6. अप्रसन्न करना; रुष्ट करना (3,3)
7. पुत्र; बच्चा; लड़का (3)
9. अरण्य; कानन; जंगल; दाव; बियाबान (2)
10. महात्मा; संन्यासी; साधु (2)
11. निष्प्रयोजन; वृथा; फिजूल में; बिना किसी बात के (3)
14. जो एक ही समय में विद्यमान रहे हों; समकालीन; समयानुसार (6)
15. मिलने की क्रिया; भेंट; मुलाकात; समझौता; दोस्ती (3)
16. गिला करना; शिकायत करना (4,2)

ऊपर से नीचे

1. अभ्यास करना; काम सिद्ध करना; आराधना करना; उपासना करना (3,3)
2. समाज की सेवा करने वाला; समाज हितैषी (3,3)
3. एक-एक रग; सभी रग; नस-नस; प्रत्येक नस; सारा शरीर (2,2)
4. नाप जोख; परिमाण; तौल (4)
7. किसी के दिमाग में कोई बात अच्छी तरह बैठाना (2,4)
8. चकमा देना; छल करना; ठगना; धोखा देना; धूर्तता दिखाना (3,3)
12. अभियुक्त को रखने का स्थान (4)
13. चमकने वाला; चमकदार; भड़कीला (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8465 का उत्तर



सुडोकू : 8420

* मध्यम

2						6		3
					1	8		
1	8		6		5			
	3	4		2		9		
			3		6			
		1		5		2	3	
			1		2		6	7
		2	8					
4		7						8

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8419

6	8	7	5	2	3	9	1	4
2	4	1	7	6	9	3	5	8
9	3	5	4	8	1	2	7	6
5	7	6	3	1	8	4	9	2
3	2	4	6	9	7	1	8	5
1	9	8	2	5	4	6	3	7
8	6	3	9	7	2	5	4	1
7	5	9	1	4	6	8	2	3
4	1	2	8	3	5	7	6	9

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

29 सितंबर, मंगलवार, 2026, शक संवत् : 07 आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 13 आश्विन मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम : 17 रबि-उल्सानी, 1448, विक्रमी संवत् : आश्विन कृष्ण तृतीया तिथि सायं 05.11 मिनट तक। वज्र योग, विष्टि (भद्रा) करण सायं 05.11 मिनट तक। चंद्रमा मेष राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 05.11 मिनट तक। अंगारकी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। भरणी श्राद्ध। तृतीया श्राद्ध। गंडमूल प्रातः 09.04 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

फैक्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करने के उपाय :

- उत्तर मुखी फैक्ट्री के मेन गेट पर लाल रंग की बजाय नीला रंग ठीक रहता है। ईशान कोण की ओर जमीन में थोड़ा-सा चांदी का चूरा दबाना ठीक है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में काले रंग की मशीनें लगी हों, तो उन पर पीला रंग करवाना सही रहता है। उत्तर दिशा में छोटे-छोटे गमलों में हरे पौधे लगाना लाभप्रद रहता है। अन्य उपाय में फैक्ट्री में नियमित रूप से कुछ दिन कपूर का पानी छिड़कना फायदेमंद रहता है। फैक्ट्री के अग्नि कोण में किसी प्रकार का रद्दीप रखना नुकसानदायक है। इसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम में रखना ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पीतल का त्रिशूल लगाना भी अच्छा है।

चिंतन

अर्थव्यवस्था के लिए फिर अग्निपरीक्षा

शेयर बाजार की गिरावट को सिर्फ निवेशकों की घटती संपत्ति के आंकड़े से नहीं समझा जाना चाहिए। यह वैश्विक राजनीति और घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते संबंध की चेतावनी भी है। अमेरिका-ईरान में जल्द डील के आसार नहीं दिख रहे हैं, इससे तनाव बना हुआ है। वहीं, रूस-यूक्रेन के बीच तनाव भी बढ़ने लगा है। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बार फिर बाहरी झटकों से निपटने की चुनौती बनी हुई है। सोमवार को सेंसेक्स 1124 अंक यानी 1.52 प्रतिशत गिरकर 72,772 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 360 अंक यानी 1.56 प्रतिशत टूटकर 22,780 पर आ गया। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। लगातार आठवें सप्ताह बाजार में कमजोरी बताती है कि निवेशकों की चिंता किसी एक कंपनी या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वैश्विक तनाव, महंगा तेल और विदेशी पूंजी के रुख में बदलाव बाजार की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इसका असर महंगाई और आम उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ सकता है। यदि पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंचता है तो यह चुनौती और गंभीर हो सकती है। दूसरी तरफ, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से वहां निवेश का आकर्षण बढ़ता है। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। भारत में विदेशी पूंजी की निकासी बाजार पर अतिरिक्त दबाव डालती है। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट को देखकर घबराहट में निर्णय लेना भी उचित नहीं है। बाजार की दैनिक गिरावट और किसी निवेश की दीर्घकालीन स्थिति अलग-अलग विषय हैं। निवेशकों को अपने जोखिम और निवेश अवधि के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। इसी बीच सोने और चांदी की कीमतों में भी 28 सितंबर को गिरावट दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 4133 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये पर आ गया, जबकि चांदी 9297 रुपये सस्ती होकर 2.23 लाख रुपये प्रति किलो रह गई। इस महीने सोने की कीमत करीब 8 हजार और चांदी की कीमत करीब 14 हजार रुपये कम हुई है। कीमती धातुओं में यह उतार-चढ़ाव भी वैश्विक बाजार की बदलती धारणा को दर्शाता है। हालांकि बाजार की हर गिरावट को आर्थिक संकट का संकेत मानना भी सही नहीं होगा। उतार-चढ़ाव शेयर बाजार की प्रकृति है, लेकिन लगातार कमजोरी निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए सावधानी का संकेत जरूर है। सरकार के सामने सबसे बड़ी जरूरत अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित करने की है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना, वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना, महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना, घरेलू निवेश मजबूत करना और घरेलू पूंजी आधार को व्यापक बनाना जरूरी है। भारत की आर्थिक बुनियाद जितनी मजबूत होगी, वैश्विक संकटों का असर उतना ही सीमित किया जा सकेगा। शेयर बाजार, कच्चे तेल और सोने-चांदी की कीमतों में हो रही हलचल को अलग-अलग घटनाओं के बजाय व्यापक आर्थिक परिदृश्य में देखना होगा। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, महंगाई, पूंजी प्रवाह और विकास की बुनियाद को लगातार मजबूत करना होगा। यही इस समय अर्थव्यवस्था के लिए फिर अग्निपरीक्षा है।

महिलाओं के विरुद्ध छिपी सामाजिक हिंसा

डायन प्रथा

प्रो. अरविंद पी भानु, डॉ. भावना बत्रा, वैशाली गुप्ता
(रिसर्च स्कॉलर)

भारत को सदियों से महिलाओं को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक मानने वाली सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। नवरात्र में देवी की पूजा करने वाला यही समाज आज भी देश के अनेक हिस्सों में महिलाओं को 'डायन' घोषित कर सार्वजनिक अपमान, सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा और हत्या तक का शिकार बनाता है। विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, असम तथा अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डायन प्रथा आज भी एक भयावह सामाजिक वास्तविकता बनी हुई है। हाल ही में झारखंड में आयोजित 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध : डायन प्रथा के विशेष संदर्भ में तथा अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका' विषयक राष्ट्रीय कोलोक्वियम ने इस समस्या की गंभीरता को पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया, किंतु वस्तुतः यह समस्या किसी एक राज्य अथवा आयोजन तक सीमित नहीं है। यह भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, लैंगिक असमानता और सामाजिक बहिष्करण की गहरी संरचनाओं को उजागर करती है।

डायन प्रथा को केवल ग्रामीण अंधविश्वास या धार्मिक विश्वास का परिणाम मानना उसकी वास्तविक प्रकृति को समझने में गंभीर भूल होगी। अनेक अध्ययनों और आपराधिक मामलों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को 'डायन' घोषित करना प्रायः संपत्ति हड़पने, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने अथवा कमजोर वर्गों को दबाने का माध्यम बन जाता है। विधवा महिलाएं, अकेली बुजुर्ग महिलाएं, आदिवासी तथा सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित महिलाएं इसका सबसे आसान लक्ष्य बनती हैं। कई बार बीमारी, प्राकृतिक आपदा, पशुओं की मृत्यु, फसल की हानि या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दोष भी महिलाओं पर मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार डायन प्रथा केवल अज्ञानता नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक सत्ता-संबंधों, सामाजिक असमानता और संरचनात्मक हिंसा का रूप धारण कर चुकी है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 'मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अपने मस्तिष्क और बुद्धि का विकास करना होना चाहिए।' यह विचार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। डायन प्रथा जैसी कुप्रथाएं इस आदर्श के ठीक विपरीत खड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि वे विवेक, तर्क और वैज्ञानिक सोच के स्थान पर भय, मिथकों और सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती हैं। विडंबना यह है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, गरिमा और भयमुक्त जीवन का अधिकार प्रदान करता है। यह उल्लेखनीय है कि 1976 की स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऐसे संवैधानिक दायित्व के रूप में परिकल्पित किया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों में तर्कशीलता, मानवतावाद, आलोचनात्मक जिज्ञासा तथा सुधारवादी सामाजिक चेतना का विकास करना था, ताकि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और सामाजिक जड़ता को चुनौती दी जा सके। इस दृष्टि से डायन प्रथा केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा अपेक्षित वैज्ञानिक चेतना और सुधारवादी



समाज की अवधारणा के भी प्रतिकूल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय युवा अधिवक्ता संघ बनाम केरल राज्य (सबरीमला मामला), 2018 में स्पष्ट किया कि संविधान का उद्देश्य केवल परंपराओं को संरक्षित करना नहीं, बल्कि समानता, गरिमा और संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करना भी है। न्यायालय ने कहा कि कोई भी सामाजिक या धार्मिक प्रथा यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे संवैधानिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। इसी प्रकार नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सामाजिक नैतिकता के नाम पर संवैधानिक नैतिकता का बलिदान नहीं किया जा सकता।' यह सिद्धांत डायन प्रथा जैसी अमानवीय और भेदभावपूर्ण कुप्रथाओं पर पूर्णतः लागू होता है। जब किसी महिला को 'डायन' कहकर गांव से निकाल दिया जाता है, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसे निर्वस्त्र घुमाया जाता है अथवा उसकी हत्या कर दी जाती है, तब केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि संविधान की आत्मा पर आघात होता है। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक (1981) तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान, गरिमा और मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी उसमें निहित है। डायन घोषित की गई महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार इस संवैधानिक संरक्षण का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अनेक अवसरों पर इस बात पर बल दिया है कि संविधान का केंद्रबिंदु प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और समान नागरिकता की रक्षा है। वहीं न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का यह विचार आज भी प्रासंगिक है कि 'कानून केवल पुस्तकों में लिखे नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक प्रभावी साधन है।' यदि डायन प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथाएं आज भी महिलाओं का जीवन और सम्मान छीन रही हैं, तो यह केवल समाज की नहीं, बल्कि राज्य, प्रशासन और विधि व्यवस्था की भी सामूहिक विफलता है। डायन प्रथा की गंभीरता को न्यायपालिका ने समय-समय पर रेखांकित भी किया है। विभिन्न मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने विच-हंटिंग को महिलाओं के विरुद्ध क्रूरतापूर्ण हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक न्याय के लिए गंभीर चुनौती बताया है। न्यायालयों ने यह चिंता व्यक्त की है कि अशिक्षा, अंधविश्वास और प्रशासनिक उदासीनता के कारण निर्दोष महिलाओं को सामाजिक प्रताड़ना और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इन टिप्पणियों से स्पष्ट है कि न्यायपालिका डायन प्रथा को केवल आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर आघात के रूप में देखती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत डायन प्रथा को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में न देखकर सामाजिक न्याय, महिला अधिकारों, वैज्ञानिक चेतना और मानवीय गरिमा के प्रश्न के रूप में स्वीकार करे। किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा उसके सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े नागरिकों की सुरक्षा से होती है। जब तक महिलाओं को अंधविश्वास, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के भय से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक संवैधानिक समानता अधूरी रहेगी। भारत को यदि वास्तविक संवैधानिक लोकतंत्र बनना है, तो उसे इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध कानून, शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक जागरूकता और मानवीय संवेदनशीलता - सभी स्तरों पर निर्णायक संघर्ष करना होगा।

(लेखक फ्लैमे यूनिवर्सिटी लोरेडा से जर्मनिक हैं। वे उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

खेल

सैखोम मीराबाई चानू



भारतीय कोचों पर मेरा भरोसा और मजबूत हुआ

एशियाई खेलों में पदक जीतने का अधूरा सपना आखिरकार पूरा हो गया है। यह वह पदक था, जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी और जापान के आइची-नागोया में आखिरकार वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। जापान मेरे लिए हमेशा भाग्यशाली रहा है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में मैंने रजत पदक जीता था और जापान ने एक बार फिर यह सुनिश्चित किया कि मुझे खाली हाथ वापस न लौटना पड़े। एक खिलाड़ी का जीवन आत्मचिंतन और प्रतिक्रिया का जीवन होता है। एशियाई खेलों ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक था दृढ़ संकल्प का। जब भी किसी गंभीर चोट ने मेरे करियर को पटरी से उतारने की कोशिश की, तब हार न मानने का मेरा जज्बा और मजबूत हुआ। आइची-नागोया में मैं अपनी फिटनेस के शिखर पर थी। इसके लिए मुझे अपने कोच, ट्रेनर और फिजियो का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तैयारी कराई। भारतीय बनाम विदेशी कोच की बहस हमेशा चर्चा का गर्म विषय रहती है। भारत में कई ओलंपिक खेलों में विदेशी कोच हैं। मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे ताकत और शारीरिक क्षमता वाले खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल मंत्रालय समय-समय पर विदेशी कोच नियुक्त करता रहा है। हो सकता है कि मुझे कभी विदेशी कोच की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे लिए तो 'ये दिल है हिंदुस्तानी।' राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा के मार्गदर्शन में मेरा करियर परिपक्व हुआ और आगे बढ़ा। जब कोई कोच मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसके साथ आपका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। 2014 से मैं अपने कोच के सुरक्षित मार्गदर्शन में रही हूं। अब सवाल यह है कि क्या हमें भारत में और विदेशी कोच लाने चाहिए या फिर अपने भारतीय कोचों पर भरोसा करना चाहिए? नई खेलो इंडिया योजना में अगले पांच वर्षों और उसके बाद भी खेलों के विकास के लिए व्यापक योजनाएं हैं। इसमें मुझे राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड (एनसीएबी) की स्थापना का प्रावधान दिखाई देता है। जिस तरह राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम का उद्देश्य खेलों में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, उसी तरह एनसीएबी कोचों की योग्यता का मानकीकरण करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि कोई व्यक्ति युवाओं को सही तरीके से प्रशिक्षित करने में सक्षम है या नहीं। हमें जमीनी स्तर पर अच्छे कोचों की जरूरत है। हमारे पास ऐसे कोच होने चाहिए, जो खेल की बिल्कुल बुनियादी बातें सिखा सकें। शुरुआत में किसी जटिल और भारी-भरकम प्रशिक्षण पद्धति की जरूरत नहीं है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन वाला प्रशिक्षण दो अलग-अलग चीजें हैं। कोचिंग कोई ऐसा काम नहीं है, जिसका समाधान रातोंरात निकल आए। दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें अपने देश में तैयार हुए ऐसे कोचों की जरूरत है, जो बुनियादी ज्ञान विकसित कर सकें और पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों की अलग-अलग जरूरतों को समझ सकें, क्योंकि हमारे शरीर एक जैसे नहीं होते। हमारे पास अच्छे और जानकार कोच हैं, लेकिन उन्हें अवसर और पर्याप्त कार्यक्षेत्र दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकें तथा अधिक प्रभावी बन सकें। प्रतियोगिता का स्तर चाहे जो भी हो, पदक खिलाड़ी और कोच के बीच बने रिश्ते का परिणाम होता है। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। कोई भी विदेशी कोच ओलंपिक पदक की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन असफलता मिलने पर उनका उपहास भी नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मेरा मानना है कि भारतीय कोचों पर भरोसा किया जाना चाहिए। विदेशी विशेषज्ञों को हमारे सहायक स्टाफ की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। संशोधित खेलो इंडिया योजना में प्रौद्योगिकी, खेल चिकित्सा और खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए रिकवरी और पुनर्वास बेहतर प्रदर्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मेरे करियर में टोक्यो ओलंपिक से पहले डॉ. एरॉन हॉर्शिंग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉ. हॉर्शिंग न केवल खेलों के फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, बल्कि पूर्व भारोत्तोलक भी हैं। चोटों के उपचार को लेकर उनका दृष्टिकोण बहुत खास था। मेरे मामले में कंधे और पीठ के निचले हिस्से की चोटों के इलाज में उनकी विशेषज्ञता बेहद उपयोगी साबित हुई। यदि हम डॉ. हॉर्शिंग जैसे विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल अपने भारतीय कोचों के साथ कर सकें, तो हमारी सहायक व्यवस्था कहीं अधिक प्रभावी हो जाएगी। मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि भारतीय कोच अच्छे हैं। विदेशी विशेषज्ञों का इस्तेमाल करके हम अपनी सहायक व्यवस्था को किस तरह बेहतर बनाते हैं, यह देखना अभी बाकी है।

(लेखिका भारतीय वेटलिफ्टर हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

मन पतंग, श्वास डोर!

संकलित
दर्शन



केवल एक स्वस्थ कली ही खिल सकती है। उसी प्रकार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही सफल हो सकता है। तो स्वस्थ होना क्या है? यदि आपके भीतर कड़ापन, बेचैनी या असंतोष है, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि मन अस्थिर और अशांत है, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। यदि भावनाएं असंतुलित हैं, तो आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन को शांत, स्थिर और भावनाओं को कोमल रखना आवश्यक है। पूर्ण स्वास्थ्य हमारे भीतर से बाहर और बाहर से भीतर निरंतर प्रवाहित होना चाहिए। संस्कृत में स्व या आत्मा में स्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा अस्तित्व के पांच कोश (परत) होते हैं। पहला है पर्यावरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वायुमंडल- यह हमारा मूल आवरण है। दूसरा है भौतिक शरीर। तीसरा है प्राणमय कोश, अर्थात जीवन ऊर्जा। चौथा है मनोमय कोश, जिसमें विचार, भावनाएं और कल्पनाएं होती हैं। पांचवां है विज्ञानमय या अंतर्ज्ञानमय कोश, जिसमें सहज अनुभूति और गहरी समझ होती है- यह अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली है। जब कोई रोग उत्पन्न होता है, तो वह पहले विचार रूप में आता है, फिर ध्वनि रूप में, फिर प्रकाश रूप में आभामंडल में प्रकट होता है, और अंततः शरीर में दिखाई देता है।

हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा तोहे

संकलित
प्रेरणा



एक बार सूरदास जी चलते-चलते मार्ग में एक गहरे गड्ढे में गिर गए और निकलने के सारे प्रयास असफल हो गये। अपने कान्हा को ही पुकारने लगे, एक भक्त अपने जीवन में विपत्ति काल में प्रभु को ही तो पुकारता है। जैसे ही सूरदास जी ने कान्हा को याद किया, प्रभु भी उसकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए! सच है जब एक भक्त दिल से पुकारता है तो यह टीस प्रभु के दिल में भी उठा करती है। उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, और प्रभु के पांव की नन्ही-नन्ही सी पैजनिया की छन-छन की आवाज सुनते ही सूरदास जी को समझते देर न लगी। कान्हा उनके समीप आये और बोले अरे बाबा नीचे क्या कर रहे हो, लो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी सी मिश्री सी घुली हुई वाणी सुनी तो जान गए की मेरा कान्हा आ गया, और बहुत प्रसन्न हो गए, और कहने लगे की अच्छा कान्हा, बाल गोपाल के रूप में आ गए, कन्हाई तुम आ ही गए न? बाल गोपाल कहने लगे अरे कौन कान्हा ? किसका नाम लेते जा रहे हो, जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज्यादा बातें न बनाओ। सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगेः सच में कान्हा तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं, माना कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है लेकिन तेरे भक्तों का दुःख तुझे नचा देता है। क्यों कान्हा सच है न? तभी तो तू दौड़ा चला आया। जैसे ही उन्होंने इतना कहा सूरदास जी ने झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और उस मंगलमय ब्रह्मसंस्पर्श से वे रोमांचित हो उठे।

अंतर्मन



आज की पाती

घुमंतू परिवारों को स्थायी सहारे की जरूरत

भारत में ऐसे हजारों परिवार आज भी हैं, जिनके बच्चों के लिए नियमित स्कूल तक पहुंच आसान नहीं है। हिमाचल, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के अनेक परिवार पीढ़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए जीवन बिताते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे भी माता-पिता के साथ स्थान बदलते रहते हैं और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। केंद्र सरकार अब इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। यदि स्कूल तक पहुंच, आर्थिक सहायता, आवास, पहचान दस्तावेज और रोजगार के अवसर एक साथ उपलब्ध कराए जाएं, तो घुमंतू परिवारों की अगली पीढ़ी के जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। शिक्षा से जुड़ाव वंचना से बेहतर और स्थायी जीवन की शुरुआत बन सकता है। ऐसे लोगों को प्रेरित करने का सरकार का यह प्रयास सराहनीय होगा। - कार्तिकलाल मांडोत, सूरत

ट्रेंड

पहली एलएनजी ट्रेन

अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से देश को पहली एलएनजी ट्रेन सर्विस की वर्चुअल रूप से शुरुआत की। यह ट्रेन न सिर्फ डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यह ट्रेन हमारे संकल्प को पूरा करेगी। - अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री



पिंकी का शानदार प्रदर्शन

पिंकी बलहारा ने एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के -78 किग्रा कुराश ड्रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के लिए पिंकी को बधाई! उम्मीद है कि वह आगे भी बेहतरीन प्रदर्शन कर भारत का नाम और रोशन करेंगी। - राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री



सांस्कृतिक चेतना

राजनीति से दूर रहते हुए भी अशोक सिंघल ने देशभर के हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाई। उनका जीवन पूरी तरह से भारत माता की सेवा के लिए समर्पित था; उन्होंने देश की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए पूरे हिंदू समाज को एकजुट किया। - धर्मेंद्र प्रधान, सांसद, भाजपा



घटिया सड़क

पूरी सड़क हाथ से छोड़ी जा रही है। दिल्ली में पहले कभी इतनी घटिया सड़क नहीं बनी। कल, जब इसी सरकार के लेकर एक वीडियो बनाया जा रहा था, तो मंत्री प्रवेश वर्मा आधा लो बैठे और एक लड़के को धक्का मार दिया। -अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली



करंट अफेयर

चीन की दीवार का एक हिस्सा खदान के कचरे से क्षतिग्रस्त

चीन की महान दीवार का एक सुदूर हिस्सा पिछले 20 वर्षों से खदान का कचरा फेंके जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। चीन के सरकारी प्रसारक 'सीसीटीवी' की खबर के अनुसार, उत्तर-मध्य चीन में मिंग राजवंश के दौर की इस प्राचीन दीवार के पत्थरों को कोयला खदान के कचरे को सस्ते में ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हांगकांग के अखबार 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने सीसीटीवी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शांक्सी प्रांत की मिंगयू काउंटी में दीवार के एक हिस्से का इस्तेमाल पिछले करीब 20 वर्षों से कोयला खदान का कचरा फेंकने के आसान रास्ते के रूप में किया जा रहा था, जबकि फिक्सलब्लोअर' द्वारा स्थानीय अधिकारियों को बार-बार आगाह भी किया गया था। खबर के अनुसार, महान दीवार के गुआंजियाओ हिस्से को नुकसान पहुंचना 2007 में उस समय शुरू हुआ, जब बिना लाइसेंस के काम कर रही कंपनी 'मिंगयू चाओकाई कोल इंडस्ट्री' ने खनन अपशिष्ट के निपटान के लिए इस संरचना के बीच से तोड़फोड़ की थी। सीसीटीवी ने बताया कि 2015 से फिक्सलब्लोअर द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की जिससे तोड़फोड़ लगभग दो दशकों तक जारी रही।



ऑफ बीट

पृथ्वी के ऊपरी सतह के रहस्यों का पता चला

पृथ्वी आज एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। ग्रह के मैन्मा पर वहानों के इन विशाल स्तैब की निरंतर गति से महाद्वीप बनते हैं और शायद इससे



जीवन का सृजन करने में भी मदद मिली हो। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि अपने शुरुआती रूप में, ग्रह में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं थीं और इसके बजाय इसकी विशेषता स्थिर सतह (एक ढक्कन की कल्पना करें) रही होगी - मंगल ग्रह के समान। दूसरों का कहना है कि इसकी विशेषता एपिसोडिक, स्टॉप-स्टार्ट टेक्टोनिक्स रही होगी। प्लेट टेक्टोनिक्स महासागरों और वायुमंडल की संरचना से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि प्लेटों की निरंतर गति कार्बन और अन्य तत्वों को भी इधर-उधर ले जाती है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी कैसे निकलती है, इससे भी निकटता से जुड़ा हुआ है। इस वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स को पृथ्वी पर जीवन के विकास से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक विशिष्ट रासायनिक फिंगरप्रिंट टेक्टोनिक प्लेटों की गति उनकी सीमाओं पर ज्वालामुखी गतिविधि उत्पन्न करती है। लेकिन द्वीप चापों पर, जैसे कि तथाकथित रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर को घेरता है, इस ज्वालामुखी की एक विशिष्ट रासायनिक फिंगरप्रिंट है जो आज के औसत महाद्वीपीय सतह के लगभग समान है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

जवाबदेही से दूर

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो काम सरकार को खुद करना चाहिए, उसके बारे में या तो अदालतें याद दिलाती हैं या फिर आम जनता को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ता है। यह किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी का मामला होना चाहिए कि आए दिन 'सब ठीक है' के सरकारी दावे के बरक्स ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं, जो कानून-व्यवस्था की लाचारगी को ही दिखाती हैं। दिल्ली में चौकसी के तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में कमी नहीं आ रही है, तो यह प्रशासनिक तंत्र की नाकामी ही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार की कई घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और प्रशासनिक तंत्र को कठघरे में खड़ा किया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को हाल के दिनों में दिल्ली में सामने आए बलात्कार के कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें एक पार्क में सामूहिक बलात्कार और चलती बस के अंदर नाबालिग के खिलाफ यौन हिंसा की घटना भी शामिल हैं। अदालत ने साफतौर पर दर्ज किया है कि दिल्ली-एनसीआर में यौन हिंसा की घटनाएं कानून लागू करने वाली एजंसियों की ओर से बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक व्यवस्थागत विफलता को रेखांकित करती हैं।

कहीं भी जब जघन्य अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि वहां शासन-प्रशासन हालात को संभालने में नाकाम है और इसका खमियाजा आखिरकार साधारण जनता को उठाना पड़ता है। दिल्ली में जब वर्ष 2012 में चलती बस में निर्भया के बलात्कार और उसकी बर्बर हत्या का मामला सामने आया था, तब समूचे देश में आक्रोश फैल गया था। व्यापक आंदोलन के बाद जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर विस्तृत सिफारिशें दी थीं। तब समाज में दिखी जागरूकता और सरकार की सक्रियता से यह उम्मीद बंधी थी कि कम से कम आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराया जा सकेगा। हकीकत यह है कि उस त्रासद घटना के बाद भी न तो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में कमी आई, न ही सरकार या पुलिस की कार्यशैली में कोई खास बदलाव दिखा। ऐसी हर वारदात के बाद अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जैसी सरकारी औपचारिक घोषणाएं होती रहीं, लेकिन आज भी हालत यह है कि आए दिन दिल्ली-एनसीआर में सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात की खबरें अक्सर आती रहती हैं।

इस संबंध में शीर्ष अदालत ने ठीक कहा है कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में जवाबदेही तय करना जरूरी है। आमतौर पर होता यही है कि किसी महिला के खिलाफ यौन हिंसा होती है, तो मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार उस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देती है, वरना वह कोई रोजमर्रा की आपराधिक घटना की तरह गुजर जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है, वह अपनी प्रकृति में निर्भया के साथ हुई घटना की तरह ही है। कुछ घटनाओं में पीड़िता की जान किसी तरह बच गई, लेकिन कई मामलों में लड़की की हत्या कर दी गई। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि यहां की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अपराधियों का रास्ता आसान नहीं होगा। मगर हकीकत यह है कि हत्या और बलात्कार की ज्यादातर घटनाओं में आपराधिक मानसिकता वालों के भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखता। ऐसे माहौल में महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें?

विरोध की चिंगारी

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वे निश्चित तौर पर भरोसे के संकट, लापरवाही और सुरक्षा में कोताही की ओर इशारा करती हैं। विरोध के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर विद्यार्थियों को विश्वास में लेने की गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि परिसर में की गई तोड़-फोड़ में बाहरी लोगों का हाथ है। हालांकि, सच्चाई गहन जांच-पड़ताल के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस घटना से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि हर स्तर पर व्यवस्था का हाल ऐसा क्यों है कि इसमें सुधार के लिए जेन-जी को विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ता है! अगर किसी अप्रिय घटना की आशंका से उपजी नाराजगी को व्यापक विरोध में तब्दील होने दिया जाए, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?

गौरतलब है कि एलपीयू परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा एक छात्रा से बलात्कार किए जाने की सूचना फैलने के बाद विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बीते रविवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया और परिसर में तोड़-फोड़ के साथ विद्यार्थियों की पुलिस से झड़पें भी हुईं। इसके बाद विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीब पंद्रह घंटे तक यातायात अवरुद्ध रखा। विश्वविद्यालय प्रशासन शुरू से यह कहता रहा कि परिसर में बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई है और यह सिर्फ अफवाह है। सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि अगर किसी ने विश्वविद्यालय परिसर में अफवाह फैलाई थी, तो उसे हिंसक विरोध प्रदर्शन में तब्दील कैसे होने दिया गया? इस तरह के संवेदनशील मसले पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? जाहिर है, अगर प्रभावी संवाद के जरिए विद्यार्थियों को भरोसे में लिया गया होता, तो विरोध की चिंगारी को सुलगने से पहले ही शांत किया जा सकता था।

जटिल संघर्षों से उपजी वैश्विक अस्थिरता



रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष राजनीति, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े हैं। स्थायी शांति के लिए सैन्य विकल्पों के बजाय संवाद और कूटनीतिक समाधान जरूरी है।

सुरेश सेठ

रूस वह देश है, जहां लियो टाल्स्टाय ने 'युद्ध और शांति' की रचना के जरिए मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति और शांति की आकांक्षा को उजागर किया था। आज उसी धरती पर युद्ध जैसे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चौथे वर्ष से आगे निकल चुका है और मध्य-पूर्व में अमेरिका तथा ईरान के बीच महीनों से जारी संघर्ष ने वैश्विक अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। सवाल केवल यह नहीं कि युद्ध कब खत्म होंगे, बल्कि यह है कि आधुनिक दुनिया में शांति की राह लगातार इतनी कठिन क्यों होती जा रही है। सितंबर में रूस के संसदीय चुनाव के अंतिम दिन यूक्रेन ने वहां बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि इस दौरान डेढ़ हजार से अधिक ड्रोन मार गिराए गए। हमलों में कुछ लोगों की मौत हुई और एक प्रमुख तेल प्रतिष्ठान को भी नुकसान पहुंचा। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब रूस में 18 से 20 सितंबर तक स्टेट ड्यूमा के चुनाव हो रहे थे। रूस की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 450 सदस्यीय ड्यूमा में 355 सीटें जीतने का एलान किया। इन चुनावों को क्रेमलिन ने युद्ध के बीच अपने शासन और नीतियों के लिए समर्थन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि आलोचकों और कुछ पर्यवेक्षकों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

यहां चुनाव और युद्ध का यह संयोग एक असहज प्रश्न खड़ा करता है कि क्या लंबे समय से चल रहे युद्धों में राजनीति और सैन्य रणनीति एक-दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि शांति की संभावना लगातार पीछे खिसकती जाती है? इसका उत्तर किसी एक देश या नेता के व्यवहार में नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तलाशना होगा, जहां सुरक्षा, सत्ता, संसाधन और रणनीतिक हित एक-दूसरे में उलझ चुके हैं। मध्य-पूर्व की स्थिति इस जटिलता को और बढ़ाती है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष ने होर्मुज जलमार्ग को वैश्विक चिंता का केंद्र बना दिया है। यह दुनिया के महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। इसके आसपास तनाव बढ़ने का असर केवल युद्धरत पक्षों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि तेल, गैस, जहाजरानी, बीमा और आपूर्ति-व्यवस्था के जरिए उसका प्रभाव दूर-दूर तक पहुंचता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी हुई, लेकिन युद्ध समाप्त करने और होर्मुज से आवागमन सामान्य बनाने पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है।

युद्धों की आधुनिक त्रासदी यह है कि उनके लक्ष्य अक्सर सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। कभी युद्ध भू-भाग पर कब्जे के लिए होते थे, अब उनमें ऊर्जा-सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग, रणनीतिक संसाधन, आपूर्ति-शृंखला और तकनीकी वर्चस्व जैसे हित भी शामिल हो गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर युद्ध के पीछे केवल आर्थिक स्वार्थ होता है। राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ऐतिहासिक विवाद और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मगर यह भी उतना ही सच है कि युद्ध जितना लंबा खिंचता है, उसके आर्थिक दुष्परिणाम भी उतने ही व्यापक होते जाते हैं। इसका बड़ा बोझ युद्धक्षेत्र से बाहर का आम नागरिक भी उठाता है। ऊर्जा के दाम बढ़ते हैं, परिवहन महंगा होता है, खाद्य वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं और सरकारी धन का बड़ा हिस्सा विकास के बजाय रक्षा और पुनर्निर्माण पर खर्च होने लगता है। युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों को नहीं निगलता। वह अस्पताल, विद्यालय, सड़कें, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों की संभावनाओं को भी लील लेता है।



> **आज दुनिया को केवल युद्धविराम की नहीं, युद्ध की राजनीति से बाहर निकलने की दीर्घकालिक दृष्टि की जरूरत है। सैन्य शक्ति किसी राष्ट्र को सुरक्षा का एहसास करा सकती है, लेकिन स्थायी शांति केवल हथियारों से नहीं आती। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, प्रतिशोध अगली कार्रवाई का आधार बनता है और फिर बातचीत की मेज तक पहुंचना पहले से अधिक कठिन हो जाता है। ऐसे में शांति के लिए संवाद, पारस्परिक सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक सहयोग और विवादों के राजनीतिक समाधान की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। युद्ध का अंत केवल तब नहीं होता, जब मिसाइलें चलना बंद हो जाएं, बल्कि उस वक्त होता है, जब भय की जगह भरोसा, प्रतिशोध की जगह बातचीत और विनाश की जगह पुनर्निर्माण की राजनीति शुरू हो।**

लियो टाल्स्टाय के समय में युद्ध का मैदान अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देता था। आज ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले और लंबी दूरी के हथियार युद्ध की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। किसी एक देश के भीतर शुरू हुई कार्रवाई का असर कुछ ही घंटों में दूसरे महाद्वीप के बाजारों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत बाजार, बंदरगाह, ऊर्जा-मार्ग और अर्थव्यवस्था भी चुकाती है। सबसे विचित्र स्थिति तब पैदा होती है, जब युद्धरत पक्षों की भाषा में शांति और जमीन पर संघर्ष साथ-साथ चलते हैं। संवाद की अपील होती है, मध्यस्थ सक्रिय होते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बहस होती है, लेकिन दूसरी ओर सैन्य तैयारी और हमले जारी रहते हैं। अमेरिका-ईरान संघर्ष में भी एक ओर बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे हैं और दूसरी ओर होर्मुज जलमार्ग तथा ऊर्जा ढांचे को लेकर दबाव बना हुआ है।

यहां यह मान लेना भी उचित नहीं होगा कि हर युद्ध केवल नेताओं की सत्ता बचाने या हथियार बेचने की इच्छा से चलता है। ऐसे निष्कर्ष अक्सर वास्तविक भू-राजनीतिक जटिलताओं को सरल बना देते हैं। फिर भी राजनीति और युद्ध का संबंध नकारा नहीं जा सकता। चुनावी समय-सारिणी, जनमत, राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति और नेतृत्व की घरेलू मजबूरियां कई बार विदेश नीति के फैसलों को प्रभावित करती हैं। अमेरिका में संभावित मध्यावधि चुनाव नवंबर में हैं और ईरान युद्ध को लेकर वहां राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। विडंबना यह है कि जिन युद्धों को निर्णायक विजय के लिए शुरू किया जाता है, वे अक्सर निर्णायक अंत तक पहुंच ही नहीं पाते। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, प्रतिशोध अगली कार्रवाई का आधार बनता है और फिर बातचीत की मेज तक पहुंचना पहले से अधिक कठिन हो जाता है। इस चक्र में सबसे कमजोर आवाज उसी नागरिक की होती है, जिसके घर पर मिसाइल गिरती है, जिसकी दुकान बंद हो जाती है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता और जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी महंगाई के दबाव में टूटती जाती है।

आज दुनिया को केवल युद्धविराम की नहीं, युद्ध की राजनीति से बाहर निकलने की दीर्घकालिक दृष्टि की जरूरत है। सैन्य शक्ति किसी राष्ट्र को सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति केवल हथियारों से नहीं आती। उसके लिए संवाद, पारस्परिक सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक सहयोग और विवादों के राजनीतिक समाधान की इच्छा चाहिए। युद्ध का अंत केवल तब नहीं होता, जब मिसाइलें चलना बंद हो जाएं, बल्कि उस वक्त होता है, जब भय की जगह भरोसा, प्रतिशोध की जगह बातचीत और विनाश की जगह पुनर्निर्माण की राजनीति शुरू हो। वरना टाल्स्टाय की 'युद्ध और शांति' की रचना मौजूदा समय में सचमुच उलटकर 'शांति की तलाश में युद्ध' बन जाएगी और मानवता अगली पीढ़ी से पूछती रहेगी कि युद्ध खत्म क्यों नहीं होते। बहरहाल, अब देखना यह है कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए किस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाता है।

रुतबे का सफर

सदाशिव श्रोत्रिय

लोग ऐसा मानते हैं कि मोबाइल ने भारतीय जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है, पर मेरी मान्यता है कि उससे भी पहले कार के आगमन ने भी उसे काफी गंभीरता से प्रभावित किया था। कार के आते ही हमारा समाज जैसे दो हिस्सों में बंट गया- कार वाले लोग और बिना कार वाले लोग। आमतौर पर होता यही है कि कार में बैठते ही हम अपने आप को साथ के बहुत से लोगों की दुनिया से अलग कर लेते हैं। उस दुनिया से, जिसमें लोग किसी सड़क पर थूकते हैं और उसी सड़क पर चलते भी हैं। उस दुनिया से, जिसमें लोग अपना सामान खुद ढोते हुए चलते हैं और जिसमें लोगों के लिए बहुत दूर की किसी जगह जाने के लिए सार्वजनिक वाहन ही एकमात्र विकल्प है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर कार किसी व्यक्ति को बाहरी दुनिया से जैसे एक सुरक्षित पनाहगाह में ले जाती है। कार में बैठ कर उसे ऐसा लगता है, जैसे उसने बहुत से आक्रामक बलों से रक्षा के लिए कोई कवच धारण कर लिया हो। जैसे लोग पहले अपने किसी रिश्तेदार से या किसी परिचित से आलंबन की उम्मीद करते थे, वैसे अब वे घूमने के लिए सहारा कार, भूखंड या बैंक में रखे हुए धन में ढूंढ़ते हैं।

अपनी निजी कार में बैठे हुए कोई अपने साथ के बहुत से लोगों से, अपने मां-बाप और उनके सपनों से कट जा सकता है। लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वे सबसे कट जाएंगे। हालांकि इस बात को कोई भी आसानी से समझ सकता है कि भारत में लोगों के लिए आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाना है, तो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को मजबूत करना होगा। मगर आम आदमी के लिए इस सार्वजनिक परिवहन सेवा का हाल आज किसी से छिपा नहीं है।

एक पहलू यह भी है कि किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति पर कार एक बड़ा बोझ है। कार का होना लोगों को आलसी और फिजूलखर्ची बनाता है। अपनी आय का बहुत बड़ा भाग व्यक्ति कार पर खर्च कर डालता है। एक व्यक्ति की तनख्वाह लंबे समय तक अटकती है, तो वह उधार लेकर अपना काम चलाता है। लंबे समय के बाद जब उसे अपनी तनख्वाह का बकाया पैसा मिला, तो उसने देखा कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा वह कार से इधर-उधर घूमने में उड़ा चुका होता है। कार पास में हो, तो व्यक्ति का अकारण ही कहीं भी उसी से जाने का मन हो जाता है। एक बार कार का चस्का लग जाए, तो बस या ट्रेन से यात्रा करना परेशानी भरा लगने लगता है।

कार श्रेष्ठता, शक्ति, प्रगति और साहसिक यात्रा का झूठा आभास कराती है, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति पर एक तरह का बोझ और जिम्मेदारी लादती है। साइकिल चलाना हमारे जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि वह हमारी शारीरिक ऊर्जा को उपलब्धि और साहसिक यात्रा में बदल देता है।

हर व्यक्ति को किसी उपलब्धि के लिए स्वयं कुछ प्रयास और श्रम करना पड़ता है। पर कार को बहुत से लोग एक ऐसी 'रेडीमेड' या तैयार उपलब्धि के रूप में देखते हैं, जिसे एक व्यक्ति दूसरे के पास बिना कोई श्रम किए स्थानांतरित कर सकता है। कार के स्वामित्व से ही व्यक्ति की अहंता में वृद्धि हो जाती है, ऐसी गलतफहमी बहुत-से लोगों को होती है। एक अमीर पिता अपने लड़के या लड़की को एक मंहगी कार दिला कर इस तरह की गलतफहमी पाल लेता है। अपने किसी गुणविहीन पुत्र को एक उम्दा कार दिला कर कई अमीर पिता यह मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी संतान को सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण और सम्मानित बना दिया। इस तरह की सोच हास्यास्पद है, पर कारों के व्यापारी इस मनोवैज्ञानिक सोच से भलीभांति वाकिफ होते हैं।

कार से कहीं भी जाना-आना एक तरह का नशा है, जिसकी लत एक बार लग जाने पर बहुत मुश्किल से ही छूटती है। कार हाथ में आते ही आदमी अपनी हर इच्छित जगह जाने के लिए उतावला हो जाता है। कई बार गैरजरूरी तरीके से भी। इसके लिए उसे कितना ही पेट्रोल और पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस बारे में वह अक्सर सोचना ही बंद कर देता है। अगर कार में घूमने वाला व्यक्ति परिस्थितियां आवागमन के लिए किसी अन्य सार्वजनिक साधन का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाए, तो वह और उसके परिचित इसे उसके 'वर्गच्युत' हो जाने के रूप में ही देखते हैं। कई समृद्ध बुजुर्गों में अक्सर बहुत इधर-उधर जाने की शारीरिक क्षमता शेष नहीं रहती, फिर भी किसी कार का उपयोग करने के लिए वे महीने की तनख्वाह देकर एक ड्राइवर रखते हैं।

कार का स्वामित्व किसी व्यक्ति की सामाजिक चेतना को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर किसी कार वाले को ही अपनी मैत्री और संबंधों के योग्य मानता है। कार-विहीन व्यक्ति ऐसे लोगों की नजर में अक्सर एक कमतर इंसान होते हैं। ऐसे उदाहरण आम हैं, जिनमें किसी कार के मालिक ने गरीब लोगों के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कार में कहीं खरोंच लग गया। कार यात्रा का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे हम समाज के अन्य लोगों के साथ यात्रा के अनुभवों से वंचित हो जाते हैं। उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, उनकी सोच के बारे में जानने के एक अमूल्य अवसर को हम अपनी कार-यात्रा की वजह से खो देते हैं। यह जनतंत्र की मूल भावना और उसके मूल उद्देश्य से ही दूर चले जाने जैसा है। कार खरीदने में समर्थ होते हुए भी यदि कोई कार नहीं रखता है, तो इसे जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी किसी प्रतिबद्धता के द्योतक के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **साइकिल चलाना हमारे जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि वह हमारी शारीरिक ऊर्जा को उपलब्धि और साहसिक यात्रा में बदल देता है। पर कार को बहुत से लोग एक ऐसी 'रेडीमेड' या तैयार उपलब्धि के रूप में देखते हैं, जिसे एक व्यक्ति दूसरे के पास बिना कोई श्रम किए स्थानांतरित कर सकता है।**

आस्था से खिलवाड़



लोक के बीच आस्था उमड़ती है तो उसके साथ बाजार भी सज जाता है। पर्व के वक्त मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। धूप, उमस और घंटों की प्रतीक्षा के बीच भी भक्तों की श्रद्धा कम नहीं होती। लेकिन इसी आस्था के बीच पूजा के नाम पर अलग-अलग दरें तय होना क्या उचित है? सामान्य दर्शन से लेकर विशेष पूजा और वीआइपी दर्शन तक, मानो श्रद्धा भी अब भुगतान की क्षमता से तय होने लगी है। छह सौ रुपए दीजिए और घंटों की कतार से बच जाइए। क्या भगवान के दरबार में भी पैसा रास्ता छोटा कर देता है? बाबाधाम के एक प्रसंग में पुरोहित द्वारा सौ रुपए को 'भीख' कहकर ठुकराने का वीडियो सामने आया। सवाल यह है कि जब श्रद्धा से दिया गया धन स्वीकार्य है तो उसकी कीमत तय करने का अधिकार किसे है? विडंबना यह भी है कि जिन मंदिरों में कभी वंचित समुदायों के प्रवेश पर रोक थी, आज वही समुदाय कांवड़ उठाकर पहुंच रहा है। आस्था सबकी है, तो मंदिर भी सबके होने चाहिए। श्रद्धा को बाजार और भेदभाव से मुक्त करना ही सच्ची धार्मिकता है।

– महेश कुमार केशरी, बोकारो, झारखंड

स्वाभाविक सवाल

'मिलावट के विरुद्ध' (संपादकीय, 26 सितंबर) पढ़ा। आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारी थाली में पहुंच रहा भोजन कितना शुद्ध और सुरक्षित है। डेयरी उत्पादों का आधार दूध ही जब मिलावट के संदेह से घिरा हो, तो उनसे बने उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल स्वाभाविक है। फलों-सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए रसायनों के इस्तेमाल से लेकर मसालों में कृत्रिम रंगों की मिलावट तक, मुनाफे के लिए स्वास्थ्य से समझौते के उदाहरण सामने आते रहे हैं। विडंबना यह है कि भोजन जैसी बुनियादी जरूरत भी अब बाजार की लालच भरी मानसिकता से अछूती नहीं रही। सरकार को खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी और उनके कठोर पालन को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उत्पादकों और उपभोक्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक मुनाफा स्वास्थ्य से बड़ा बना रहेगा, शुद्ध भोजन एक अधिकार के बजाय चुनौती बना रहेगा।

– विकास पंडित, बड़वानी, मध्य प्रदेश

किसकी जवाबदेही

पिछले दस महीनों में निर्वाचन आयोग से जुड़ी चौदह शिकायतें और एक दिन में चार शिकायतों की खबरें महज संयोग मानकर टाल देना आसान है, लेकिन लोकतंत्र में सवालों को टालना इतना आसान नहीं। यदि किसी निर्वाचन आयुक्त को आयोग के महत्त्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मीडिया से मिले, तो फिर संस्थागत संवाद की स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में नए मतदाताओं से मांगी जा रही अतिरिक्त सूचनाओं की वैधानिकता भी स्पष्ट होनी चाहिए। मताधिकार कोई ऐसी सुविधा नहीं जिसे प्रक्रियाओं की भूलभुलैया में उलझा दिया जाए। तकनीकी व्यवस्था के बढ़ते केंद्रीकरण से यदि स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों की पहुंच और अधिकार सीमित होते हैं, तो यह भी गंभीर चिंता का विषय है। आखिर मतदाता का नाम जोड़ने वाला अधिकारी ही उसके आंकड़ों तक सहज पहुंच न रखे, तो जवाबदेही किसकी होगी?

– भगत जारस्ट, लाखनवास, राजस्थान

जातिगत भेदभाव

जाति के आधार पर भेदभाव गंभीर चिंता का विषय है। आइआइटी मुंबई में छात्र साहिल की दुखद आत्महत्या से जुड़ा विवाद इसी चिंता को सामने लाता है। परिजनों और कुछ लोगों ने परीक्षा निरीक्षक पर छात्र को उसकी जाति के कारण प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी में छात्र के मोबाइल से नकल करने और निरीक्षक द्वारा उसकी उत्तर पुस्तिका ले लेने की बात कही जा रही है। वहीं, जिसे मोबाइल कहा जा रहा था, उसके कैलकुलेटर होने की बात सामने आई है। इन परिस्थितियों में आत्महत्या के मामले की गहन जांच हो। साथ ही, नियमों का पालन जाति देखकर नहीं, सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। पारदर्शिता बहुत सारी समस्याओं के सामने समाधान का एक कारगर औजार होती है।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ, उत्तर प्रदेश

सम-सामयिक

बलूचिस्तान : खनिज पर कब्जे की होड़ में बढ़ रहा खून-खराबा

जनसत्ता संवाद

एक तरफ बलूचिस्तान की जमीन के नीचे सोना, तांबा और दूसरे बेशकीमती खनिज हैं तो दूसरी तरफ उसी जमीन पर दशकों से खून-खराबा और अलगाववाद का संघर्ष चल रहा है। अब अमेरिका, चीन और कनाडा की नजर इन खजानों पर है। ऐसे में सवाल है, क्या खनिजों की यह दौड़ बलूचिस्तान का संघर्ष और गहरा कर रही है?

जनवरी और अगस्त 2026 के बीच, बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों और जवाबी कार्यवाहियों में 1,846 लोग मारे गए। इनमें 357 नागरिक, 614 सरकारी सुरक्षा बल और 875 विद्रोही शामिल थे। केवल छह से आठ जुलाई के बीच, बलूचिस्तान में तीन अलग-अलग उग्रवादी हमलों में 42 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस ने संयुक्त रूप से 'आपरेशन शाबान' शुरू किया, जिसके तहत 15 जुलाई तक 123 उग्रवादियों को मार गिराया गया। 15 जुलाई को, बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 11 अगस्त को उसी 'एक्स' खाते से दुनिया से बलूचिस्तान की आजादी को 'कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से' मान्यता देने का आग्रह किया गया।



पाकिस्तान की चाल

बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत (43.6 प्रतिशत) है, लेकिन गैस, कोयले और खनिज संसाधनों का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद, यह विकास के लगभग हर पैमाने पर पीछे है। यह प्रांत 1948 से ही अस्थिरता की स्थिति में है। बलूच जनता पाकिस्तान में प्रांत के विलय को एक स्वेच्छा से किया गया साफ-सुथरा विलय नहीं मानती।

सितंबर 2025 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वाइट हाउस की यात्रा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और रत्नों का एक लकड़ी का डिब्बा भेंट किया। उसी महीने की शुरुआत में, पाकिस्तानी सेना से जुड़े 'फ्रंटियर वर्क्स आर्गनाइजेशन' ने मिसौरी स्थित 'यूएस स्ट्रेटजिक मेटल्स' के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत 500 मिलियन अमेरिकी डालर के शुरुआती निवेश से तीन चरणों में पाकिस्तानी खनिज आपूर्ति शृंखलाओं का विकास करना था। पाकिस्तान के पास छह से आठ ट्रिलियन अमेरिकी डालर के अनछुए खनिज भंडार हैं। इनमें से ज्यादातर भंडार बलूचिस्तान में हैं।

बलूचिस्तान के छिपे हुए खजाने पर सिर्फ अमेरिका की ही नजर नहीं है। कनाडा भी लंबे समय से 'बैरिक माइनिंग' की रेको डिक परियोजना के जरिए जुड़ा हुआ है, जो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब बलूचिस्तान सरकार और बैरिक के संयुक्त स्वामित्व में है। चालू होने पर इसके दुनिया की सबसे बड़ी तांबा-सोना खदानों में से एक बनने का अनुमान है। हालांकि, मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं के कारण इसके काम में बार-बार देरी हुई है। चीन की भागीदारी इससे भी कहीं अधिक गहरी है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) से जुड़ी बुनियादी संरचना और खनन के माध्यम से है। वह वर्तमान में सैंदक खदान (सोना, चांदी, तांबा) चला रहा है, जिसपर इस्लामाबाद को सुरक्षा पर काफी खर्च करना पड़ रहा है।

ऐसे में बलूचिस्तान का आर्थिक उत्पादन पाकिस्तानी सरकार के लिए बहुत मायने रखता है, जो अब अमेरिका, चीन और कनाडा से किए गए वादों की गारंटी के रूप में खड़ा है। जिन जिलों में खदानें और गलियारे स्थित हैं, उन्हीं इलाकों में सक्रिय उग्रवाद के कारण इस उत्पादन को सुरक्षित रखना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और बेहद जरूरी भी।

भारत के लिए, इस अस्थिरता पर करीबी नजर रखना जरूरी है। पाकिस्तान इन आंदोलनों को बदनाम करने और कठोर दमन को सही ठहराने के लिए नियमित रूप से भारतीय हस्तक्षेप का हवाला देता है। जबकि, वहां चल रहा हिंसक विरोध दर्शाता है कि स्थानीय लोग पाकिस्तान के इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

शोध

पहली बार सौर मंडल के बाहरी ग्रह से रेडियो संकेत

जनसत्ता संवाद

दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से करीब 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैस दानव ग्रह 'बीटा पिक्टोरिस बी' से रेडियो संकेत दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह पहली बार है जब सौर मंडल से बाहर के किसी ग्रह (एक्सोप्लैनेट) से आने वाले रेडियो उत्सर्जन की पुष्टि की गई है।

यह खोज परग्रही (एलियन) जीवन मिलने का संकेत नहीं है। लेकिन यह एक्सोप्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्र को समझने का नया रास्ता खोलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इसी तरह के रेडियो संकेतों के अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि दूसरे ग्रह अपने वायुमंडल को तारकीय विकिरण से किस हद तक बचा पाते हैं और किन ग्रहों में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की टीम ने दक्षिण अफ्रीका स्थित मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप ऐरे के 64 डिशों वाले नेटवर्क से बीटा पिक्टोरिस तंत्र का अध्ययन किया। इस दौरान ग्रह बीटा पिक्टोरिस बी से आने वाले बदलते हुए रेडियो उत्सर्जन का पता चला।

सौर मंडल में गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल गैस दानव ग्रह रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इनमें गुरु हमारे सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली रेडियो स्रोत है। इन ग्रहों से आने वाले रेडियो संकेतों का अध्ययन वैज्ञानिकों को उनके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। साथ ही इससे यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रहों के ध्रुवीय क्षेत्रों में आरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति कैसे बनती है। इसी तरह की प्रक्रिया बीटा पिक्टोरिस बी में भी रेडियो उत्सर्जन पैदा कर रही है। जब किसी तारे से ऊर्जावान आवेशित कण निकलते हैं, तो वे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को अपनी क्षेत्र रेखाओं के साथ ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जा सकता है। वहां ये कण ग्रह के वायुमंडल के कणों से टकराते हैं। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति (आरोरा) दिखाई देती है।

इसी दौरान रेडियो उत्सर्जन भी पैदा हो सकता है। यह जानकारी 'डिस्कवरी आफ रेडियो इमिशन फ्राम एक्सोप्लैनेट बीटा पिक्टोरिस बी' शोधपत्र में सामने आई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, रेडियो उत्सर्जन का संबंध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से पैदा होने वाली 'आरोरल' गतिविधि से है। यह खोज इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रह के रेडियो संकेत को उसके तारे से अलग करके सीधे उसी ग्रह से जोड़ा गया है। संकेतों की ये विशेषताएं इलेक्ट्रान साइक्लोट्रान मेजर अस्थिरता से पैदा होने वाले रेडियो उत्सर्जन से मेल खाती हैं। यह वही भौतिक प्रक्रिया है जिसे हमारे सौर मंडल के ग्रहों और कुछ 'अल्ट्राकूल' बौने तारों में 'आरोरल रेडियो' उत्सर्जन से जोड़ा जाता है।

यह कैसे पता चला कि संकेत ग्रह से ही आया? यही इस अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। किसी दूर के तारा-ग्रह तंत्र से रेडियो संकेत मिलने पर 'एक्सोप्लैनेट' प्रणालियों से रेडियो उत्सर्जन के संकेत मिले थे, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें निश्चित रूप से किसी एक ग्रह से नहीं जोड़ पाए थे। बीटा पिक्टोरिस तंत्र में भी शुरुआत में यही सवाल था। शोधकर्ताओं ने रेडियो तस्वीरों में स्रोत की स्थिति को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए बहुत दूर स्थित पृष्ठभूमि को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। इन स्थिर खगोलीय स्रोतों की मदद से रेडियो स्रोत की स्थिति को खगोलीय संदर्भ तंत्र के साथ मिलाया गया।

'बीटा पिक्टोरिस बी' एक विशाल गैस ग्रह है, जो पृथ्वी से करीब 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित बीटा पिक्टोरिस तारे की परिक्रमा करता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की टीम ने दक्षिण अफ्रीका स्थित मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप ऐरे के 64 डिशों वाले नेटवर्क से बीटा पिक्टोरिस तंत्र का अध्ययन किया। इस दौरान ग्रह बीटा पिक्टोरिस बी से आने वाले बदलते हुए रेडियो उत्सर्जन का पता चला।



(फाइल फोटो)

विश्व परिक्रमा

चीन को मिले एफ-35 के कलपुर्जे, अमेरिका ने जांच बिठाई

जनसत्ता संवाद

अमेरिकी रक्षा विभाग इस बारे में जांच कर रहा है कि देश के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान के कलपुर्जे हांगकांग कैसे पहुंचे। जबकि एक मीडिया संस्थान ने बुधवार को अपनी खबर में कहा कि एफ-35 के उपकरण चीन को मिल चुके हैं।

एफ-35 संयुक्त कार्यक्रम से जुड़े कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वह और रक्षा विभाग एफ-35 के कलपुर्जों के मामले में 'एक खेप संबंधी मुद्दे' से अवगत हैं। कार्यालय ने कहा, हम इन कलपुर्जों को वापस हासिल करने, घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने के उद्देश्य से अमेरिकी अधिकारियों और उद्योग जगत के साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।



आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने मीडियाकर्मियों से वार्ता में माना कि विमान के कलपुर्जे हांगकांग पहुंच गए। आस्ट्रेलिया उन कई देशों में शामिल है, जिनकी सेना इस एफ-35 लड़ाकू विमान का संचालन करती हैं। मार्ल्स ने कहा, हम निश्चित रूप से अमेरिका और उसकी प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ इस मामले में काम कर रहे हैं।

दूसरी ओर, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे इस घटना की जानकारी नहीं है, जबकि हांगकांग सरकार ने कहा कि वह विशिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगी। सामाचार एजंसी ब्लूमबर्ग ने बुधवार को खबर दी कि चीन के पास एफ-35 के कलपुर्जे हैं, जिनमें काकपिट कैनोपी और हथियार कक्ष का दरवाजा शामिल हैं। ये कलपुर्जे कई महीने पहले आस्ट्रेलिया से अमेरिका भेजे जाने के दौरान अप्रत्याशित रूप से हांगकांग की ओर मोड़ दिए गए थे। इन्हें या तो मरम्मत या नष्ट करने के लिए भेजा जा रहा था। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि खेप का मार्ग कैसे बदला गया।

जानें-समझें

डिजिटल सामग्री की लत

बच्चों की आनलाइन सुरक्षा का सवाल

जनसत्ता संवाद

इस बात पर बहस तेज हो गई है कि कैसे एल्गोरिदम और फीचर्स बच्चों को नुकसानदेह सामग्री तक पहुंचा सकते हैं और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। बच्चों की आनलाइन सुरक्षा सिर्फ उम्र की पाबंदी या आपत्तिजनक सामग्री हटाने से नहीं होगी, क्योंकि असली असर इस बात से भी पड़ता है कि मंचों पर बच्चों के लिए सामग्री को कैसे डिजाइन किया गया है।



नीतिगत सवाल

भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 96.96 करोड़ दर्ज की गई। 2025-26 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक, यह संख्या एक दशक पहले 25.15 करोड़ थी। ग्रामीण इलाकों में 14 से 16 साल के 89 फीसद बच्चों के घर पर स्मार्टफोन है। सर्वे में डिजिटल लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया है। सेवाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे उपयोक्ता का ध्यान अपनी ओर खींचकर रखें। ऐसे में नीतिगत सवाल यह नहीं है कि बच्चों को आनलाइन कैसे लाया जाता है, बल्कि ये है कि उसके बाद क्या होता है?

अदालत की दखल

कर्नाटक ने मार्च 2026 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार ने उम्र के अलग-अलग दायरों पर विचार किया। जुलाई 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों को 'आनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म' 'रोब्लाक्स' से दूर रखने की याचिका पर नोटिस जारी किया। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद को बताया कि मध्यस्थों (इंटरमीडियरी) को शिकायत मिलने के दो घंटे के भीतर आपत्तिजनक फोटो को हटाना होगा।

फैसले दूसरे के हाथ में

बच्चे का दिन कैसा बीतेगा, यह आनलाइन मंच पहले ही तय कर देता है। किसी मंच का 'रैंकिंग सिस्टम' तय करता है कि 13 साल का बच्चा सबसे पहले क्या देखेगा और प्रोडक्ट टीम किसी पोस्ट की समीक्षा से बहुत पहले ही आटोप्ले और अजनबियों से मैसेजिंग जैसे डिफाल्ट सेट कर देती है। 'कंटेंट माडरेशन' (समीक्षा) पर हुई शोध से पता चलता है कि सबसे अहम फैसले इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर शुरुआती स्तर पर ही ले लेते हैं। 2025 में 1,003 नाबालिगों पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 11 फीसद ने किसी खास मंच पर आनलाइन आपत्तिजनक चर्चा में हिस्सा लिया था। 19 फीसद ने स्नैपचैट, किक और बी-रियल पर ऐसा किया था। वही बच्चे अलग-अलग मंच पर विभिन्न स्तर के जोखिम का सामना कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि जोखिम किसी एक पोस्ट से नहीं, बल्कि मंच से तय होता है। इससे खामी कहां है, इसका पता चलता है।

कानूनी ढांचा

भारत में बच्चों के लिए ऐसे मामलों को लेकर पहले से ही एक कानून है। 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' (डीपीडीपी एक्ट) की धारा 9(2) डेटा फिड्यूशरी (डेटा पर नियंत्रण रखने वाला) को ऐसा डेटा बढ़ाने से रोकती है जिससे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। धारा 9(3) बच्चों की ट्रैकिंग, उनके व्यवहार की निगरानी और उन्हें लक्षित करके विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाती है। 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित नियमों में सहमति की जरूरत है, लेकिन अभी तक बुरे असर के लिए कोई परीक्षण या कोई पैमाना तय नहीं किया गया है।

आस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम 10 दिसंबर 2025 को लागू हुआ। ई-सेफ्टी कमिश्नर की 31 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक तीन महीनों में 10 से 15 साल के बच्चों के बीच खाता रखने वालों की संख्या 52 फीसद से घटकर 42 फीसद हो गई। वहीं, कम से कम एक प्रतिबंधित मंच का इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा 85.9 फीसद से घटकर 81 फीसद के करीब बना रहा।



कई देशों ने कानून के जरिए बच्चों को इन मंच से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सेवा में कमी और निजी चोट के मामलों को कवर करता है। नियम से सभी फीचर्स को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है।
– *ज्योत्सना अत्रे, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ*



आजकल छात्रों का आनलाइन समय बढ़ रहा है और वे नए उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसे में आनलाइन खतरे बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा को समग्र रूप से देखना चाहिए, खासकर अब जब प्रौद्योगिकी बच्चों के जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त है।
– *रूबेन पाल, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ*

आनलाइन कितनी सुरक्षा

सर्वे में शामिल सात फीसद नाबालिगों ने किसी दूसरे बच्चे की कृत्रिम मेधा से बनी आपत्तिजनक तस्वीरें देखी थीं। एनसीआरबी ने 2024 में सूचना तकनीक अधिनियम के तहत बच्चों को लक्षित करने वाले 1,238 साइबर अपराध दर्ज किए। डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में 13 इंटरफेस डिजाइन की पहचान की गई है। इनमें झूठ और सब्सक्रिप्शन का जाल शामिल हैं। इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। पाया गया है कि 47 फीसद नाबालिगों ने निर्धारित न्यूनतम उम्र तक पहुंचने से पहले ही किसी मंच का इस्तेमाल किया था।

– *प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी*

व्यक्तित्व

सावन बरवाल : मैराथन में भारत के लिए रचा इतिहास

जनसत्ता संवाद

सावन बरवाल के लिए इस साल की शुरुआत में मैराथन में जाने का फैसला महत्त्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने शनिवार को यहां एशियाई खेलों में रजत पदक जीता और इसके बाद कहा कि अगर वह यह उपलब्धि हासिल नहीं करते तो यह समय की बर्बादी होती। बरवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैराथन में भारत को अप्रत्याशित रजत पदक दिलाया और इस दौरान अपना ही राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ा। उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी दो घंटे, 11 मिनट और 37 सेकंड में पूरी की। यह मैराथन में उनका लगातार दूसरा राष्ट्रीय रिकार्ड था।



इसी साल अप्रैल में राटरडैम में उन्होंने अपने करियर की पहली मैराथन दौड़ में ही 2:11:58 के समय के साथ शिवनाथ सिंह का 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ दिया था। सेना में कार्यरत इस 28 वर्षीय एथलीट ने कहा, 'यह पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं 15-16 साल से अभ्यास और प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। अगर मुझे यह पदक नहीं मिलता तो यह सब व्यर्थ जाता और समय की बर्बादी होती। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर के रहने वाले बरवाल के पिता कुलदीप नई दिल्ली में ड्राइवर के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां सुभद्रा देवी गृहिणी हैं। बरवाल पिछले एक दशक से भी अधिक समय से लंबी दूरी की दौड़ में भाग ले रहे हैं। उन्हें अपने भाई से प्रेरणा मिली जो स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल थे। एक दिन वह अपने भाई के साथ गए और ट्रैक के किनारे दौड़ने लगे। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में 1500 मीटर की दौड़ के लिए स्कूल की टीम में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर वह पहली बार 2015 में अंडर-18 वर्ग में 3000 मीटर की दौड़ में शामिल हुए। उनका पहला सीनियर स्तर का मुकाबला 2021 में फेडरेशन कप में 5000 मीटर की दौड़ थी। उन्होंने देहरादून में 2025 के राष्ट्रीय खेलों में 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीता। वह 2019 में खेल कोटा के तहत अपने बड़े भाई के साथ सेना में भर्ती हो गए थे।

पुणे के सैन्य खेल संस्थान में यूनिस खान और रिलायंस फाउंडेशन में अजीत मार्कोस जैसे अपने कोच की सलाह पर उन्होंने मैराथन की ओर रुख किया। उनका वीओ2 मैक्स (अधिकतम आक्सीजन ग्रहण क्षमता) उच्च पाया गया था, जो उन्हें 42.195 किमी की दूरी के लिए बहुत अच्छा धावक बनाता है। बरवाल ने कहा, मुझे मैराथन में अच्छा प्रदर्शन करने का पूरा भरोसा था। इसलिए यह सही फैसला था। बरवाल से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता था कि वह अपनी पहली दो मैराथन दौड़ में ही राष्ट्रीय रिकार्ड बनाएंगे, उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ने के लक्ष्य के साथ ही मैराथन में भाग लिया था। मैराथन में भारतीय एथलीट दो घंटे 12 मिनट से कम समय नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया। मैंने स्वयं से कहा कि अगर मैं दो घंटे 12 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाता, तो मैराथन दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। एशियाई खेलों में हालांकि उनका पूरा ध्यान पदक जीतने पर था।

दिल की उम्र भी बढ़ती है

25 की उम्र के बाद हर दस साल में ऐसे बदलता है दिल



डॉ. अश्विन मेहता
डायरेक्टर हार्ट फेल्योर प्रोग्राम, सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली

20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं।

30 से 40 की उम्र : 5 से 10 फीसदी तक कम हो सकती है ब्लड पम्प करने की क्षमता

- अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पम्पिंग क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पम्प करने की अधिकतम क्षमता 5-10% कम हो सकती है।

ध्यान रखें : बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही हो तो जरूर पता करें।

40 से 50 साल : दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है सख्ती

- दिल की मांसपेशी कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती है। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

ध्यान रखें : इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खर्राटों को नजरअंदाज न करें। इनका इलाज कराएं।

50 से 60 साल : दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है

- दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वह क्षमता, जिसके जरिए वह जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है, घटने लगती है।

ध्यान रखें : सप्ताह में दो दिन स्क्वाट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।

60 से 70 साल : दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है, शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता

- जरूरत पड़ने पर कार्यक्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलने, सीढ़ियां चढ़ने या लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है।

ध्यान रखें : लेटने पर सांस फूलने या पैरों-टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।



250 मिनट

2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। यह शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था।

सेहतमंद का फार्मूला

ये पांच बातें भी बहुत काम की



रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।



अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।



व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में एक घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50 फीसदी तक कम कर सकती है।

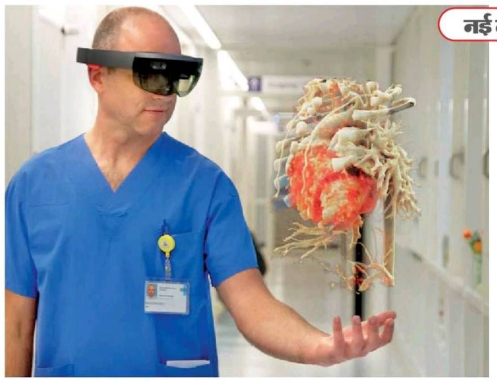


ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।



हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।

नई तकनीक



होलोग्राम से मिल रही सर्जरी में मदद

तस्वीर जर्मनी के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की है। इसमें एक सर्जन होलोलेंस के जरिए मरीज के दिल का 3-D होलोग्राम देखकर विश्लेषण कर रहे हैं। होलोग्राम तकनीक की मदद से जटिल हार्ट सर्जरी से पहले दिल की बनावट समझने और ऑपरेशन की योजना बनाने में काफी मदद मिलती है।

हैल्दी हार्ट टिप्स

दिल की सेहत के तीन संकेत, एक जरूरी बचाव

1. **मसूड़ों** की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
2. **हाथों** की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैंसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
3. **सामाजिक** अलगाव और अकेलेपन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30 फीसदी तक बढ़ जाता है। हॉर्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
4. **फ्लू** वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28 फीसदी, मिनी स्ट्रोक का 47 फीसदी और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85 फीसदी तक कम होता है।

- वेब एमडी और हॉर्वर्ड की रिसर्च

दुनिया की हार्ट साइंस

1950 के मुकाबले दिल की बीमारियों से मृत्यु का जोखिम करीब 75 फीसदी घटा

10 पड़ाव, जिन्होंने सुधारी दिल की सेहत

दिल की धड़कन को पहली बार ठीक से रिकॉर्ड करने से लेकर दिल के खतरों को पहचानने तक, विज्ञान ने लंबा सफर तय किया है। हर पड़ाव पर मिली एक नई जानकारी ने दिल को देखने और बचाने का तरीका बदल दिया। पढ़िए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पड़ावों के बारे में...

1929 | जर्मनी- नस के रास्ते दिल तक पहुंचा कैथेटर

वर्नर फोर्समैन ने अपने हाथ की नस से कैथेटर दिल के दाहिने हिस्से तक पहुंचाया।
सीख- रक्त वाहिकाओं के रास्ते बिना छाती खोले भी दिल तक पहुंचा जा सकता है।

1967 | अमेरिका- बायपास ने बनाया खून का नया रास्ता

रेने फेलाोरो ने पैर की नस से कोरोनरी आर्टरी बायपास तकनीक विकसित की।
सीख- दिल की धमनी में रुकावट हो तो दूसरी रक्त वाहिका से रास्ता बनाया जा सकता है।



1984-87 | स्वीडन- कमर-कूल्हे का अनुपात भी खतरा

गुटेनबर्ग में हुए अध्ययन में कमर-कूल्हे का अनुपात अधिक होने को हार्ट अटैक के जोखिम से जोड़ा गया।
सीख- पेट के आसपास जमा ज्यादा चर्बी से भी हार्ट अटैक का जोखिम।

1948 | अमेरिका- बीमारी से पहले ही दिखे दिल के छिपे खतरे

फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी से पता चला कि हाई बीपी और धूम्रपान हृदय रोग के प्रमुख जोखिम हैं।
सीख- बीपी, कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी का संकेत।



2002 | फ्रांस - कैथेटर से पहला हार्ट वॉल्व रिप्लेस किया गया

पहली बार 12 साल के बच्चे में ट्रांसकैथेटर हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट किया गया।
सीख- यहां से बिना छाती खोले हार्ट वॉल्व बदलने की राह खुली

2021 | चीन- 600 गांवों में नमक का प्रयोग

21 हजार लोगों को 75% सोडियम क्लोराइड नमक देने पर स्ट्रोक 14% तक कम हुए।
सीख- सॉल्ट सब्स्टीट्यूट स्ट्रोक का जोखिम घटाने में मदद कर सकता है।

1958 | जापान- जब पता चला खानपान व दिल का संबंध

7 देशों की स्टडी में हाई सेचुरेटेड फैट्स वाले खानपान का संबंध हृदय रोगों से पाया गया।
सीख- ज्यादा संतृप्त वसा खाने वाले दिल की बीमारी के जोखिम से ज्यादा जुड़े हैं।

1986 | इटली- सही समय व स्ट्रेप्टोकाइनेस लाभदायक

11,806 मरीजों पर स्टडी- थक्का घोलने वाली स्ट्रेप्टोकाइनेज से मृत्यु दर घटी।
सीख- हार्ट अटैक में जितनी जल्दी प्रभावी इलाज मिले, परिणाम बेहतर हो सकता है।

1988 | ब्रिटेन- एस्पिरिन ने बदला हार्ट अटैक का इलाज

ऑक्सफोर्ड के नेतृत्व में 17,187 मरीजों पर एस्पिरिन का प्रयोग हुआ।
सीख- थक्का बनने की प्रक्रिया पर उपचार जान बचा सकता है।

2022 | द. कोरिया- लोगों के खानपान पर 10 साल नजर

6,565 लोगों की सीफूड आदतों की स्टडी के अनुसार इससे खतरा कम होता है।
सीख- सीफूड दिल की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है।

अभिव्यक्ति

प्रेरणा

अपने आस-पास केवल उन लोगों को इकट्ठा करिए, जो आपको ऊपर उठा सकते हैं।-**ओपरा विनफ्रे**

संपादकीय

किसानों-गरीबों की क्रय-शक्ति बनाए रखना जरूरी है

देश के आधे से ज्यादा भाग में सूखे से खेती का रकबा घटा है यानी उत्पादन गिरेगा। आमतौर पर ये राज्य धान, सोयाबीन, दाल, मक्का, कपास और गन्ना के क्षेत्र हैं। चावल गरीबों का प्रमुख भोजन है, जबकि देश की जरूरत भर की दालें पैदा नहीं होतीं। इन्हें आयात करना पड़ता है। सरकार भले ही आगामी उत्पादन को लेकर नाउम्मीद नहीं हुई हो लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पैदावार में भारी गिरावट होगी। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक यूपी में बीते वर्ष 2025-26 में पिछले आठ वर्षों के मुकाबले रकबा भी घटा है, पैदावार भी। मिलों में रिकवरी (प्रति टन गन्ने में चीनी की मात्रा) भी कम रही। इसी बीच डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर बना रहा यानी इन जिंसों का आयात महंगा होगा। कुल का संकट जारी है। रुपया कमजोर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसके उलट उत्पादन घटने के कारण किसानों की क्रय-शक्ति और घटेगी, जिससे रोजमर्रा के सामान का उठान कम होगा। अर्थशास्त्री रेग्नर का आर्थिक दुष्चक्र का सिद्धांत बताता है कि सामान्य उपभोग के सामान खरीदने कम होने से भी छोटे उद्योगों पर संकट बढ़ता ही है और इससे रोजगार भी घटता है। लिहाजा सरकार विकास-व्यय को थोड़ा लचीला बनाते हुए फिलहाल गैर-तात्कालिक जरूरत वाले पूंजीगत निवेश, जैसे हाईवेज और एयरपोर्ट्स पर खर्च घटाकर इसे किसानों-गरीबों की क्रय-शक्ति बनाए रखने में लगाए।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com



भक्ति में ताजगी, जागरूकता, चौकन्नापन और समर्पण मांगें

भक्तों की दुनिया में यह चर्चा बहुत होती है कि क्या भगवान से मांगा जाए? एक वर्ग कहता है भगवान सब जानता है तो क्यों मांगा जाए? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान परमपिता है, अपने माता-पिता से मांगने में क्या दिक्कत है? तुलसीदास जी ने बताया कि काकभुशुंडि जी ने गरुड़ जी को कहा- मन भावत वर मागऊँ स्वामी, तुम्ह उदार उर अंतरजामी। हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अब इसी चौपाई में एक वक्तव्य दूसरे को खंडित कर रहा है। आधे में है कि मैं मांग रहा हूं और दूसरे में है कि आप सब हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान भक्त के हृदय की बात जानते हैं। तो ईश्वर से जब भी मांगें, भौतिक वस्तु न मांग कर कहें कि हमें भक्ति में ताजगी, जागरूकता, चौकन्नापन और समर्पण प्रदान करिए। बाकी वस्तुएं तो हम कमा लेंगे और गंवा देंगे। पर यदि देना चाहें तो इतनी बातें दे दीजिए। दुर्गुणों से बचने के लिए हिरण की तरह हमें चौकन्ना बना दीजिए। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • लोकतंत्र में जवाबदेही तय करनी होगी

'काम नहीं, तो वोट नहीं' का सिद्धांत अपनाएं तो क्या होगा?

राजनीति



पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में एक नागरिक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सड़क के लम्बित कार्य को लेकर शिकायत की। उसका टोटूक संदेश था : सड़क बनवाइए, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। मांग रखे जाने के इस तरीके पर सिंधिया आपत्ति जताते दिखाई देते हैं और नागरिक से कहते हैं कि धमकी देने के बजाय अनुरोध करें। लेकिन इसके बाद सड़क के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी जाती है और जरूरी प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दे दिए जाते हैं।

सिंधिया लंबे समय से मेरे मित्र हैं। वे एक भले व्यक्ति और सक्षम मंत्री हैं। इसलिए यह घटना उनके बारे में नहीं, बल्कि इससे मिलने वाले सबक के बारे में है। हमें यह सरल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि नागरिक की धमकी की वजह से सड़क का काम मंजूर हुआ। दरअसल, खबरों की मानें तो इसकी डीपीआर पहले ही तैयार हो चुकी थी। सिंधिया की मंशा पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं हो सकता। लेकिन यह घटना लोकतंत्र की एक बुनियादी बात को सामने लाती है : मतदाता याचक नहीं होता, और सड़क आदि सुविधाएं उपलब्ध कराकर नेता भी नागरिक पर कोई उपकार नहीं कर रहे होते हैं। सड़कों का निर्माण सार्वजनिक धन से किया जाता है, जिसके संग्रह का स्रोत भी नागरिक ही है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के धन और जनहित के बीच एक माध्यम है। इसलिए यह रिश्ता अनुकम्पा नहीं, उत्तरदायित्व का होना चाहिए।

लेकिन समय के साथ हमने जाने कैसे ऐसी राजनीतिक संस्कृति बना डाली है, जिसमें नागरिक अकसर याचक की मुद्रा में राजनेता के पास पहुंचता है। चुनाव के समय राजनेता भी नागरिक के सामने इसी शैली में आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मतदाता यह सिद्धांत अपना लें कि काम नहीं, तो वोट नहीं, तो क्या होगा? गुस्से भरे नारे के रूप में नहीं, धमकी के रूप में भी नहीं, बल्कि यह जवाबदेही तय करने का एक संवैधानिक लोकतांत्रिक माध्यम हो।

अलबत्ता शोध बताते हैं कि भारतीय मतदाताओं ने हमेशा ही इस तरह का व्यवहार नहीं किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई करीब 1.8 लाख ग्रामीण सड़कों का अध्ययन करने वाले एक बड़े शोध में पाया गया कि सड़कों के निर्माण से सत्तारूढ़ दल को अधिक चुनावी समर्थन नहीं मिला। सड़कें ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जो साफ दिखाई देती हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, फिर भी उन्हें उपलब्ध कराने से चुनावी जीत की वह गारंटी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है।

ऐसा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ यह नहीं हो सकता कि भारत के लोग आसानी से बहकावे में आ जाने वाले हैं। ऐसा कहना न केवल उनके लिए अपमानजनक, बल्कि गलत भी होगा। भारतीय मतदाता जटिल राजनीतिक गणनाएं करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वे अकसर सत्ता-परिवर्तन करके सरकारों को दंडित करते हैं। समस्या यह है कि राजनीति में प्रदर्शन केवल एक कसौटी है, जिसके आधार पर मतदाता फैसला करते हैं। पहचान दूसरी कसौटी है। जाति मायने रखती है। धर्म मायने रखता है। समुदाय के प्रति निष्ठा मायने रखती है। राष्ट्रीय नेतृत्व मायने रखता है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मायने रखता है। राजनीतिक नैरेटिव मायने रखते हैं। भावनात्मक मुद्दे मायने रखते हैं। और जब चुनाव पहचान और नैरेटिव के बीच मुकाबला बन

भावनात्मक मुद्दे मायने रखते हैं। जब चुनाव पहचान और नैरेटिव के बीच मुकाबला बन जाए, तो घर के बाहर मौजूद खस्ताहाल सड़क अजीब तरह से मतपेटी से गायब हो सकती है। यही भारतीय मतदाता का बड़ा विरोधाभास है।

जाए, तो घर के बाहर मौजूद खस्ताहाल सड़क अजीब तरह से मतपेटी से गायब हो सकती है।

यही भारतीय मतदाता का बड़ा विरोधाभास है। एक नागरिक के रूप में तो हम जमकर शिकायतें करते हैं, लेकिन मतदाता के रूप में बहुधा अलग तरह से वोट देते हैं। हम सड़क के गड्ढों को कोस सकते हैं, लेकिन चुनाव में किसी बिल्कुल अलग मुद्दे पर वोट दे आ सकते हैं। हम प्रदूषण, भ्रष्टाचार या बदहाल नागरिक सुविधाओं पर घंटों चर्चा कर सकते हैं और फिर चुनावी बहस को ऐसे मुद्दों के हाथों में जाने दे सकते हैं, जिनका हमारे रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता से बहुत कम संबंध है। शायद राजनेताओं ने भी इसे समझ लिया है।

समाधान यही है कि नागरिक संगठित हों, ताकि अपने वोट की ताकत का अधिकतम प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। 'काम नहीं, तो वोट नहीं' का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि नागरिक किसी विपक्षी दल के प्रति अपनी निष्ठा तय कर लें। इसका मतलब यह होना चाहिए कि हर दल और हर जनप्रतिनिधि यह समझे कि मतदाता जवाबदेही और काम चाहता है और उसी के अनुसार अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। भारतीय लोकतंत्र में यही वह बदलाव है, जो अब तक नहीं आया है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

दूरदृष्टि • समय से पहले ही सजग हो जाना जरूरी

दिल की बीमारियों के उजागर हो जाने की राह मत देखिए

हेल्थ



डॉ. नरेश त्रेहन
सीएमडी, मेदांता हॉस्पिटल

पहले यह धारणा आम हुआ करती थी कि हृदय रोग की बीमारी अधेड़ उम्र के बाद ही शुरू होती है। लेकिन अब यह सोच हकीकत से तेजी से दूर होती जा रही है। सच्चाई तो यह है कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां अकसर उम्र की तीसरी या चौथी दहाई के लोगों को प्रभावित करती हैं, जो अपने निजी और पेशेवर जीवन के सबसे सक्रिय दौर में होते हैं।

मुद्दे चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि कितने कम उम्र के मरीज हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि इस बात की भी है कि रिस्क फैक्टर्स को कितने लंबे समय तक अनदेखा किया जाता है। हाई ब्लडप्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर और मोटापा वर्षों तक हृदय रोग का खतरा बढ़ाते रह सकते हैं, लेकिन इनके कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। जब तक किसी कार्डियक समस्या का सामना करना पड़ता है, बचाव का मौका पहले ही हाथ से निकल चुका होता है।

भारतीयों की बदलती जीवनशैली भी इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। लंबे समय तक डेस्क पर बैठे रहना, कसरत या शारीरिक गतिविधियों की कमी, अनियमित नींद, प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन और तंबाकू का इस्तेमाल- ये सब मिलकर ऐसे जोखिम पैदा कर रहे हैं, जिन्हें युवा आबादी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तनाव भी आधुनिक जीवन की एक हकीकत है, खासकर युवा पेशेवरों के लिए, और स्वास्थ्य के प्रति व्यापक नजरिए में इस पर भी ध्यान देना होगा।

प्रिवेंशन पर आधारित हेल्थकेयर को हमारी स्वास्थ्य-व्यवस्था का नियमित हिस्सा बनाना जरूरी है। युवाओं को अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने के लिए लक्षणों का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा है, उनकी पहचान तो समय रहते ही कर ली जानी चाहिए और उन्हें उचित सलाह दी जानी चाहिए।

हमें यह सोचने का तरीका भी बदलना होगा कि कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य को किस तरह देखा जाता है। जब लंबे समय तक काम करना, लगातार बैठे रहना और पर्याप्त नींद न लेना सामान्य बात बन जाती है, तो देर-सबेर इसका असर हेल्थ पर पड़ता ही है। नियोक्ता काम के दौरान लोगों को बीच-बीच में उठकर चलने-फिरने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, नियमित जांच की सुविधा दे सकते हैं और स्वस्थ विकल्पों को अधिक आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं।

लोगों को हृदय रोग के लक्षणों के बारे में भी अधिक जागरूक होने की जरूरत है। सीने में बेचैनी, सांस फूलना, बिना किसी वजह के पसीना आना, मितली, चक्कर आना या हाथ, कंधे, पीठ अथवा जबड़े तक फैलने वाली बेचैनी आदि सिम्पटम्स को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता मिलना जीवन बचा सकता है।

प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी रोकथाम पर आधारित चिकित्सा में हुई प्रगति से अब हृदय रोग के खतरे की पहचान पहले ही करना संभव हो रहा है- अकसर लक्षण दिखाई देने से भी पहले। इससे डॉक्टरों को बीमारी के गंभीर या आपात स्थिति में बदलने से पहले ही जरूरी कदम उठाने का मौका मिलता है।

कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के क्षेत्र में हमारी अगली बड़ी उपलब्धि रोकथाम ही होनी चाहिए। हमें जोखिम

आज सवाल यह नहीं है कि युवा भारतीयों को हृदय रोग का खतरा है या नहीं। वह तो स्पष्टतया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे को इतना पहले पहचानने के लिए तैयार हैं कि उसके बारे में कुछ किया जा सके?

की पहचान पहले करनी होगी, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना होगा और नियमित हेल्थकेयर का हिस्सा बनाकर बचाव संबंधी जांचों को आम बनाना होगा। परिवारों, स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य व्यवस्था- सभी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हृदय की सेहत पहली बार लक्षण सामने आने से बहुत पहले ही प्रभावित होने लगती है।

युवा भारत को हृदय-रोग के बारे में केवल तभी नहीं जानना चाहिए, जब उसे खुद किसी गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़े। अगर हम समय रहते कदम उठाएं, तो बीमारी के दुष्परिणामों से निपटने के बजाय उसके पूरे क्रम को ही बदल सकते हैं।

इसीलिए सवाल यह नहीं है कि कम उम्र के भारतीयों को हृदय रोग का खतरा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे को इतना पहले पहचानने के लिए तैयार हैं कि उसके बारे में कुछ किया जा सके? **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

कार बाजार • एसयूवी के मुकाबले कम कीमत, बड़े केबिन-बूट स्पेस और चलाने की कम लागत से बढ़ी छोटी सेडान की लोकप्रियता

एसयूवी के दबदबे के बीच एंट्री लेवल सेडान की बिक्री 19% बढ़ी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

देश के कार बाजार में एसयूवी की हिस्सेदारी करीब 66% हो चुकी है। इसके बावजूद एंट्री-लेवल (कॉम्पैक्ट या छोटी) सेडान की मांग बनी हुई है।

जैटो डायनेमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस सेगमेंट की बिक्री 2024 की 2.71 लाख से बढ़कर 2025 में 3.22 लाख हो गई। यानी 51,293 ज्यादा कारें बिकीं। कॉम्पैक्ट सेडान की बाजार हिस्सेदारी भी 2024 के 6.2% से बढ़कर इस साल जनवरी-अगस्त में 7.1% हो गई। हालांकि, इसी अवधि में मिड-साइज सेडान की हिस्सेदारी 1.7% से घटकर 0.9% रह गई। छोटी सेडान बाजार को एसयूवी के मुकाबले कम कीमत, बड़े केबिन-बूट स्पेस और चलाने की कम लागत का सपोर्ट मिल रहा है।

2025 • एंट्री लेवल सेडान की सालाना बिक्री 3.2 लाख पार

अवधि	बिक्री
2024	2,71,082
2025	3,22,375
जन.-अग.-26	2,52,110

2026 • कार बाजार में छोटी सेडान की हिस्सेदारी 7.1%

मॉडल	बिक्री	मार्केट शेयर
मारुति डिज़ायर	1,68,413	66.8%
हुंडई ऑरा	49,517	19.6%
होंडा अमेज़	26,676	10.6%
अन्य	7,504	3.00%

ग्रोथ इंजन: सीएनजी मॉडल्स, बिक्री हर साल 46% बढ़ रही

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी-सीईओ शैलेश चंद्रा के मुताबिक, एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट में सीएनजी मॉडलों की रिटेल बिक्री सालाना करीब 46 फीसदी बढ़ रही है। यह पूरी कार इंडस्ट्री की ग्रोथ से लगभग दोगुनी है।

सेगमेंट	सीएनजी की हिस्सेदारी
मुकम्मल कार बाजार	20-25%
कॉम्पैक्ट सेडान	60%
निजी खरीदार	53%
फ्लीट (टैक्सी आदि)	73-75%

सीएनजी मॉडल भी इस सेगमेंट की मांग बढ़ा रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) के एमडी-सीईओ शैलेश चंद्रा के मुताबिक, कॉम्पैक्ट सेडान की करीब 60 फीसदी बिक्री सीएनजी मॉडल की है, जबकि पूरे कार बाजार में इनकी हिस्सेदारी 20-25 फीसदी है।

कीमतें बढ़ रहीं, इसलिए किफायती कॉम्पैक्ट सेडान का बड़ा साइज अब ग्राहकों को आकर्षित कर रहा

हैचबैक से सेडान में जाना बड़े साइज का अहसास देता है। पर दाम और एसयूवी के विकल्प बढ़ने से सेडान पर दबाव बना रहेगा।

अवधि	कारों के औसत दाम
5-6 साल पहले	₹6-7 लाख
इस साल	₹11-12 लाख
5 साल में (अनुमान)	₹15-16 लाख

छोटे शहरों के खरीदार बढ़ा रहे कॉम्पैक्ट सेडान की मांग

बड़े शहर: कॉम्पैक्ट सेडान की मांग में टैक्सी आदि की भूमिका ज्यादा है।

छोटे शहर, ग्रामीण बाजार: यहां निजी खरीदारों की आकांक्षा वाली मांग ज्यादा देखी जा रही है।

फ्लीट की प्राथमिकता: माइलेज, रखरखाव पर कम खर्च।

निजी ग्राहकों की प्राथमिकता: डिजाइन, सेफ्टी, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी।

स्रोत: जैटो डायनेमिक्स

कंपनियों को डर कि सेडान चाहने वाले ग्राहक छूट जाएंगे

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने टैक्सी कंपनियों के लिए खास मॉडल एक्सप्रेस और प्राइवेट खरीदारों के लिए एरिस को अलग रखा है। चंद्रा ने कहा, 'अगर एरिस न आती तो सेडान चाहने वाला ग्राहक हाथ से निकल सकते थे। कंपनी ने मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाने की तैयारी भी की है।' अन्य कंपनियां भी यही कर रही हैं।

पहली बार कार खरीदने वालों का पसंदीदा मॉडल

- मोबिलिटी ग्लोबल के इंडिया एंड आसियान डायरेक्टर पुनीत गुप्ता का कहना है कि छोटी सेडान अब एसयूवी से सिर्फ बॉडी स्टाइल में नहीं, वैल्यू प्रपोजिशन में भी मुकाबला कर रही है।
- चलाने का कम खर्च, बड़ा केबिन व बूट स्पेस और सीएनजी का विकल्प इसे वैल्यू-कॉन्शस और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए प्रासंगिक बनाए हुए हैं।
- मारुति के सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी के मुताबिक, चौथी पीढ़ी की डिजायर के करीब 50% खरीदार युवा और पहली बार कार खरीदने वाले लोग हैं।

मनी मैनेजमेंट

ऑटो-डेबिट घरेलू बजट बिगाड़ रहा...

छोटे सब्सक्रिप्शन पर हर साल ₹20 हजार तक खर्च

भास्कर न्यूज | मुंबई

ऑनलाइन सर्विसेज के छोटे मासिक सब्सक्रिप्शन धीमे-धीमे आम आदमी का बजट बिगाड़ रहे हैं। 199 या 299 रुपए के छोटे प्लान शुरुआत में बड़े नहीं लगते, लेकिन बैंक खाते से हर महीने ऑटो-डेबिट होने पर घरेलू बजट को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन, एक परिवार अगर ओटीटी वीडियो (₹199 और ₹299), म्यूजिक (₹149) और अन्य एप (₹499) के प्लान लेता है, तो महीने का कुल खर्च ₹1,146 यानी सालाना ₹13,752 हो जाता है। इसमें कुछ और छोटे प्लान जुड़ते ही सालाना बिल आसानी से ₹20,000 पार कर जाता है।

बड़ी समस्या इन सर्विसेज का कम इस्तेमाल है। हर महीने पैसे कटने पर कम इस्तेमाल होने वाली सर्विस का वास्तविक खर्च दोगुना पड़ता है। सालाना प्लान का पेमेंट क्रेडिट कार्ड बिल में छिप जाता है। इनका फ्री ट्रायल लेते ही ऑटो-डेबिट लिंक हो जाता है, जिसे रद्द न करने पर ऑटो रिन्यूअल शुरू हो जाता है। समय के साथ दाम बढ़ने और बिना अनुमति पैसे कटने से यह अनजाना खर्च बोझ बन जाता है।

स्मार्ट स्टेप्स

इन दो तरीकों से अनजाने खर्चों पर लगाम लगाएं

तीन महीने का बैंक स्टेटमेंट जांचें... पिछले तीन महीने के बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करके ऑनलाइन खर्चों की लिस्ट बनाएं। बिना इस्तेमाल वाली सर्विसेज तुरंत बंद करें। एक समय में एक ही सर्विस का सब्सक्रिप्शन रखें और जरूरत पूरी होने पर बदलकर दूसरी लें। इससे पेमेंट्स की संख्या नियंत्रित रहती है।

सतर्कता

बचत स्थिर है तो एप खर्च बढ़ाना गलत

सालाना डिस्काउंट देखकर लिया गया ₹1,999 का प्लान 3 महीनों के बाद इस्तेमाल न होना सीधा नुकसान है। इमरजेंसी फंड स्थिर रहने के बीच हर महीने ऑटो-डेबिट खर्च बढ़ना वित्तीय खतरा है। गैर-जरूरी सर्विसेज बंद करके सालाना हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं।

बिजनेस ब्रीफ

टाटा: विमान इंजन के लिए कनाडा की कंपनी से करार

नई दिल्ली| टाटा प्रोजेक्ट्स ने कनाडा की कंपनी एमडीएस एयरो से हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां भारत में विमानों के इंजन का टेस्टिंग सेंटर बनाएंगी। इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन और हाई-प्रेशर सिस्टम का काम देखेगी। वहीं कनाडाई कंपनी नई टेक्नोलॉजी और सपोर्ट मुहैया कराएगी। इससे भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। एमडीएस 27 से ज्यादा देशों में ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है।

डेयरी बिजनेस बढ़ाएगी ITC, दूध-दही पर नजर

कोलकाता| आईटीसी आशीर्वाद ब्रांड के जरिए पूर्वी भारत में डेयरी कारोबार बढ़ा रही है। इसके तहत कंपनी बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ब्रांडेड दूध व दही की बढ़ती मांग भुनाने में जुटी है। इसी रणनीति से आईटीसी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बन गई है। कंपनी प्रोजेक्ट गोमुख के तहत 40 हजार किसानों से सीधे दूध खरीद रही है। आईटीसी का लक्ष्य 5 वर्षों में आशीर्वाद ब्रांड की बिक्री 20 हजार करोड़ रुपए पहुंचाने का है।

सुजान ने खरीदे 2 फेमस अफ्रीकी सफारी कैंप

नई दिल्ली| भारतीय हॉस्पिटैलिटी कंपनी सुजान ने अफ्रीका के जाम्बिया में दो प्रसिद्ध सफारी कैंप खरीदे हैं। कंपनी ने छियावा सफारिस से छियावा कैंप और ओल्ड मोंडोरो का अधिग्रहण किया है। डील की रकम का खुलासा नहीं किया गया है। इस डील से कंपनी को अफ्रीका के बड़े वाइल्डलाइफ एरिया में सीधी एंट्री मिल गई है। भारत से बाहर सुजान का यह पहला बड़ा विस्तार है। कंपनी 4 साल में ग्लोबल पोर्टफोलियो दोगुना करेगी।

सेबी: स्टॉक एक्सचेंजों की सेल्फ लिस्टिंग पर विचार

मुंबई| बाजार नियामक सेबी स्टॉक एक्सचेंजों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की अनुमति देने के लिए कमेटी बना सकता है। नया नियम अमल में आने पर पहले से लिस्टेड एक्सचेंजों पर भी लागू होगा। सेबी लिस्टिंग से पहले हितों के टकराव से जुड़े नियमों की समीक्षा करेगा। एनएसई के चेयरमैन श्रीनिवास इंजेटी ने भी सेल्फ-लिस्टिंग पर पुनर्विचार की मांग की थी। इस खबर के बाद बीएसई के शेयर में 2% की गिरावट आई।

बाजार पस्त • सबसे ज्यादा 42% गिरावट इंफोसिस में, रिलायंस का मार्केट कैप सबसे अधिक घटा

36% बड़ी कंपनियों के शेयर अभी 52 हफ्तों की ऊंचाई से 20% नीचे, पर फंडामेंटल्स मजबूत

हिना ओझा | नई दिल्ली

शेयर बाजार की गिरावट में दिग्गज कंपनियां ज्यादा पिटी हैं। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 की 18 यानी 36% कंपनियों के शेयर 52 हफ्तों के ऊंचे स्तर से 20% से भी ज्यादा नीचे आ गए हैं। इनका मार्केट कैप ₹31.35 लाख करोड़ घट गया है।

निफ्टी 50 खुद इस साल 5 जनवरी के रिकॉर्ड स्तर 26,373 से टूटकर 22,780 पर आ गया है, यानी करीब 13.6% गिर चुका है। आमतौर पर किसी शेयर के 20% या इससे ज्यादा गिरने पर उसे बेयर ग्रिप (मंदी की पकड़) में माना जाता है। सबसे ज्यादा 42% गिरावट इंफोसिस में देखी गई, जबकि मार्केट कैप के मामले में सबसे बड़ी चोट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पड़ी है।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के मुताबिक, यह बड़ा वैल्यूएशन रीसेट है क्योंकि हाल के वर्षों में कई शेयर तेजी से चढ़कर सामान्य से ज्यादा वैल्यूएशन पर पहुंच गए थे। इस बीच मुनाफा वसूली, ग्लोबल यील्ड (विदेशी बॉन्ड पर कमाई) बढ़ने, महंगे कच्चे तेल और सेक्टर की अपनी दिक्कतों ने निफ्टी को 10 फीसदी से लेकर 12 फीसदी तक नीचे धकेला है।

सबसे ज्यादा गिरने वाले 10 में से 4 शेयर आईटी सेक्टर के, टीसीएस 38% टूट चुकी

कंपनी	52-W हाई	अभी भाव	गिरावट
इंफोसिस	1,728	1,000	42%
विप्रो	273	164	40%
टीसीएस	3,350	2,082	38%
आईटीसी	426	269	37%
टीएमपीवी	448	291	35%
एचडीएफसी लाइफ	789	531	33%
मारुति सुज़ुकी	17,370	12,065	31%
एसबीआई	1,780	1,258	29%
जियो फाइनैंशियल	317	227	28%
एचडीएफसी बैंक	1,021	736	28%

नोट: शेयरों की कीमत रुपए में

रिलायंस का मार्केट कैप 4.8 लाख करोड़ घटा, एचडीएफसी बैंक को भी बड़ा झटका

कंपनी	52-वीक हाई पर	अभी	घटा
रिलायंस इंडस्ट्रीज	21.4	16.6	4.8
एचडीएफसी बैंक	15.5	11.3	4.2
टीसीएस	11.7	7.5	4.1
इंफोसिस	6.9	4.0	2.8
एसबीआई	11.3	9.0	2.2
आईटीसी	5.3	3.4	2.0
मारुति सुज़ुकी	5.4	3.8	1.6
टीएमपीवी	2.6	1.1	1.6
हिंदुस्तान यूनिलीवर	6.1	4.6	1.5
विप्रो	2.8	1.6	1.2

नोट: आंकड़े लाख करोड़ रुपए में, स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई रिसर्च

टॉप-18 कंपनियों का मार्केट कैप इस साल अब तक 28% घट चुका

- निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल 18 कंपनियों का कुल मार्केट कैप 112.75 लाख करोड़ से घटकर 81.40 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी इस मामले में 27.8% गिरावट आई।
- कुल मार्केट कैप नुकसान का करीब 83% (25.94 लाख करोड़ रुपए) सिर्फ ऊपर की 10 कंपनियों ने झेला।
- अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस को 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का झटका लगा।
- इंफोसिस के मार्केट कैप में गिरावट निफ्टी की गिरावट की तुलना में करीब 3.4 गुना ज्यादा है।

अभी आईटी और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा गिरावट का दबाव झेल रहे

आईटी: मीणा के मुताबिक, एआई से पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैंटेनेंस की कमाई घटने का डर है। बोनांजा के रिसर्च के एनालिस्ट प्रथमेश कडिवाल का कहना है कि विदेशी ग्राहकों ने टेक खर्च टाला। इससे आईटी कंपनियों की कमाई घटी और शेयर गिरे।

बैंकिंग-फाइनेंस: बीमा कमीशन और खर्च के मामले में प्रस्तावित सुधारों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और फंडिंग लागत से मार्जिन घटा है। मीणा के मुताबिक, इंडेक्स में बैंकों का वेटेज ज्यादा होने से असर बढ़ जाता है।

भास्कर नॉलेज

52 हफ्तों के हाई का क्या मतलब है?

यह बीते एक साल में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये महंगे ही होते हैं।

वैल्यूएशन रीसेट क्या है?

ऐसा तब होता है, जब शेयर की कीमत कंपनी की कमाई के मुकाबले जरूरत से ज्यादा महंगा हो जाए और फिर गिरकर वाजिब स्तर पर आए। यह नए निवेशकों के लिए अच्छा होता है।

रिकवरी कब तक होगी?

कडिवाल के मुताबिक, ब्लूचिप कंपनियों की कमाई मजबूत, कर्ज कम और कैश फ्लो स्थिर है। इस लिहाज से गिरावट फंडामेंटल्स से ज्यादा सेंटीमेंट कमजोर होने का नतीजा है। मीणा का मानना है कि रिकवरी तब आएगी जब ग्लोबल यील्ड (बॉन्ड से कमाई) स्थिर हों, कच्चे तेल के दाम घटें और विदेशी निवेशक वापस खरीदारी करने लगें।

स्टारशिप ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरी; एक इंजन बंद , पर मिशन पूरा



टेक्सास | स्पेसएक्स के इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारशिप ने सोमवार को टेक्सास के स्टारबेस से पहली बार पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरी। यह इस्की 14वीं उड़ान थी। उड़ान के दौरान एक इंजन बंद हो गया, फिर भी मिशन जारी रहा। स्टारशिप ने अगली पीढ़ी के 26 स्टारलिंक वी3 उपग्रह तैनात किए। योजना 10 घंटे की थी, पर करीब तीन घंटे बाद उसे उत्तरी प्रशांत महासागर में उतारा गया। हालांकि लैंडिंग बहुत स्मूद नहीं रही, लेकिन यह नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए अहम है।

राहत • ब्रांड प्रमोशन की बड़ी सहूलियत मिली

म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में नजर आएंगे सेलिब्रिटी, सेबी ने दी मंजूरी

भास्कर न्यूज | मुंबई

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के विज्ञापनों में अब निवेशकों को पसंदीदा सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए नए 'एडवरटाइजमेंट कोड' को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ब्रांड के प्रचार के लिए सेलिब्रिटीज को साइन कर सकेंगी। नए नियम शेयर ब्रोकर, निवेश सलाहकारों और पोर्टफोलियो मैनेजरों पर भी लागू होंगे। कंपनियों को हर विज्ञापन के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। बस विज्ञापन जारी करने के 3 दिनों के भीतर इसकी जानकारी सेबी को देनी होगी। इससे कंपनियों को लिए प्रचार आसान होगा, हालांकि नियमों के सही पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं की रहेगी।

रेटिंग-रैंकिंग • रिस्क और रिटर्न का हो सकेगा प्रचार

कंपनियां अब रेटिंग एजेंसियों से मिली अपनी रैंकिंग और परफॉर्मेंस का भी विज्ञापन कर सकेंगी। इससे निवेशकों को सही और जांची-परखी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। हालांकि, इसके लिए तय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

स्पष्टीकरण • आम सूचनाएं विज्ञापन नहीं मानी जाएंगी

सेबी ने साफ किया है कि कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली हर जानकारी को विज्ञापन नहीं माना जाएगा। नए नियमों में सर्विसेज से जुड़ी रोजमर्रा की जानकारियों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है, ताकि निवेशकों को जरूरी सूचनाएं बिना रोक-टोक मिलती रहें।

सबसे बड़ा बायबैक प्लान

एनवीडिया रिकॉर्ड 14 लाख करोड़ का बायबैक करेगी

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

एआई चिप कंपनी एनवीडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बायबैक प्लान पेश किया है। कंपनी 150 अरब डॉलर (₹14.4 लाख करोड़) मूल्य के खुद के शेयर खरीदेगी। इस ऐलान से कंपनी का कुल बायबैक बढ़कर 235 अरब डॉलर (22.5 लाख करोड़) हो गया है, जो पहले 85 अरब डॉलर (₹8.2 लाख करोड़) था।



इसके साथ ही एनवीडिया ने एप्रल के 2024 के 110 अरब डॉलर (मौजूदा भाव से ₹10.6 लाख करोड़) के रिकॉर्ड बायबैक को पीछे छोड़ दिया है। एआई चिप्स की भारी मांग के कारण एनवीडिया की कमाई लगातार बढ़ रही है। जुलाई तिमाही के अंत में कंपनी के पास 2.15 लाख करोड़ का कैश था। 2028 तक आय 70% बढ़ने का अनुमान है।

टाटा ग्रुप • होल्डिंग कंपनी को लिस्टिंग से बचाने की नई कवायद

टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड को दिया टाटा संस में दो कंपनियों को मिलाने का प्रस्ताव

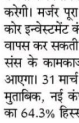
बिजनेस संवाददाता | मुंबई

टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने दो कंपनियों को इसमें मिलाने का प्रस्ताव दिया है।

ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में मर्ज करने को कहा है। इससे टाटा संस का कारोबारी ढांचा बदल जाएगा और कंपनी के प्राइवेट बने रहने का रास्ता खुल सकता है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के बोर्ड से इस प्रस्ताव पर विचार करने और आरबीआई से पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने को कहा है। टाटा संस में 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि नए ढांचे में कंपनी एनबीएफसी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के नियामकीय मानदंड पूरे नहीं करेगी। मर्जर पूरा होने पर टाटा संस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन वापस कर सकती है। इसके बाद टाटा संस के कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक, नई कंपनी की कुल आय का 64.3% हिस्सा सीधे कारोबार से आएगा और ऑपरेटिंग आय ₹1.05 लाख करोड़ होगी। इसके मुकाबले वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली आय ₹40,072 करोड़ ही रहेगी। साथ ही, नई कंपनी की कुल संपत्ति करीब ₹2 लाख करोड़ होगी, जिसमें समूह की कंपनियों में ₹1.77 लाख करोड़ का निवेश शामिल होगा।

...उधर आरबीआई को टाटा संस के जवाब का इंतजार

आरबीआई को टाटा संस की लिस्टिंग के औपचारिक जवाब का इंतजार है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, टाटा संस का बोर्ड आरबीआई को भेजे जाने वाले जवाब को जल्द अंतिम रूप देगा, जिसमें लिस्टिंग की समय-सीमा शामिल होगी। दरअसल, टाटा संस का एसेट साइज ₹2.01 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो आरबीआई की तय ₹1 लाख करोड़ की सीमा से अधिक है। इसलिए टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्ट होना होगा। कंपनी ने पहले डी-रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी थी, जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया।



सितंबर में तीसरा सेटलमेंट

अब अदाणी ग्रुप ने निपटाया पब्लिक शेयरहोल्डिंग केस

भास्कर न्यूज | मुंबई

अदाणी समूह की चार कंपनियों, चेयरमैन गौतम अदाणी और 13 अन्य ने बाजार नियामक सेबी के साथ एक और मामला निपटा लिया है। न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े इस मामले में उन्होंने कुल 1.48 करोड़ रुपए का निपटान शुल्क चुकाया। इस महीने समूह से जुड़ा यह तीसरा सेटलमेंट ऑर्डर है। सेबी ने सितंबर 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मामले में अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस शामिल थीं। कंपनियों ने आरोपों को न मानते हुए और न नकारते हुए सेटलमेंट अर्जी दी थी। रकम अगस्त 2026 में जमा हुई, जिसके बाद कार्यवाही बंद कर दी गई।



ग्रोथ • 5 साल में 5 करोड़ वर्ग फीट रिटेल स्पेस जुड़ेंगे

2031 तक भारत में 56% नए शॉपिंग मॉल बड़े साइज के होंगे: जेएलएल

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश में अगले 5 साल में बनने वाले शॉपिंग मॉल में बड़े साइज (लार्ज-फॉर्मेट) का दबदबा रहेगा। 2031 तक बाजार में आने वाली नई सप्लाई में 56% हिस्सेदारी बड़े साइज वाले मॉल्स की होगी।

जेएलएल की रिपोर्ट के मुताबिक, डेवलपर्स अगले 5 साल में 5.11 करोड़ वर्ग फीट नया रिटेल स्पेस जोड़ेंगे। इससे 7 बड़े शहरों का कुल मॉल स्पेस 9.21 करोड़ से बढ़कर 14.32 करोड़ वर्ग फीट पहुंचेगा। नई सप्लाई में बड़े मॉल्स का हिस्सा 2.87 करोड़ वर्ग फीट रहेगा। इसमें से 30-35% जगह मनोरंजन, खाने-पीने

छोटे शॉपिंग मॉल की बाजार 15% हिस्सेदारी रह जाएगी

अगले 5 साल में रिहायशी इलाकों के पास छोटे शॉपिंग मॉल (नेबरहुड मॉल) भी तेजी से उभरेंगे। नई सप्लाई में इनकी हिस्सेदारी 15% यानी 79 लाख वर्ग फीट रहेगी। डेवलपर्स अब रिहायशी इलाकों में खरीदारों को बेहतर अनुभव दे रहे हैं, ताकि मेन मार्केट के ट्रैफिक और पार्किंग की झंझटों से राहत मिले।

और सेवाओं के लिए होगी। 2026 की पहली छमाही में 63 लाख वर्ग फीट मॉल स्पेस किराए पर लिया गया। इस दौरान खाली जगह 11.2% रही।

बिजनेस एंकर निफ्ट ने 26 हजार से ज्यादा लोगों की माप ली, इससे 27 साइज चार्ट बने, 14 पुरुषों के, 13 महिलाओं के

कहीं 32 फिट, कहीं 34 भी टाइट; अब भारतीयों के हिसाब से बदलेगा कपड़ों का साइज

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दुकान या स्टोर पर ग्राहक से अमूमन एक सवाल जरूर किया जाता है- आपका साइज क्या है? और जवाब अक्सर अटक जाता है। एक ब्रांड में 32 नंबर की पैंट फिट आती है, तो दूसरे में 34 भी तंग निकलती है। अब सरकार यह उलझन खत्म करने के लिए भारतीयों के शरीर के हिसाब से खुद का साइज सिस्टम ला रही है।

फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'दिक्कत की जड़ यह है कि भारत में आज तक भारतीयों के शरीर की कोई वैज्ञानिक नापजोख थी ही नहीं।' नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की डीन (एकेडमिक्स) नूपुर आनंद के मुताबिक, भारत में अब तक सभी ब्रांड्स अमेरिका और ब्रिटेन के साइज चार्ट उधार लेते रहे। फिर बिक्री, शिकायतों और रिटर्न देखकर उनमें सुधार करते रहे। कमर तंग





अब 'आईएन' फ्रेमवर्क, इसमें महिलाओं के स्लिम, रेगुलर और कर्वी साइज; पुरुषों के लिए स्लिम, रेगुलर, एथलेटिक

पहलू	अभी	प्रस्तावित लेबल
साइज बेस	अंदाज और तजुर्बा	उठी बॉडी स्कैन से माप डेटा
लेबल	S-M-L या 32, 40 जैसे नंबर	आईएन + ऊंचाई + शेप + माप
महिला साइज	यूएस 6=यूके 10, सटीक माप नहीं	बस 85 श्रेमी
शेप	तय नहीं	महिला: स्लिम, रेगुलर, कर्वी; पुरुष: स्लिम, रेगुलर, एथलेटिक
ऊंचाई	अलग से नहीं	टॉल, एवरेज, शॉर्ट

निकली, तो अगली खेप थोड़ी बड़ी बना दी गई। यही ट्रेंड चलता रहा है।

अब कपड़ा मंत्रालय के तहत निफ्ट ने 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 26 हजार से ज्यादा लोगों की माप ली। इससे 27 साइज चार्ट बने, 14 पुरुषों के और 13 महिलाओं के। कपड़ों पर 'आईएन' (इंडिया) टैग लगाकर ऐसा सिस्टम बनाने की तैयारी है, जो दुनिया में भी चल सके। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, फ्रेमवर्क तय हो चुका है और अब स्वीकार्य अंतर तय हो रहे हैं। बदलाव की जरूरत इसलिए भी बढ़ी कि ढीले कुर्ते और साड़ी का दौर पीछे छूट रहा है और फिटिंग वाले कपड़े चलन में हैं। आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के वाइस प्रेसिडेंट नीरज गौर के मुताबिक, एक फिट देश की सिर्फ 15-20% आबादी को ही ठीक आ सकता है। ज्यादातर ब्रांड्स में 30% से ज्यादा सामान वापस आता है, जिसकी बड़ी वजह साइज है। साफ पैमाना होने पर रिटर्न घट सकते हैं।

रास्ता आसान नहीं है। कंसल्टेंसी फर्म कियर्नी के पार्टनर अंकुर सिंह इसे फिट की गारंटी नहीं, बल्कि साझा भाषा मानते हैं। ब्रिटेन में 2001 से 2004 के बीच 16 रिटेलर्स ने मिलकर साइज डेटाबेस बनवाया, फिर भी सबने अपनी-अपनी ग्रेडिंग चलाई। अमेरिका में 1941 की बड़ी स्टडी के बाद इंडस्ट्री आसान ग्रिड पर लौट गई। सबक साफ है- डेटा तभी मानक बनता है, जब पूरी इंडस्ट्री उसे अपनाए।

अब बदलाव के इस दौर में असली इम्तिहान छोटे कारोबारियों का है। पैटर्न दोबारा बनाना और सप्लायर बदलना महंगा सौदा है। आम बाजार के काम आने वाले ज्यादातर चार्ट मुफ्त हैं, बाकी हर चार्ट के ₹20,000 लगेंगे। घाटकोपर के एक कपड़ा दुकानदार कहते हैं कि सप्लायर सब न मानें, तो उलझन बनी रहेगी।

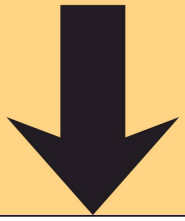
Last Day To Join Private Channel.
Closing entry for new members Now.

♦ **Indian Newspaper**
1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
And more Newspapers

♦ **InternationalNewspapers channel**
[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**
National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**
[National + InternationalEditorials]



Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees 📍

Trust me... this will be your best purchase of 2026